

श्रीमती सरोजिनी रामास्वामी

बनाम

भारत का संघ और ए. एन. आर.

अगस्त 27, 1992

[जे. एस. वर्मा, एन. एम. कासलीवाल, के. रामास्वामी, के. जयचंद्र रेड्डी और एस. सी. अग्रवाल,
जे. जे.]

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968: धारा 3 (2), 4 (1), (2) (3) और 6 (1) (2) (3)।

न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969: नियम 6,8,9,10,11।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश-कथित दुर्व्यवहार, वित्तीय कदाचार और अनियमितताएं संबंधित अध्यक्ष न्यायाधीश को प्रस्तुत करने की जांच समिति की रिपोर्ट कि क्या वह संबंधित अध्यक्ष न्यायाधीश को प्रस्तुत करने से पहले रिपोर्ट की प्रति का हकदार है-क्या संसद के समक्ष सुनवाई के अवसर का हकदार है-जांच समिति की रिपोर्ट-'दोषी नहीं' का पता लगाना-'दोषी पाए जाने का प्रभाव-क्या न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है-जांच समिति की रिपोर्ट की तुलना धारा 197 Cr.P.C के तहत दी गई मंजूरी से की जा सकती है।-जांच समिति का कार्यकाल-क्या अदालत द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 121,124 (4) (5)।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश-हटाने की प्रक्रिया-हटाने का आदेश पारित राष्ट्रपति द्वारा-न्यायिक समीक्षा कि क्या बाहर रखा गया है।

अनुच्छेद 136-न्यायाधिकरण-जांच समिति क्या है यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत गठित-क्या न्यायाधिकरण।

न्यायिक समीक्षा की प्रकृति और दायरा।

प्रशासनिक कानून-प्राकृतिक न्याय-तथ्यों पर निर्भर करता है प्रत्येक मामले में-उल्लंघन की अलग से जांच नहीं की जा सकती है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 197।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत गठित जांच समिति की रिपोर्ट, 1968 - क्या इसे धारा 197 Cr.P.C के तहत दी गई मंजूरी के बराबर माना जा सकता है।

वित्तीय अनियमितताओं और अनियमितताओं के कुछ आरोप थे न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 (2) के संदर्भ में एक प्रतिष्ठित न्यायविद के रूप में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

और इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश। हालांकि, नौवीं लोकसभा के भंग होने पर, केंद्र सरकार ने लोकसभा के निर्णय के समर्थन में कार्य करने से परहेज किया। अध्यक्ष का विचार था कि प्रस्ताव की सूचना के साथ-साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने और अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक जांच समिति का गठन करने का अध्यक्ष का निर्णय लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया था। "न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति" नामक एक निकाय प्रतिनिधि इस न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इसके संयोजक के रूप में भेजे गए और सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत संघ को निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वह जांच समिति को अधिनियम के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए। अपने निर्णय द्वारा, न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति v. भारत संघ और अन्य।, [1991] 4 एस. सी. सी. 699, बहुमत ने अभिनिर्धारित किया कि (i) अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत एक प्रस्ताव सदन के विघटन पर समाप्त नहीं होता है; (ii) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में दो चरण शामिल हैं। पहला चरण न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार जांच और सबूत का है जो संविधान के अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित किया गया है और दूसरा चरण दुर्व्यवहार के आरोपों के साबित होने के बाद शुरू होता है। दूसरे चरण में जब प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर अनुच्छेद 121 के तहत प्रतिबंध हटा दिया जाता है।

और अनुच्छेद 124 (4) के तहत परिकल्पित प्रक्रिया आकर्षित होती है। पहला चरण न्यायिक समीक्षा के अधीन है, लेकिन दूसरा चरण न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, जिसमें संसदीय प्रक्रिया शामिल है।

संविधान पीठ के फैसलों के बाद, अधिनियम के तहत अध्यक्ष द्वारा गठित समिति न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए आगे बढ़ी। 10 मई, 1992 को विद्वान न्यायाधीश }

समिति के पीठासीन अधिकारी को एक पत्र संबोधित करते हुए उनसे अध्यक्ष को भेजे जाने से पहले अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया। उनसे अनुरोध किया कि वे अध्ययन के लिए उचित समय देकर और उस पर उचित कार्रवाई करके रिपोर्ट को रोक दें। जांच समिति ने जवाब दिया कि चूंकि उच्चतम न्यायालय ने संबंधित मामले में मामले को अपने हाथ में ले लिया है (1992 का रिट याचिकाकर्ता 149) इसलिए समिति न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करेगी। इसके बाद पत्नी ने न्यायाधीश ने इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की-जिसे मूल रूप से न्यायाधीश द्वारा स्वयं समिति को न्यायाधीश को समिति की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने के निर्देश के लिए दायर किया गया था और साथ ही साथ

याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि (i) न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति के मामले में निर्णय के तार्किक परिणाम के रूप में, न्यायाधीश अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले समिति की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने का हकदार है; (ii) एक बार जब प्रक्रिया का संसदीय भाग शुरू हो जाता है और अध्यक्ष न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करने के साथ सदन में प्रस्ताव पेश करता है, तो न्यायाधीश

प्रक्रिया के वैधानिक भाग की न्यायिक समीक्षा की मांग करने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जाएगा, भले ही यह इसके लिए आधार हो

समिति के निष्कर्षों की वैधता का परीक्षण करने के लिए न्यायिक समीक्षा या तो अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर संसदीय प्रक्रिया शुरू होने से पहले 'अभी' उपलब्ध है या कभी नहीं; (iii) न्यायाधीश को प्रस्तुत करने से पहले रिपोर्ट की आपूर्ति न करना।

माननीय अध्यक्ष न केवल न्यायाधीश के संवैधानिक अधिकार को पराजित करेंगे, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करेंगे; (iv) अनुच्छेद 124 (4) के तहत राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने का आदेश न्यायिक समीक्षा से मुक्त होने के कारण, न्यायाधीश को प्रक्रिया के संसदीय भाग के प्रारंभ से पहले न्यायिक समीक्षा की मांग करने का अवसर होना चाहिए, जिसके लिए उन्हें अध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए।

और (v) कि जांच समिति संविधान के अनुच्छेद 136 के प्रयोजनों के लिए एक न्यायाधिकरण है और चूंकि उक्त समिति के निष्कर्षों के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की जाएगी, इसलिए समिति की रिपोर्ट संबंधित न्यायाधीश को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

जाँच समिति की ओर से यह तर्क दिया गया था कि (i) जाँच पूरी होने पर 111 में निष्कर्षों की रिकॉर्डिंग में समाप्त होती है।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

रिपोर्ट, संवैधानिक प्राधिकरणों के बीच सौहार्द का सिद्धांत यह कहता है कि अदालतों को रिपोर्ट में निष्कर्ष दर्ज होने के बाद अधिनियम द्वारा विचार की गई प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए; (ii) न्यायाधीश प्रतिकूल निष्कर्ष पर हमला करने के लिए संसदीय प्रक्रिया के दौरान अवसर का हकदार है। और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि संसद ऐसा अवसर नहीं देगी या प्रस्ताव पर मतदान करने से पहले न्यायाधीश द्वारा उठाए गए निष्कर्षों पर आपत्तियों पर उचित रूप से विचार नहीं करेगी; और (iii) हटाने के आदेश की न्यायिक समीक्षा को बाहर नहीं किया जा सकता है।

महान्यायवादी ने तर्क दिया (i) कि समिति में है

अध्यक्ष के अधीनस्थ प्राधिकारी की प्रकृति। यह रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 के तहत एक लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने जैसी है। जब तक मंजूरी की वैधता पर शुरुआती चरण में सवाल नहीं उठाया जाता है, तब तक आरोपी को बाद के चरण में उस पर हमला करने से रोक दिया जाता है। इसी सादृश्य पर विद्वान न्यायाधीश समिति द्वारा रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल निष्कर्षों, यदि कोई हों, को संसद द्वारा विचार के लिए लिए जाने से पहले चुनौती देने का हकदार है। यह तभी किया जा सकता है जब ऐसी रिपोर्ट न्यायिक समीक्षा की मांग के लिए विद्वान न्यायाधीश को उपलब्ध कराई

जाए; (ii) हटाने की संसदीय प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, संसद के प्रत्येक सदन में कोई प्रस्ताव रखे जाने से पहले, विद्वान न्यायाधीश को रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने और उसकी न्यायिक समीक्षा की मांग करने का अधिकार है; और (iii) अनुच्छेद 124 (4) के तहत राष्ट्रपति द्वारा हटाए गए आदेश को चुनौती देने का विद्वान न्यायाधीश का अधिकार संदेहपूर्ण होने के कारण, यह उचित है कि प्रतिकूल निष्कर्ष, यदि कोई हो, के मामले में न्यायिक समीक्षा की मांग करने के अपने अधिकार को विफल करने से बचने के लिए, विद्वान न्यायाधीश को अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत अध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले इस स्तर पर समिति की रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।

याचिका का निपटारा करते हुए, यह न्यायालय,

पकड़ना: (जे वर्मा के अनुसार, अपने और के. जे. रेड्डी और एस. सी. अग्रवाल के लिए,

जे. जे)

1. यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय का एकमात्र तार्किक परिणाम

न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति यह है कि संबंधित न्यायाधीश को संसदीय प्रक्रिया शुरू करने से पहले जांच समिति की रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है ताकि वह न्यायिक समीक्षा के उपाय का लाभ उठा सके यदि समिति ने विद्वान न्यायाधीश के खिलाफ 'दोषी' का निष्कर्ष दर्ज किया है।

[190 बी-सी] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

112

1.1 . समिति में अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने से पहले संबंधित न्यायाधीश को प्रस्तुत करने का कोई दायित्व नहीं है।

अध्यक्ष/अध्यक्ष अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति में घोषित कानून के अनुरूप है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया वैधानिक है क्योंकि अध्यक्ष द्वारा संसद के समक्ष रिपोर्ट को समिति द्वारा अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) और (3) के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। [148 - एफ]

उप-न्यायिक जवाबदेही समिति v. भारत संघ और ओआरएस। , [1991] 4 एस. सी. सी. 699, संदर्भित।

1.2 . यदि अध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले समिति द्वारा न्यायाधीश को रिपोर्ट की एक प्रति की आपूर्ति पर विचार किया गया था

अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून अधिनियम की धारा 4 और उसके तहत बनाए गए नियम 9 में प्रतियों की संख्या सहित अपने तरीके के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत रूप से प्रावधान करते हुए कानून में बनाए गए प्रावधानों में उस क्षेत्र को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। इस कानून में इस तरह के प्रावधान का अभाव एक जानबूझकर है और उस आवश्यकता के अभाव पर जोर देने के लिए एक अनजाने में चूक नहीं है जो संवैधानिक राष्ट्रीय योजना से भी मेल खाती है। [169 डी-ई]

2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रत्येक न्यायाधीश को उनकी नियुक्ति पर उनके कार्यकाल के दौरान पद से हटाया नहीं जा सकता है, सिवाय इसके कि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) में प्रदान की गई विधि। संसद द्वारा अनुच्छेद 124 (5) के तहत बनाए गए कानून, अर्थात् न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और उसके तहत बनाए गए न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 को अनुच्छेद 124 (4) के साथ पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत में किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई गई संवैधानिक योजना क्या है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 124 (5) के तहत इस तरह से अधिनियमित कानून में यह प्रावधान है कि किसी मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ लगाया गया कोई भी आरोप

उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत केवल अधिनियम में निर्दिष्ट संसद सदस्यों की न्यूनतम संख्या से कम नहीं होनी चाहिए, अन्य सभी तरीकों को बाहर रखा गया है। निर्धारित तरीके से प्रक्रिया शुरू करने पर, अध्यक्ष/अध्यक्ष को यह तय करना होता है कि क्या ए. सी. क्यू. सेशन की जांच की आवश्यकता है। यदि वह संसद के निर्दिष्ट न्यूनतम सदस्य द्वारा प्रस्ताव के रूप में लगाए गए आरोप पर कार्रवाई नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर, यदि अध्यक्ष/सभापति, उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने और ऐसे व्यक्तियों से परामर्श करने के बाद, जो वह उचित समझते हैं, यह राय बनाते हैं कि प्रथम दृष्टया 113

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

न्यायाधीश के खिलाफ आरोप की जांच के लिए मामला बनता है, वह अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार न्यायिक अधिकारियों की एक समिति का गठन करता है। [188 ई-एच, 189-ए]

3. नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 6 में सन्निहित योजना है -

कि जहां जांच समिति का निष्कर्ष 'दोषी नहीं' है, चाहे वह सर्वसम्मत हो या जांच समिति के सदस्यों के बहुमत द्वारा, न्यायाधीश को हटाने की पूरी प्रक्रिया उस निष्कर्ष के साथ समाप्त हो जाती है जो न्यायाधीश द्वारा दुर्व्यवहार के आरोप को शांत करता है और सभी अफवाहों को खारिज कर देता है और प्रस्ताव को संसद द्वारा विचार के लिए लेने की भी आवश्यकता नहीं है ताकि प्रक्रिया का संसदीय भाग पूर्ववर्ती निष्कर्ष की शर्त के अभाव में शुरू न हो।

एक स्थिति, जब 'दोषी नहीं' का निष्कर्ष अधिकांश सदस्यों द्वारा दिया जाता है केवल, तीसरे सदस्य द्वारा दोषी होने का विपरीत निष्कर्ष भी नहीं है

संसद के उन सदस्यों सहित जिन्होंने प्रस्ताव की सूचना दी हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिनियम की धारा 3 (1) में कोई अधिकार है

उस स्थिति की जांच करना भी 'दोषी नहीं' के निष्कर्ष पर बहुत कम हमला करता है

जाँच समिति द्वारा बहुमत से भी अभिलिखित किया गया। नियमों के नियम 9 (6) के साथ पठित अधिनियम की धारा 6 (1) इस दिशा में एक स्पष्ट संकेत है।

[146 ई-एच, 148 ए-बी]

3.1 . अधिनियम और नियमों के प्रावधान एक मजबूत संकेत हैं

कि तदनुसार न्यायाधीश को हटाने के लिए संवैधानिक योजना

संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) के साथ और अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित समान दायित्व कानून न्यायिक समीक्षा द्वारा भी सभी जांच को बंद कर देता है जहां जांच समिति सर्वसम्मति से या यहां तक कि

जाहिर है, संबंधित न्यायाधीश 'नहीं' के निष्कर्ष से व्यथित नहीं हो सकता है। उसके पक्ष में दोषी और यदि ऐसा निष्कर्ष सर्वसम्मति नहीं है, लेकिन

बहुमत, दोषी की असहमत राय का गैर-प्रकटीकरण, जैसा कि आवश्यक है

नियमों के नियम 9 (6), यहां तक कि संसद के लिए भी, किसी भी संभावित प्रतिबंध को रोकता है।

असहमति से संबंधित न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को नुकसान राय और, इसलिए, उससे कोई वैध शिकायत नहीं हो सकती है

अज्ञात असहमत राय। इस कारण से, संबंधित न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] प्रस्तुत करता है।

1 एस सी आर।

114

उस स्थिति में न्यायिक समीक्षा के बहिष्कार के खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती है। 'दोषी नहीं' के निष्कर्ष वाली समिति की रिपोर्ट की स्थिति में ऐसी स्थिति होने के कारण, कम से कम उस स्थिति में समिति के लिए अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत अध्यक्ष/अध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले संबंधित

न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। [147 एफ-एच, 148-डी]

3.2 . यदि न्यायाधीश के खिलाफ कई आरोप बनाए गए हैं और

उनमें से कुछ के संबंध में निष्कर्ष यह है कि न्यायाधीश 'दोषी' है जबकि अन्य आरोपों पर निष्कर्ष यह है कि न्यायाधीश 'दोषी नहीं' है, तो प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष के संबंध में जो परिणाम सामने आएंगे, वे उसकी प्रकृति पर निर्भर करेंगे। दूसरे शब्दों में, जिस आरोप के संबंध में न्यायाधीश को 'दोषी नहीं' पाया जाता है, उसके परिणाम अधिनियम की धारा 6 (1) और नियमों के नियम 9 (6) के अनुसार होंगे और उन आरोपों से संबंधित हटाने की प्रक्रिया इस तरह से समाप्त हो जाएगी

किसी न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों के संबंध में 'दोषी नहीं' के निष्कर्ष के मामले में किसी भी आगे की जांच या न्यायिक समीक्षा के अधीन हुए बिना संकेत दिया गया। [149 बी-डी]

4. जब समिति की रिपोर्ट में निष्कर्ष यह है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार के लिए 'दोषी' है, तो अधिनियम की धारा 6 (2) में आदेश दिया गया है कि न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। सदन द्वारा प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट के साथ

धारा 4 (2) के अनुसार और अधिनियम की धारा 4 (3) के तहत इसके समक्ष रखा गया है। निष्कर्ष की शुद्धता सहित गुणों पर पूर्ण विचार' संसद के समक्ष सामग्री के आधार पर जांच समिति द्वारा किए गए 'दोषी' पर संसदीय भाग के दौरान विचार किया जाता है

4.1 . ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत में अपनाई गई संवैधानिक योजना में संबंधित न्यायाधीश को अवसर नहीं दिया जाना चाहिए जब - संसद न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत गठित समिति द्वारा 'दोषी' पाए जाने पर उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर विचार करती है। इस तरह का अवसर निष्पक्षता की आवश्यकता के अनुरूप है और नागरिक परिणामों वाले किसी भी निर्णय के लिए प्रक्रिया की एक आवश्यक विशेषता है। संबंधित न्यायाधीश को इस तरह का अवसर देने के तरीके का सटीक विवरण अध्यक्ष/सभापति और संसद को तय करना हो सकता है, लेकिन हमारी संवैधानिक योजना में स्पष्ट जनादेश है कि प्रक्रिया को अपनाया गया

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

इस उद्देश्य के लिए ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समिति की रिपोर्ट में किए गए 'दोषी' के निष्कर्ष पर संबंधित न्यायाधीश के दृष्टिकोण और टिप्पणियों, यदि कोई हो, की संसद के प्रत्येक सदन को उपलब्धता सुनिश्चित करे, ऐसी प्रक्रिया जो संबंधित न्यायाधीश के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करती हो और संबंधित न्यायाधीश के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करती हो।

विद्वान न्यायाधीश द्वारा धारण किए गए उच्च पद की गरिमा। [162 एफ-जी, 160 ए-बी]

4.2 . इसलिए, यह संवैधानिक योजना में निहित है

अनुच्छेद 124 (4) और अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून में किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है कि जब संसद जांच समिति की रिपोर्ट और उसे उपलब्ध कराई गई अन्य प्रासंगिक सामग्रियों के साथ विचार के लिए न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लेती है तो जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए गए उसके खिलाफ 'दोषी' के निष्कर्ष पर संबंधित न्यायाधीश के दृष्टिकोण और टिप्पणियों, यदि कोई हो, का लाभ संसद को भी मिलना चाहिए। इस अभ्यास के निष्पादन को सक्षम बनाने के लिए और संसद को इस स्तर पर रिपोर्ट में किए गए 'दोषी' के निष्कर्ष के खिलाफ कारण दिखाने के संबंधित न्यायाधीश के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए, अध्यक्ष/अध्यक्ष का यह स्पष्ट दायित्व है कि वह संबंधित न्यायाधीश को जांच समिति की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करे, जबकि इसे धारा 4 (2) के तहत संसद के समक्ष धारा 4 (3) के तहत जितनी जल्दी हो सके रखा जाए। इस दृष्टिकोण में प्रोविड का लाभ भी है।

संबंधित न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के संसदीय भाग के दौरान अपना दृष्टिकोण रखने और उसके खिलाफ 'दोषी' पाए जाने पर, यदि कोई टिप्पणी है, तो उसे प्रस्तुत करने का अवसर देना, जिसके लिए प्रस्ताव पर मतदान करने से पहले संसद द्वारा विचार करने के लिए जांच समिति द्वारा किया गया था।

न्यायाधीश को हटाना। [158 एफ-एच, 159-ए]

4.3 . यदि संवैधानिक योजना, परिकल्पना करती है और एक

जांच समिति द्वारा अभिलिखित 'दोषी' के निष्कर्ष पर संबंधित न्यायाधीश को पद से हटाने के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर, जिसे संसद के समक्ष विचार के लिए रखा जा रहा है और संसद को 'दोषी' के निष्कर्ष को स्वीकार करने का निर्णय लेने से पहले इसे ध्यान में रखना आवश्यक है और संसद द्वारा हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करके उस पर कार्रवाई करना आवश्यक है।

हटाने की कार्यवाही को समाप्त करने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिए अपेक्षित बहुमत, यह इंगित करेगा कि योजना में कारण दिखाने का इस तरह का अवसर अंतिम निर्णय लेने के चरण से पहले दोष के अनुचित निष्कर्ष के खिलाफ है, जो केवल न्यायिक समीक्षा के अधीन होना आवश्यक है। स्पष्ट इरादा यह है कि ऐसी स्थिति में संसद को ही सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट (1992) के प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

1 एस सी आर।

उस स्तर पर न्यायिक समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिनियम की धारा 6 (3) के अनुसार दुर्व्यवहार को तभी साबित माना जाता है जब संसद प्रस्ताव को इस तरीके से स्वीकार करती है।

निर्धारित किया गया। [163 ए-डी]

संबंधित न्यायाधीश के लिए न्यायिक समीक्षा का उपाय केवल तभी उपलब्ध होता है जब उसके दुर्व्यवहार को कानून में 'साबित' माना जाता है, न कि जांच समिति द्वारा किए गए 'दोषी' के अनुचित निष्कर्ष के खिलाफ, जिस पर संसद द्वारा कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने का एक अन्य कारण यह है कि किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही को जनहित में जल्द से जल्द समाप्त करने की आवश्यकता होती है और इसलिए, जांच समिति द्वारा 'दोषी' के अनुचित निष्कर्ष के चरण में प्रक्रिया में कोई रोक लगाने पर विचार नहीं किया जाता है। संबंधित न्यायाधीश को उस स्तर पर 'दोषी' के उस अनुचित निष्कर्ष के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर भी उस स्तर पर न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता के बिना उसके हित की पूरी तरह से रक्षा करता है, समिति के दोषी पाए जाने की संसद की जांच की गुंजाइश बहुत व्यापक है। [163 डी-एफ]

4.4 . इसके विपरीत दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप एक गंभीर विसंगति होगी। अगर

'समिति द्वारा किए गए दोषी' का निष्कर्ष अपने आप में अनुच्छेद 124 (4) के उद्देश्य के लिए 'साबित दुर्व्यवहार' के बराबर है, अगर संसद हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है तो विसंगत स्थिति उत्पन्न होगी। इसके बाद। उस स्थिति में प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और 'साबित दुर्व्यवहार' के निष्कर्ष के बावजूद, न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता है। 'साबित दुर्व्यवहार' के निष्कर्ष के बावजूद हटाने की प्रक्रिया के अंत में ऐसी तीखी स्थिति पर योजना में कभी विचार नहीं किया जा सकता था और इसलिए, एक ऐसी संरचना जो उस बेटुकी बात का कारण बन सकती है, उसे त्याग दिया जाना चाहिए। [164 डी-ई]

4.5 . भले ही जांच समिति द्वारा किए गए 'दोषी' के निष्कर्ष की न्यायिक समीक्षा केवल संबंधित सीमित आधारों पर अनुमत हो सकती है।

वैधानिकता के लिए, फिर भी हटाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय संसद की शक्ति इतनी सीमित नहीं होगी क्योंकि संसद उनके अधीन है

समिति द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण सामग्री पर विचार करने पर 'दोषी' पाए जाने के बावजूद प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का अधिकार जो उसे उस सामग्री के संभाव्य मूल्य में भी जाने में सक्षम बनाता है जिस पर निष्कर्ष आधारित है और किसी दिए गए मामले में प्रस्ताव को स्वीकार करने की वांछनीयता का निर्णय करने में सक्षम बनाता है। संसद प्रस्ताव पर मतदान करके निर्णय लेती है और यदि वह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का विकल्प चुनती है तो उसे अपने निर्णय के लिए कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है। [163 जी-एच, 164-ए] 117

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

यह मानने का कोई कारण नहीं है कि संसद ऐसा नहीं करेगी।

किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में शामिल राज्य के किसी अन्य अंग या प्राधिकरण से जितनी अपेक्षा की जाती है, उतनी ही प्रतिक्रियाशीलता और गंभीरता के साथ संवैधानिक योजना में अपने दायित्व का निर्वहन करना। इस प्रक्रिया में संसद को सौंपी गई शक्ति की प्रकृति और विस्तार राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश देने के बाद तक न्यायिक समीक्षा के बहिष्करण को इंगित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है, यदि संसद आवश्यक बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार करती है। समिति द्वारा किया गया 'दोषी' का निष्कर्ष केवल संसद को अपनी प्रक्रिया शुरू करने और

उस निष्कर्ष पर कार्य करें जो अधिनियम की धारा 4 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चरण में, सबसे अच्छा, अस्थायी और अयोग्य है। [164 ए-सी]

4.6 . ऐसा होने पर, संबंधित के लिए न्यायिक समीक्षा का उपाय

न्यायाधीश को संसद द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने पर अपने 'साबित दुर्व्यवहार' के चरण तक पहुंचने के बाद ही होना चाहिए, जो अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निष्कासन के आदेश की ओर ले जाता है। संबंधित न्यायाधीश द्वारा समय के बीच न्यायिक समीक्षा का सहारा लें

समिति द्वारा जाँच का समापन और राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश देना समय से पहले होगा और संवैधानिक योजना में अनुचित है। यह निर्माण संबंधित न्यायाधीश के हितों की रक्षा करते हुए हटाने की प्रक्रिया में शामिल सभी उच्च गणमान्य व्यक्तियों की भूमिका को पूर्ण प्रभाव और उचित महत्व देता है, इस बात में संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि उनमें से प्रत्येक संवैधानिक योजना के तहत अपनी भूमिका और दायित्व की सीमा के महत्व के लिए पूरी तरह से जीवित होगा। हालाँकि, यदि कोई अवैधता तब भी होती है, तो प्रक्रिया के अंत में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान प्रक्रिया को बीच में बाधित किए बिना इसके सुधार की अनुमति देता है। [164 एफ-एच, 165-ए]

5. न्यायिक समीक्षा किसी कार्यवाही की वैधता निर्धारित करने और उपयुक्त राहत देने के लिए अदालतों की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग है और इस प्रकार

कानून के शासन को बनाए रखें। इस शक्ति के प्रयोग के लिए आगे किसी वैधानिक प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है जो भारत के संविधान द्वारा उच्च न्यायालयों को दी गई है। [173 - एफ]

5.1 . आधुनिक प्रवृत्ति कुछ स्थितियों में सीमित सीमाओं के भीतर न्यायिक समीक्षा को स्वीकार करना है, भले ही पूरी प्रक्रिया राजनीतिक हो क्योंकि 'राजनीतिक प्रश्न सिद्धांत' इस पाठ्यक्रम की अनुमति देता है। ऐसे मामलों में जहां पूरी प्रक्रिया राजनीतिक है, राजनीतिक प्रक्रिया के समापन पर उस हद तक न्यायिक समीक्षा पर संदेह नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] समर्थन करती है। 1 एस सी आर।

118

सैद्धांतिक रूप से कोई कारण नहीं है कि भारत में किसी न्यायाधीश को हटाने की पूरी प्रक्रिया के अंत में न्यायिक समीक्षा, जहां यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसका राजनीतिक प्रक्रिया केवल एक हिस्सा है, को राजनीतिक प्रक्रिया सहित पूरी प्रक्रिया के समापन के बाद बाहर रखा जा सकता है। [184 सी-ई]

एडम क्लेटन पॉवेल बनाम। जॉन डब्ल्यू. मैककॉर्मेक, 23 एल. एड. 2 डी। 491 : 395 यू. एस. 486, संदर्भित।

5.2 . केवल किसी कार्यवाई का संसदीय अनुमोदन या यहां तक कि किसी बाहरी प्राधिकरण द्वारा एक रिपोर्ट जब इस तरह के अनुमोदन के बिना, कार्यवाई या रिपोर्ट अपने आप में अप्रभावी है, तो अनुमेय आधारों पर न्यायिक समीक्षा को बाहर करने का प्रभाव नहीं पड़ता है। [173 - बी]5.3 . सिद्धांत या अधिकार में यह अनुमान लगाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि भारत में अपनाई गई संवैधानिक योजना में निष्कर्ष की न्यायिक समीक्षा की गई है।

के वैधानिक भाग के दौरान जांच समिति द्वारा दर्ज किए गए दोषी

प्रक्रिया की अनुमति नहीं है जब उस अस्थायी खोज को 'सिद्ध दुर्व्यवहार' में परिपक्व किया जाता है जो हटाने के क्रम में समाप्त होता है। तर्क

'अभी या कभी नहीं' का न्यायालय में अपील नहीं करता है और जो अधिक दिखाई देता है

संवैधानिक योजना में सुसंगत यह है कि अनुमतियों पर न्यायिक समीक्षा साइबल ग्राउंड्स अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन हटाने के आदेश के बाद प्रक्रिया के अंत में, यदि वह चरण पहुँच गया है। [170 डी-ई]

संविधान अनुमेय आधारों पर न्यायिक समीक्षा से मुक्त है - जाँच समिति द्वारा दोषी पाए जाने की वैधता की जाँच करना

हटाने के लिए वैधानिक प्रक्रिया के दौरान जो पूर्ववर्ती शर्त है

में समाप्त होने वाली संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत के लिए

के अधीन गठित जाँच समिति की रिपोर्ट में दोषी होने का न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 उपलब्ध आधारों पर अनुज्ञेय होगा।

अध्यक्ष द्वारा हटाने का आदेश दिए जाने के बाद न्यायिक जांच

संसद द्वारा हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के अनुसार

जाँच समिति की रिपोर्ट के आधार पर। [173 सी-जी]

5.5 . राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने के आदेश के परिणामस्वरूप आवश्यकता उत्पन्न होने की स्थिति में विद्वान न्यायाधीश को न्यायिक समीक्षा की उपलब्धता, व्यापक शक्तियों को देखते हुए ऐसा आदेश देने के बाद संदेह नहीं किया जा सकता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय से। [173 - ई] 119

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

5.6 . यह निष्कर्ष संबंधित के अधिकार की पर्याप्त रूप से रक्षा करता है।

न्यायाधीश, निर्धारित तरीके से शुरू होने के बाद प्रक्रिया के त्वरित समापन को सुनिश्चित करता है और इस दृष्टिकोण के साथ सहमत होता है कि यह योजना 'न्यायाधीशों को हटाने के लिए राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का एक विवेकपूर्ण मिश्रण है, यह विद्वान न्यायाधीश के अधिकार, हित और गरिमा का संरक्षण सुनिश्चित करता है और प्रक्रिया में शामिल सभी संस्थानों और कार्यकर्ताओं की गरिमा के अनुरूप है। इसमें व्यस्त निकायों द्वारा प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप को भी शामिल नहीं किया गया है जो इसमें भाग लेने के लिए संसद सदस्यों, अध्यक्ष/अध्यक्ष और संबंधित न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायिक अधिकारियों वाली जांच समिति तक सीमित हैं, अगर आरोप केवल निर्धारित तरीके से लगाए जाने की अनुमति दी जाती है तो न्यायाधीश के आचरण की जांच को उचित ठहराया जा सकता है। [170 ई-जी]

केशव सिंह, [1965] 1 एस. सी. आर. 413; उप-न्यायिक समिति

गणनाशीलता वी। भारत संघ और अन्य।, [1991] 4 एस. सी. सी. 699 एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, [1981] सप। एस. सी. सी. 87 राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ, [1978] 1 एस. सी. आर. 1 और भारत संघ और अन्र. वी. एलआरएस द्वारा रघुबीर सिंह (मृत)। आदि, [1989] 2 एस. सी. सी. 754, संदर्भित।

रेजिना वी। इंग्लैंड के लिए सीमा आयोग, (1983) 1 क्यू. बी. 600, सी. ए. ;

नॉटिंघमशायर कंट्री काउंसिल और पर्यावरण के लिए राज्य सचिव, ब्रैडफोर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का शहर और पर्यावरण के लिए राज्य सचिव, (1986) 1 ए. सी. 240; रेजिना बनाम। महामहिम का कोषागार, एक्स पार्टी स्मेडली, (1986) 1 क्यू. बी. 657, सी. ए. ; एडम क्लेटन पॉवेल बनाम जॉन डब्ल्यू. मैककॉर्मेक 23 एल.

एड। 2 डी। 491 ; सल्लेह अबास बनाम। अब्दुल हामिद, 1988 एल. आर. सी. 25; बेकर वी। कैर, 369 यू. एस. 186: 7 एल एड। 2 डी। 663 (1962) और पॉवेल वी। मैककॉर्मेक, 395 यूएस 486; 23 एल एड। 2 डी। 491 (1969) , संदर्भित किया गया।

हालस्टेड एल. रिटर बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, 84 सी. सी. एल. एस. 293 , प्रतिष्ठित।

एच. डब्ल्यू. आर. वेड, प्रशासनिक कानून, छठा संस्करण; रूल बर्जर, मैं

पैचमेंट: संवैधानिक समस्याएं (1973) विलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका का संवैधानिक कानून (1936), संदर्भित।

डेनियल ए. रेज़नेक, "क्या महाभियोग की न्यायिक समीक्षा आ रही है", 60

अमेरिकन बार एसोसिएशन जर्नल 681 (1974); मियाचेल जे. गेरहाड्ट, "महाभियोग की संवैधानिक सीमाएँ और इसके विकल्प" 68 टेक्सास लॉ रिव्यू, 1 (1989), का उल्लेख किया गया है।

6. उन विचारों में से एक जिसका न्यायालय ने 120 पर विचार किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

अनुच्छेद 136 के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण को न्यायाधिकरण के रूप में अभिनिर्धारित करना अंतिमता या निर्णायकता है और ऐसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारण की बाध्यकारी प्रकृति है। [166 - एच, 167-ए]

6.1 . समिति द्वारा निर्णय: अर्थात् न्यायाधीश 'दोषी नहीं' है।

दुर्व्यवहार, अकेले अंतिम है क्योंकि यह कार्यवाही को समाप्त कर देता है। हालाँकि, उस मामले में समिति द्वारा किए गए 'दोषी नहीं' के निष्कर्ष की न्यायिक समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। यह पहलू केवल इसी कारण से न्यायाधिकरण के चरित्र को नकारता है। दूसरी स्थिति में जब समिति का निर्णय यह है कि न्यायाधीश दुर्व्यवहार का 'दोषी' है, तो वह निष्कर्ष अनुचित है जिस पर संसद द्वारा कार्रवाई की जा सकती है या नहीं भी। समिति द्वारा किए गए 'दोषी' का निष्कर्ष संसद द्वारा स्वीकार किए जाने के अधीन होने के कारण अंतिम नहीं है और इसलिए निर्णायक नहीं है। यदि समिति को अनुच्छेद 136 के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में माना जाता है, तो यह कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करेगा और इसके परिणामस्वरूप यह भी होगा कि समिति को एक न्यायाधिकरण के रूप में माना जाएगा यदि यह पाता है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार के लिए दोषी नहीं है, लेकिन यदि यह पाता है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार के लिए दोषी है तो इसे न्यायाधिकरण के रूप में नहीं माना जाएगा। एक न्यायाधिकरण के रूप में समिति का चरित्र उन निष्कर्षों पर निर्भर नहीं कर सकता जो अंततः उसके द्वारा दर्ज किए जाते हैं।

[168 सी-एफ]

6.2 . वास्तव में, जांच समिति की रिपोर्ट जिसमें एक

यह निष्कर्ष निकालना कि न्यायाधीश दुर्व्यवहार का दोषी है, उसे हटाने के लिए पुनरीक्षण की प्रकृति का है, जिस पर संसद द्वारा एक वरिष्ठ न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय कार्रवाई की जा सकती है या नहीं, जो न्यायाधीश के निर्धारित कार्यकाल को कम करने का एकमात्र तरीका है। न्यायाधीश के दुर्व्यवहार को अधिनियम की धारा 6 (3) के अनुसार केवल तभी 'साबित माना जाता है' जब प्रस्ताव संसद द्वारा स्वीकार किया जाता है और अन्यथा नहीं। समिति द्वारा किए गए 'दोषी' का निष्कर्ष अपने आप में वह परिणाम नहीं लाता है। निष्कर्ष की निर्धारक प्रकृति का एक आवश्यक परीक्षण, न्यायाधिकरण की एक विशेषता का अभाव है। दो विरोधियों के बीच किसी भी विवाद या विवाद की अनुपस्थिति की परीक्षा भी इस तर्क को नकारती है कि समिति इस उद्देश्य के लिए एक न्यायाधिकरण है अनुच्छेद 136।

[169 ए-बी, 168 जी-एच]

6.3 . अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और

विशेष रूप से यह तथ्य कि कॉम के एक सदस्य द्वारा दर्ज किए गए कुछ निष्कर्ष

दी गई परिस्थितियों में समिति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है और

समिति द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी है, अंतिम और निर्णायक नहीं है, यह कानूनी रूप से 121 के लिए अनुमेय नहीं है।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

अभिनिर्धारित करें कि समिति संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक न्यायाधिकरण है। [169 एफ-जी]

जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम लक्ष्मीचंद और ओआरएस। , [1963] सप. 1

एस. सी. आर. 242; मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड के कर्मचारी बनाम मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड और अन्र. , जे. टी. (1992) 3 एस. सी. 446 और देव सिंह और अन्य। वी. पंजीयक, पंजाब और हरियाणा

उच्च न्यायालय और अन्य। , [1987] 2 एस. सी. आर. 1005 पर भरोसा किया गया।

भारत बैंक लिमिटेड बनाम। भारत बैंक लिमिटेड के कर्मचारी, [1950]

एस. सी. आर. 459 दुर्गा शंकर मेहता बनाम। ठाकुर रघुराज सिंह और अन्य। , [1955] 1 एस. सी. आर. 267 और भारत-चीन स्टीम नेविगेशन कंपनी। लिमिटेड वी. जसजीत सिंह,

[1964] 6 एस. सी. आर. 594, संदर्भित।

प्रति कासलीवाल, जे। (सहमत)

1. प्रतिलिपि की आपूर्ति के लिए अधिनियम या नियमों में कोई प्रावधान नहीं है

संसद के समक्ष रिपोर्ट रखने के लिए अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजने से पहले जांच समिति द्वारा संबंधित न्यायाधीश को। अधिनियम और नियमों और संविधान की योजना में, जांच समिति को उस स्तर पर न्यायिक समीक्षा की मांग के लिए न्यायाधीश को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है जब जांच पहले ही पूरी हो चुकी हो। [199 - डी, 205-ई]

2. न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसी के अधीन उभरता हुआ अधिकार नहीं है।

प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। इसे ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम के बराबर नहीं माना जा सकता है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार अपने आप में एक अधिकार है जो केवल सीमित अनुमेय आधारों पर उपलब्ध है। न्यायिक समीक्षा की मांग करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और कई कारकों पर निर्भर करेगा जिनकी जांच विशेष आदेश या कार्रवाई को चुनौती देने से पहले की जानी चाहिए। प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर कानून के अमूर्त प्रस्ताव के रूप में न्यायिक समीक्षा की कोई मांग नहीं हो सकती है। इस आधार पर कोई निर्देश नहीं मांगा जा सकता है कि यदि रिपोर्ट की प्रति अध्यक्ष को भेजने से पहले प्रदान नहीं की जाती है, तो विद्वान न्यायाधीश के पास बाद के चरण में न्यायिक समीक्षा का कोई उपाय नहीं बचेगा। अध्यक्ष को भेजने से पहले जांच रिपोर्ट की प्रति न देने में न तो प्राकृतिक न्याय के किसी सिद्धांत का उल्लंघन होता है और न ही किसी संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन होता है। [203 बी-ई]

2.1 . यह न्यायालय किसी भी प्राधिकरण को तब तक कोई आदेश नहीं दे सकता जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. न हो।

1 एस सी आर।

122

यह दिखाया जा सकता है कि ऐसा प्राधिकरण कानून या संवैधानिक दायित्व के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है। इस प्रकार, भले ही यह माना जाए कि समिति न्यायिक समीक्षा में इस न्यायालय की अधिकारिता के लिए उत्तरदायी एक वैधानिक कार्य कर रही है, यह दिखाया जाना चाहिए कि यह किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन कर रही है। वर्तमान मामले में जांच समिति अपने कानूनी कर्तव्य का पालन कर रही है और अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजने के वैधानिक दायित्व को पूरा कर रही है और इस तरह समिति की ओर से ऐसी कानूनी कार्रवाई में देरी करने या कोई बाधा डालने के लिए कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया जा सकता है। [203 एफ-जी]

3. वर्तमान में संबंधित न्यायाधीश को सुनवाई का अधिकार

कानून की योजना केवल दो प्राधिकरणों के सामने उत्पन्न हो सकती है। एक जाँच समिति के समक्ष और दूसरा संसद के समक्ष। जहाँ तक जाँच समिति के समक्ष सुनवाई के अवसर का संबंध है, प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि न्यायाधीश को उसके खिलाफ बनाए गए आरोपों को चुनौती देने के साथ-साथ किसी भी गवाह से जिरह करने और बचाव में किसी भी साक्ष्य का नेतृत्व करने के संबंध में सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है।

[201 - ई, 202 ए-बी]

3.1 . इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद अपना रास्ता अपनाने के लिए स्वतंत्र है

प्रस्ताव पर विचार करते समय प्रक्रिया, लेकिन केवल उसी को समिति की रिपोर्ट के खिलाफ न्यायिक समीक्षा की मांग के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। संसद द्वारा विद्वान न्यायाधीश के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं देने का सवाल संसद द्वारा न्यायाधीश के खिलाफ कोई निर्णय लेने के बाद ही उठ सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन पर आधारित किसी भी तर्क पर इस धारणा पर विचार नहीं किया जा सकता है कि संसद ऐसी प्रक्रिया अपना सकती है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो। इस प्रकार, यदि संसद द्वारा प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत के कथित उल्लंघन के आधार पर रिपोर्ट की प्रति प्रदान करने के लिए कोई निर्देश मांगा जा रहा है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है और यह इस मुद्दे का पूर्व निर्णय लेना और इस तरह की राहत के लिए कोई नींव या आधार रखे बिना किसी उपाय की भविष्यवाणी करना होगा। [202 सी-एफ]

4. इस मामले में पूरी संवैधानिक योजना से पता चलता है कि

संसद को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा पर पूरा भरोसा था। जाँच केवल उच्च न्यायिक अधिकारियों से बनी जाँच समिति पर छोड़ दी गई है। ऐसी समिति के दोषी नहीं होने का निष्कर्ष देने के मामले में, इसे अंतिम माना गया है और एक मौन दिया गया है और प्रस्ताव पर आगे कोई चर्चा नहीं की गई है। यह केवल जाँच 123 द्वारा दर्ज किए गए दोषी पाए जाने के मामले में है।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

समिति ने कहा कि आगे के विचार के लिए प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सहित व्यापक लोक हित में इस तरह के मामले में जाँच समिति द्वारा दोषी के इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद और इस स्तर पर न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ऐसी रिपोर्ट को चुनौती देने की अनुमति देने में कोई देरी नहीं होगी।

उचित है। जाँच समिति द्वारा संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ दोषी पाए जाने के मामले को, यदि कोई हो, दर्ज करने के बाद आगे के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। [205 जी-एच, 206-ए]

5. आरोपों पर समिति द्वारा दर्ज किए गए दोषी का निष्कर्ष है

निर्णायक और अंतिम नहीं है और संसद अभी भी यह मान सकती है कि संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोप दुर्व्यवहार के बराबर नहीं हैं और प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का निर्णय ले सकती है। दूसरी ओर, यदि न्यायिक समीक्षा के दौरान यह न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए ऐसे निष्कर्षों को मंजूरी देता है या पुष्टि करता है

जाँच समिति इस न्यायालय का निर्णय होने के कारण संसद के लिए बाध्यकारी होगी। उस स्थिति में, संसद के लिए एक अलग दृष्टिकोण रखना संभव नहीं होगा और यह योजना के ढांचे में एक अतिरिक्त संवैधानिक हस्तक्षेप होगा। एक अन्य मामले में न्यायिक समीक्षा के दौरान यह न्यायालय जांच समिति द्वारा की गई पूरी कार्यवाही को रद्द करने के निष्कर्ष पर आ सकता है और उससे एक नई जांच कराने की मांग कर सकता है। [204 सी-डी]

6. जांच समिति का जीवन और अस्तित्व नियमों के नियम 9 (2) (सी) में निर्धारित 3 महीने की अवधि के साथ या जब तक अध्यक्ष उपरोक्त नियम के परंतुक के तहत पर्याप्त कारण के लिए समय नहीं बढ़ाता है, तब तक सह-समाप्त होता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद, समिति कार्य करना बंद कर देती है और न तो यह न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय जांच समिति के निष्कर्षों की न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में इस अवधि को बढ़ा सकता है। वैधानिक नियमों में ही 3 महीने की अवधि तय की गई है और अकेले अध्यक्ष को पर्याप्त कारण के लिए ऐसी अवधि बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है। यह न्यायालय ऐसी अवधि नहीं बढ़ा सकता है और न ही अध्यक्ष को ऐसा करने के लिए कोई निर्देश दे सकता है, और मामले को नई जांच के लिए भेजने या मामले को लंबित रखने का कोई प्रयास तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि संबंधित न्यायाधीश न्यायिक समीक्षा के माध्यम से रिपोर्ट को चुनौती देने या मामले को न्यायिक समीक्षा के अभ्यास के तहत निर्णय के लिए लंबित रखने का फैसला नहीं करता है।

अवधि अनुमत नहीं है और अप्रत्यक्ष तरीके से नहीं किया जा सकता है जिसे सीधे नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय के पास वैधानिक नियमों के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार न्यायिक आदेश द्वारा जांच समिति के कार्यकाल को बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।

[204 ई-एच, 205-ए] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] समर्थन। 1 एस सी आर।

124

7. जहाँ तक संसद में कार्यवाही के समापन के बाद के चरण का संबंध है, न्यायिक समीक्षा का उपाय हमेशा उपलब्ध रहता है, जो निश्चित रूप से उस समय सामने आने वाले मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और न्यायिक समीक्षा के मान्यता प्राप्त अनुमेय आधारों के अधीन होगा, [205 ई-एफ]

8. जाँच समिति की शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित किए गए हैं और उच्च न्यायिक निकायों से बने हैं।

मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर संबंधित न्यायाधीश को अवसर देने के बाद अपने निष्कर्ष को दर्ज करने वाले अधिकारियों की तुलना किसी लोक सेवक के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत किसी कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी से नहीं की जा सकती है। [204 ए-बी]

9. न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति के मामले में वर्तमान मामले में उठाया गया विवाद मुद्दा नहीं था और उस मामले में न्यायालय सदन के विचार के लिए अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने के चरण और लोकसभा के विघटन पर ऐसे प्रस्ताव के भाग्य से संबंधित था। [200 डी-ई]

उप-न्यायिक जवाबदेही समिति v. भारत संघ और अन्य। , [1991] 4 एस. सी. सी. 699 ने समझाया।

पर के. रामास्वामी, जे. (असहमति)

1. न्यायाधीश रिपोर्ट की एक प्रति की आपूर्ति का हकदार है और समिति एक उच्च वैधानिक होने के कारण, न्यायालय स्थिति को बनाए रख सकता है। समिति के विचार में, विद्वत न्यायाधीश को रिपोर्ट की प्रति प्रदान करने का अनुरोध करें। इसका सहवर्ती यह होगा कि विद्वान न्यायाधीश

निर्णय लेने और उस पर कार्रवाई करने के लिए सोचने के लिए समय चाहिए। ज़रूरतेंवास्तव में, समिति से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह अपनी प्रस्तुति को रोक दे

2. विधायिका ने स्वयं उन निष्कर्षों के बीच अंतर किया है जो अपराध या दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दर्ज करने से प्रवाहित होंगे। और पूर्व राजनीतिक प्रक्रिया के अधीन है, विपरीत के साथ

तीसरे सदस्य का पता लगाना लेकिन बाद के मामले में यह निर्णायक है। जैसा कि आयोजित किया गया है उप-न्यायिक जवाबदेही के मामले पर समिति, कोई और कदम आधारित नहीं

इस पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह प्रतिरक्षा है

किसी भी हिस्से से हमले से, जब खुद संसद भी 125

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

उस प्रश्न में जाने से मना किया गया था। [216 डी-एफ]

2.1 . धारा 6 (1) के प्रवर्तन द्वारा, यदि समिति की रिपोर्ट

इसमें यह निष्कर्ष शामिल है कि न्यायाधीश दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है या किसी असमर्थता से पीड़ित नहीं है, तो दोनों में से किसी में भी आगे कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। रिपोर्ट के संबंध में संसद का सदन और एक विधायी अनिवार्यता है कि संसद के किसी भी सदन में लंबित प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, गति समाप्त हो जाती है। परिणाम की परिकल्पना नियम 9 (4) में भी की गई है। इस प्रकार 'दोषी नहीं', दूसरे शब्दों में, अधिकांश सदस्यों द्वारा कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता से 'दोषमुक्ति' के निष्कर्ष को निर्णायक माना जाता है और इसे गुप्त रखा जाना चाहिए और आवश्यक निहितार्थ से इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाना चाहिए। इसका कारण।

यह स्पष्ट है कि एक उच्च न्यायिक निकाय, एक अंतिम मध्यस्थ के निष्कर्ष का सम्मान किया जाना चाहिए; इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। समान रूप से अल्पमत के दृष्टिकोण का भी प्रकटीकरण न केवल न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा, बल्कि गैर-प्रकटीकरण किसी भी हिस्से से संपार्श्विक हमले या किसी तीसरे पक्ष द्वारा सवाल किए जाने वाले दायित्व को भी रोक देगा। न तो संसद के सदस्यों और न ही किसी को समिति द्वारा की गई जांच में न्यायाधीश के खिलाफ भाग लेने और साक्ष्य का नेतृत्व करने का अधिकार या अधिकार है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में कोई भी न्यायाधीश को आरोप से मुक्त करते हुए समिति द्वारा दर्ज 'दोषी नहीं' के निष्कर्षों की शुद्धता पर आक्षेप करने का हकदार है। [214 जी-एच, 215-ए, 216 बी-डी]

2.2 . इस प्रकार, यदि समिति सर्वसम्मति से या बहुमत से,

यह पाते हुए कि विद्वान न्यायाधीश दुर्व्यवहार का 'दोषी नहीं' है, निष्कर्ष शांत हो जाता है और निर्णायक होता है। राजनीतिक प्रक्रिया के अनुसार लंबित प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। 'अपराध' का अल्पमत निष्कर्ष गुप्त रहना चाहिए और किसी को भी दोषमुक्ति की रिपोर्ट तक पहुँचने या समिति द्वारा दर्ज किए गए दोषी नहीं होने के निष्कर्ष की शुद्धता पर हमला करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट की आपूर्ति करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। [223 - डी]

दूसरी ओर यदि समिति या तो सर्वसम्मति से या प्रति

बहुमत 'सिद्ध दुर्व्यवहार के लिए दोषी' का निष्कर्ष निकालता है, केवल उस हिस्से को अधिनियम और नियमों के संदर्भ में संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर 'दोषी नहीं' के अल्पमत के विचारों के साथ रखा जाना चाहिए और न्यायाधीश को हटाने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वह रिपोर्ट विद्वान न्यायाधीश के लिए प्रतिकूल है। बिना यह जाने कि रिपोर्ट की सामग्री क्या है; 126 के निष्कर्षों के समर्थन में तर्क गलत साबित हुआ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यवहार या अन्य अवैधता, एक पक्ष

कानूनी उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सामग्री की आपूर्ति के बिना, कानूनी चोट की नींव, न्यायाधीश पर्याप्त रूप से और प्रभावी ढंग से अनुरोध नहीं कर सकता है, साबित नहीं कर सकता है और निष्कर्ष आदि की गलतता का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। विद्वान न्यायाधीश सदन के पटल पर उपचार का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है। संसद। लेकिन रिपोर्ट की आपूर्ति न होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। यह न्यायिक प्रक्रिया के लिए अभिशाप है। द. अल्पसंख्यक सदस्य के 'अपराध' के निष्कर्ष की रिपोर्ट की गोपनीयता की रक्षा करना है

न्यायाधीश लेकिन जब अपराध का निष्कर्ष न्यायाधीश पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो गोपनीयता के अनुरोध पर इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, विद्वान न्यायाधीश रिपोर्ट की एक प्रति का हकदार है। [223 ई-एफ, 224 ए-डी]

3. प्रत्येक अधिकार अपने साथ निवारण के लिए आनुषंगिक उपाय रखता है

चोट लगी है। निर्विवाद रूप से और निष्पक्षता में एक तथ्य के रूप में, न्यायाधीश न्यायिक समीक्षा का हकदार है। विवाद का क्षेत्र यह है कि क्या संसद ने विचार के लिए प्रस्ताव को पहले लिया था या राष्ट्रपति द्वारा पारित किए जाने के बाद अनुच्छेद 124 (4) के तहत हटाने का आदेश। वह चरण केवल तभी निर्धारित होगा जब विद्वान न्यायाधीश ने न्यायिक समीक्षा की मांग करने का विकल्प चुना हो। यह तभी सामने आएगा जब उसे रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जाएगी।

[223 - जी, 224-ए]

तुन दातो हाजी मोहनद सल्लाह बिन अबुस बनाम। ताम श्री दातो, 1988

एल. आर. सी. 25; पॉवेल बनाम। मैककॉमैक, [1937] 395 यू. एस. 486; हालस्टेड एल. रिटर बनाम। यू. एस., 84 दावा न्यायालय 293 और रिटर बनाम। यू. एस., 300 यू. एस. 663, संदर्भित।

राउल बर्जर, महाभियोग: संवैधानिक समस्याएं, (1973);

महाभियोग पर काला; लॉरेंस जनजाति, अमेरिकी संवैधानिक कानून, 1988 द्वितीय संस्करण। ; मानपत्र, संवैधानिक कानून, 1991-92, संदर्भित।

एस. ए. डी स्मिथ, "औपनिवेशिक न्यायाधीशों द्वारा पद का कार्यकाल" 16 आधुनिक कानून

समीक्षा 502 (1974); डैनियल ए. रेजनेक, "महाभियोग आने की न्यायिक समीक्षा है" 60 अमेरिकन बार एसोसिएशन जर्नल, 681 (1974); मियाचेल जे. गेरहड्ट, "महाभियोग की संवैधानिक सीमाएँ और इसके विकल्प" 68 टेक्सास लॉ रिव्यू 1 (1989), का उल्लेख किया गया है।

4. सारत: दुर्व्यवहार की जाँच और प्रमाण या

अधिनियम और नियमों के साथ पठित अनुच्छेद 124 (5) के तहत एक न्यायाधीश की अक्षमता; संसद के प्रत्येक सदन द्वारा आवश्यक द्वारा समर्थित संबोधन

राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश का बहुमत और निष्कासन 127 द्वारा आवश्यक न्यायिक आचरण और उत्साह को पुनर्जीवित करने और प्रेरित करने के लिए एक अनुशासनात्मक उपाय के समान है।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई.

कानून की सर्वोच्चता का दावा कि न्यायाधीश भी कानून के अधीन होगा। न्यायाधीश एक संवैधानिक पद पर होता है। अनुच्छेद 124 (5) ने अक्षमता से पीड़ित एक गलती करने वाले न्यायाधीश या न्यायाधीश को हटाने के लिए न्यायिक और राजनीतिक दलाली का एक संयोजन तैयार किया। समिति द्वारा अध्यक्ष को इस निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत की गई रिपोर्ट कि कथित दुर्व्यवहार साबित हो गया है और न्यायाधीश को साबित दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया है, नई सामग्री का गठन करती है। एक अर्ध-न्यायिक मामले में, यदि अपराधी को उसके खिलाफ सामग्री की जानकारी से वंचित किया जा रहा है, हालांकि इसका लाभ अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के मामले में दंडक प्राधिकरण को दिया गया था।

यह प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन है। हालांकि, विधानमंडल इन सिद्धांतों के संचालन को स्पष्ट रूप से या निहित रूप से बाहर कर सकता है, लेकिन

बहुत अधिक बहिष्करण के अभाव में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा। दुर्व्यवहार या असमर्थता के अपराध का निष्कर्ष, जिससे न्यायाधीश पीड़ित है, पद की बरामदगी के अलावा समाज में प्रतिष्ठा के नुकसान के नागरिक परिणामों के साथ दौरा करेगा। अब यह तय कानून है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत परिकल्पित न्यायपूर्ण और निष्पक्ष प्रक्रिया की संवैधानिक राष्ट्रीय योजना का एक अभिन्न अंग हैं। [221 एफ-जी, 222 जी-एच, 223 ए-सी]

भारत संघ बनाम। एच. सी. गोयल, [1964] 4 एस. सी. आर. 718; भारत संघ और

ओआरएस। वी. मोहम्मद. रमजान खान, [1991] 1 एस. सी. सी. 588; मजहरुल इस्लाम हाशमी बनाम। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य, [1979] 4 एस. सी. सी. 537 और मोहिंदर सिंह गिल और अन्र। वी. मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली और अन्य।, [1978] 2 एस. सी. आर. 272 पर भरोसा किया।

अभिधारणा यह होनी चाहिए कि यह कानून का सृजन होना चाहिए और राज्य को न्यायाधिकरण को न्यायिक समीक्षा की अपनी अंतर्निहित शक्ति सौंपनी चाहिए; किसी दिए गए मामले में किसी न्यायालय के सभी या कुछ अंश उपस्थित हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। न्यायाधिकरण को पक्षों के बीच विवाद का फैसला करना चाहिए इसके समक्ष, पक्षकारों को उचित अवसर देने के बाद, निष्पक्ष खेल और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप। यह आवश्यक नहीं है कि प्रोपियो वीगर इसे लागू करने योग्य हो। केवल

यह तथ्य कि यह आगे के आदेशों के अधीन है, निर्णय या उसके तहत दर्ज किए गए निष्कर्षों के प्रभाव को दूर नहीं करता है। [220 डी-ई]

5.1 . समिति को कानूनी रूप से प्रस्तुत सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. पी. के अनुसार आरोपों के सबूत या अस्वीकृति पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

1 एस सी आर।

128

न्यायाधीश और अधिवक्ता को सुनने के बाद। 'सिद्ध अपराध या दोषी नहीं' के विवाद पर निर्णय लेने के अलावा समिति का कोई अन्य कार्य नहीं है। नियम 6 के संचालन द्वारा समिति, साक्ष्य पर विचार करने और 'उचित संदेह से परे प्रमाण' के मानक को लागू करने पर, यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित या गलत साबित हुई है। अकेले अपराध का पता लगाना राजनीतिक प्रक्रिया के अधीन है। अतः जाँच समिति एक उच्च न्यायिक निकाय या प्राधिकरण है। [221 सी-डी]

भारत-चीन स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड बनाम जसजीत सिंह, एडिशनल। कस्टम और ओआरएस के कलेक्टर।, [1964] 6 एस. सी. आर. 594 भारत बैंक लिमिटेड, दिल्ली बनाम. भारत बैंक लिमिटेड, दिल्ली [1950] एस. सी. आर. 495 के कर्मचारी; संबद्ध

सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम पी. एन. शर्मा और अनुर. , [1965] 2 एस. सी. आर. 366 दुर्गा शंकर महता बनाम। ठाकुर रघुराज सिंह और अन्य।, [1955] 1 एस. सी. आर. 267 और देव सिंह और अन्य। वी. पंजीयक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य।, [1987] 2 एस. सी. आर. 1005, संदर्भित।

6. जिस क्षण समिति द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए, वह वास्तव में संसद का दस्तावेज नहीं बन गया, लेकिन जब अध्यक्ष/सभापति या दोनों, जैसा भी मामला हो, रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर साक्ष्य और प्रस्ताव के साथ नियम 16 में निर्धारित तरीके से रखने का कारण बनते हैं, यह संसद का दस्तावेज बन जाता है। तब तक अध्यक्ष/सभापति अधिनियम के तहत दस्तावेज को अपनी वैधानिक क्षमता में रखते हैं। [218 ए-बी]

मौलिक न्यायनिर्णय: 1992 की लिखित याचिका (सिविल) सं. 514।

याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल और रंजीत कुमार।जी. रामास्वामी, महान्यायवादी, डी. एन. द्विवेदी, अतिरिक्त महान्यायवादी। वकील

उत्तरदाताओं के लिए जनरल (एन. पी.), एफ. एस. नरीमन, सुश्री ए. सुभाषनी, पी. एच. पारेख, राजू रामचंद्रन, सुभाष चंद्र शर्मा, सुनील डोगरा और ए. एम. खान विल्कर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वर्मा, जे. न्यायिक समीक्षा की मांग करने का हकदार व्यक्ति और जिस स्तर पर यह जांच समिति के निष्कर्षों के खिलाफ उपलब्ध है

एस. एम. टी. घोषित कानून के अनुसार न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (2) के तहत गठित।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

129

न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति v. भारत संघ और अन्य, [1991]। 4 एस. सी. सी. 699-इस रिट याचिका में निर्णय का प्रश्न है। याचिकाकर्ता के अनुसार, न्यायिक समीक्षा का उपाय उपलब्ध है

जांच समिति द्वारा इस निष्कर्ष के खिलाफ संबंधित न्यायाधीश, यदि कोई हो, कि विद्वान न्यायाधीश अधिनियम की धारा 4 (2) के अनुसार अध्यक्ष को समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ही दुर्व्यवहार का 'दोषी' है या नवीनतम जब तक कि इसे अधिनियम की धारा 4 (3) द्वारा आवश्यक संसद के समक्ष रखा जाता है, लेकिन उसके बाद नहीं। तदनुसार, याचिकाकर्ता का दावा है कि रिपोर्ट की एक प्रति अध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले संबंधित न्यायाधीश को प्रस्तुत की जानी चाहिए, ताकि न्यायाधीश के अधिकार को संरक्षित किया जा सके - रिपोर्ट में 'दोषी', यदि कोई हो, के निष्कर्ष की न्यायिक समीक्षा की मांग करें। इस प्रस्तुतिकरण की योग्यता पर यहाँ विचार किया गया है।

याचिकाकर्ता न्यायमूर्ति श्री वी. रामास्वामी की पत्नी हैं, जो एक वर्तमान न्यायाधीश हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस रिट याचिका में कुछ संवैधानिक मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के निर्माण पर निर्णय लिया जाना है, जिसे न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 के साथ पढ़ा जाना है। भारत संघ और अन्य, [1991] 4 एस. सी. सी. 699। संक्षेप में, यह याचिका कानून में दिए गए उस पहले के फैसले की अगली कड़ी है। श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए कार्यवाही का पाठ।

श्री वी. रामास्वामी के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले वित्तीय अनियमितताओं और अनियमितताओं के कुछ आरोप लगाए गए थे।

अक्टूबर 1989 में नौवीं लोकसभा के 108 सदस्यों द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव के एक रोटीस द्वारा। 12 मार्च, 1991 को नौवीं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, जिन्होंने इस न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति पी. वी. सावंत, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति पी. डी. देसाई और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 (2) के संदर्भ में एक प्रतिष्ठित न्यायविद के रूप में इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

श्री न्यायमूर्ति ओ. चिनप्पा रेड्डी की एक समिति का गठन किया। नौवीं लोकसभा के भंग होने पर, केंद्र सरकार का विचार था कि

नौवीं लोकसभा के 108 सदस्यों द्वारा विद्वान न्यायाधीश के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करने के लिए प्रस्ताव दिया गया।

1 एस सी आर।

130

नौवीं लोकसभा के अध्यक्ष का प्रस्ताव स्वीकार करने और अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक समिति का गठन करने का निर्णय नौवीं लोकसभा के भंग होने के साथ समाप्त हो गया था। तदनुसार, केंद्र सरकार ने अध्यक्ष के अधिसूचित करने के निर्णय की सहायता के लिए कार्य करने से परहेज किया

कि समिति में दो वर्तमान न्यायाधीशों की सेवाओं को संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी के पैरा 11 (बी) (आई) के अर्थ के भीतर 'वास्तविक सेवा' के रूप में माना जाएगा ताकि वे निम्नानुसार कार्य कर सकें -

समिति के सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 124 (5) के अनुसार बनाए गए अधिनियम के तहत एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव की स्थिति और लोकसभा के विघटन पर इस तरह के प्रस्ताव के लिए चूक के सिद्धांत की प्रयोज्यता के साथ-साथ संबंधित प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे, जिसमें कानून की अदालत में इसकी न्याय्यता भी शामिल है।

इन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ।

"न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति" नामक एक निकाय प्रतिनिधि

इस न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इसके संयोजक के रूप में 1991 की रिट याचिका संख्या 491 दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में 1991 की रिट याचिका संख्या 541 दायर की। दोनों याचिकाओं में आम लोगों की प्रार्थना भारत संघ को निर्देश देने के लिए थी कि वह तत्काल कदम उठाए ताकि जांच समिति अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। अधिनियम के तहत; और संबंधित न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी को न्यायिक कार्य करने और न्यायिक कार्य करने से रोकने के लिए

समिति के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान शक्तियाँ। संविधान पीठ द्वारा उसमें दिया गया निर्णय न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति v है। भारत संघ और ओआरएस।, [1991] 4 एससीसी 699। 4 के बहुमत से संविधान पीठ: 1 अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत एक प्रस्ताव सदन के विघटन पर समाप्त नहीं होता है। बहुमत की राय इस प्रकार समाप्त हुई:

" बस इतना करना आवश्यक है कि सही घोषित किया जाए

संवैधानिक स्थिति। कोई विशिष्ट रिट या निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

किसी भी प्राधिकरण को जारी करें। प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु और अंततः इसका उद्देश्य

जो कुछ भी आवश्यक है उसकी सेवा करना कानूनी घोषित करना है और

संवैधानिक स्थिति और विभिन्न अंगों को छोड़ दें

राज्य के दायरे में आने वाले मामलों पर विचार करने के लिए

उनकी संबंधित अधिकारिता और शक्तियाँ। " (पैरा 123 पर

पी। 762)

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

131

उन मामलों में संविधान पीठ के समक्ष विवाद था

इसलिए निर्णय लिया और याचिका संख्या लिखें। 491 और 1991 के 541 का निपटारा निर्णय में निहित कानून की उचित घोषणाओं द्वारा किया गया था।

इसमें कानूनी और संवैधानिक स्थिति की घोषणा के बाद

उपरोक्त निर्णय में विवादग्रस्त बिंदुओं की ओर से, भारत संघ ने नौवीं लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णय की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाए और भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी के पैरा 11 (बी) (i) द्वारा आवश्यक समिति के दो वर्तमान न्यायाधीशों के संबंध में आवश्यक अधिसूचना भी जारी की गई।

अधिनियम के तहत अध्यक्ष द्वारा गठित समिति तब

न्यायाधीश श्री वी. रामास्वामी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए आगे बढ़े और, जैसा कि इस याचिका की सुनवाई में सूचित किया गया है, समिति ने जांच पूरी कर ली है और अधिनियम की धारा 4 (2) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करने के लिए अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है।

विद्वान न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी ने दिनांकित एक पत्र भेजा।

10 मई, 1992 को जांच समिति के पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत से अनुरोध किया गया कि समिति की रिपोर्ट की एक प्रति उन्हें भेजी जाए ताकि उन्हें समिति के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, यदि आवश्यक या आवश्यक हो, तो अदालत में निवारण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके।

सचिव द्वारा उन्हें 15 मई, 1992 के पत्र द्वारा समिति को जवाब भेजा गया था। इन पत्रों को सामूहिक रूप से याचिका के अनुलग्नक I में चिह्नित किया गया है। इन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" जस्टिस वी. रामास्वामी

न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय

2 , तीनमूर्ति मार्ग

नई दिल्ली-110011

10 मई, 1992

माननीय न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत

पीठासीन अधिकारी

के तहत नियुक्त समिति

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968

433 संसद भवन अनुलग्नक

नई दिल्ली-110001।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1

साहब,

मुझे सूचित किया गया है कि समिति अपना काम फिर से शुरू कर रही है।

समिति। न्यायिक जवाबदेही v. भारत संघ और अन्य। , [1991] 4 एस. सी. सी. 699 ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत समिति एक वैधानिक समिति है। और जब से वह अपनी कार्यवाही शुरू करता है और अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखे जाने तक, उसकी कार्यवाही को संसद के बाहर माना जाता है और इसलिए, न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

चूँकि समिति को मेरे खिलाफ बनाए गए विभिन्न आरोपों के संबंध में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे समय पर रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए ताकि मेरे खिलाफ कोई भी निष्कर्ष दिए जाने की स्थिति में मुझे उचित कार्यवाही दायर करके इसे चुनौती देने का अधिकार दिया जा सके। संविधान पीठ के फैसलों को पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा अवसर मेरे लिए उपलब्ध होगा, क्योंकि समिति संसद के बाहर एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करती है। इसलिए, मुझे उम्मीद नहीं है समिति। इस मूल्यवान संवैधानिक अधिकार को निष्फल बनाने के लिए, यदि इसकी रिपोर्ट मेरे लिए

प्रतिकूल है, तो इसे जल्दबाजी में माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत करके, जो इसे सत्र के दौरान संसद के समक्ष रख सकते हैं।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

133

इस तरह की प्रक्रिया का सहारा लेना न केवल रिपोर्ट प्राप्त करने के मेरे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा, क्योंकि उस स्थिति में, मुझे एक उपयुक्त मंच पर रिपोर्ट को चुनौती देने से पहले ही खाली कर दिया जाएगा।

मैं आपको बहुत पहले से लिख रहा हूँ ताकि

रिपोर्ट के पूरा होने पर, एक प्रति मुझे तुरंत भेजी जाती है और यदि आवश्यक या आवश्यक हो तो मुझे अदालत में निवारण की मांग करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। इसलिए, स्वाभाविक रूप से, आप मुझे रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करके, उक्त रिपोर्ट को एक साथ माननीय अध्यक्ष को अग्रेषित करने से रोकेंगे। इसलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस अनुरोध का बहुत जल्द जवाब देंगे, क्योंकि इस संबंध में कोई भी देरी मेरे हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी और माननीय के निर्णय द्वारा मुझे दिए गए अधिकार की सीमा को भी विफल कर देगी।

सुप्रीम कोर्ट। कृपया आपके इस पत्र को प्राप्त करने के कुछ दिनों के भीतर मेरे इस अनुरोध का जवाब दें। आभार व्यक्त करते हुए,

आपकी ईमानदारी से,

एसडी /

(वी. रामास्वामी) "

" समिति के तहत आवेदन किया गया न्यायाधीश (पूछताछ) अधिनियम, 1968

433 , संसद भवन अनुलग्नक

नई दिल्ली-110001

15 मई, 1992

17 - सी. बी.-II/91

सी. गुप्ता,

सचिव सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

134 को।

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. रामास्वामी,
न्यायाधीश, भारत का सर्वोच्च न्यायालय,
2, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110011।

साहब,

आपके 10 मई, 1992 के पत्र के संदर्भ में

समिति के लिए उस वकील ने आपका पत्र लाया संविधान पीठ का ध्यान जो अब जब्त कर लिया गया है

14 मई, 1992 को सुनवाई के दौरान मामले में 1992 की रिट याचिका संख्या 149, जिसमें कहा गया है कि समिति

इसमें दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करेंगे।

उक्त मामले में उनके प्रभुओं द्वारा सम्मान।

आपकी वफादारी से,

एस. डी/- एस. सी. गुप्ता

सचिव "

याचिकाकर्ता, श्रीमती. श्री न्यायमूर्ति वी. की पत्नी सरोजिनी रामास्वामी

रामास्वामी ने यह रिट याचिका 6 जुलाई, 1992 को दायर की है।

अधिनियम के तहत प्रत्यर्थियों के रूप में नियुक्त। इस रिट याचिका में मांगी गई राहत समिति को रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने के निर्देश के लिए है श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी को समिति की ओर से और उक्त रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष को एक साथ अग्ररेषित करने से रोकने के लिए ताकि श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी अपनी रिपोर्ट में समिति के निष्कर्षों के खिलाफ, यदि आवश्यक या आवश्यक हो, तो न्यायालय में निवारण की मांग कर सकें। यह राहत [1991] 4 एस. सी. सी. 699 में रिपोर्ट की गई संविधान पीठ के निर्णय के आधार पर मांगी गई है कि समिति की पूरी कार्यवाही वैधानिक प्रकृति की है और इसलिए, न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

जब यह मामला पहली बार 21 जुलाई, 1992 को हमारे सामने सुनवाई के लिए आया,

हमने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल को संकेत दिया कि भले ही इस याचिका में दावा की गई राहत के लिए याचिकाकर्ता का अधिकार 135 है

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

यह विद्वान न्यायाधीश की पत्नी के रूप में उनकी स्थिति और उनके पति के माध्यम से उन्हें प्राप्त होने वाले अधिकार पर आधारित था, फिर भी न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी को एक पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था और यह भी संकेत नहीं दिया गया था कि रिट याचिका विद्वान न्यायाधीश के लिए और उनकी ओर से थी ताकि इस याचिका में निर्णय के लिए विद्वान न्यायाधीश को ही बाध्य किया जा सके। हमने यह भी बताया कि गुण-दोष के आधार पर इस रिट याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले विद्वान न्यायाधीश की सटीक स्थिति हमें स्पष्ट करनी होगी। श्री कपिल सिब्बल

उन्होंने संकेत दिया कि विद्वान न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी इसमें दिए गए निर्णय से बाध्य होंगे और उन्होंने इस आशय से एक लिखित याचिका दायर करने का भी बीड़ा उठाया। तदनुसार हमने इस उद्देश्य के लिए मामले को अगले दिन, 22 जुलाई, 1992 तक के लिए स्थगित कर दिया। 21 जुलाई, 1992 की कार्यवाही इस प्रकार है:

" श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील, की ओर से पेश होते हैं

न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी न्यायनिर्णायक द्वारा बाध्य होंगे। इस याचिका में जो कहा गया है जिसमें उसकी पत्नी याचिकाकर्ता है,

विद्वान न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी और कल तक अदालत में इसे दायर करें।

सुबह।

इस मामले पर कल 22 जुलाई को सुनवाई होगी।

1992. "

22 जुलाई, 1992 को वकील श्री रंजीत कुमार ने श्री को निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में उनके द्वारा न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी को संबोधित एक पत्र दायर किया, जिसके आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने उनका समर्थन किया। उसी को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" रंजीत कुमार

अधिवक्ता

XXX

XXX

21 जुलाई, 1992।

सब: लिखित याचिका (सी) नहीं। 514 1992 का

एमआरएस। सरोजिनी रामास्वामी बनाम। यूनियनभारत और ओ. आर. एस.

136

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

पिरय महोदय,

जब रिट याचिका (सिविल) सं. 514/1992 को लिया गया था

आज, पीठ वाले माननीय न्यायाधीशों ने चाहा

बाध्यकारी के संबंध में आपके रुख के बारे में सूचित किया जाना

याचिका की स्थिति में निर्णय की प्रकृतिसुनवाई और उस पर दिए गए निर्णय के लिए लिया गया।

श्री कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अपनी ओर से पेश हुए

इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने विद्वान को सूचित किया

न्याय करता है कि श्रीमती रामास्वामी के अधिकार के रूप में इसे स्थानांतरित करने के लिए

माननीय न्यायालय आपके पद पर बने रहने के अधिकार से सीधे प्रवाहित हुआ

इस माननीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण करने के लिए, आप

स्वाभाविक रूप से संबंध में दिए गए निर्णय से बाध्य होना

1992 की रिट याचिका संख्या 514 में मांगी गई राहतों में से।

कृपया पुष्टि करें कि क्या श्री सिब्बल ने सही बताया है

माननीय इस संबंध में आपकी स्थिति का न्याय करते हैं।

आभार व्यक्त करते हुए,

आपकी वफादारी से,

एसडी /

(रंजीत कुमार)

2 , तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली,

श्री सिब्लल द्वारा दिया गया बयान मेरे कथन को सही ढंग से दर्शाता है।

स्थिति.

एस. डी./- वी. रामस्वान

21.7.1992

श्री रंजीत कुमार के उपरोक्त पत्र को पेश करने पर, बेयरिन

उस पर श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी द्वारा स्वीकृति का समर्थन I

उसके अपने हाथ, हमने इस प्रभाव के लिए एक आदेश दिया जो में निहित है

22 जुलाई, 1992 की कार्यवाही निम्नानुसार है:

" याचिकाकर्ता एस. एम. टी. के विद्वान वकील श्री रंजीत कुमार।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

137

21 जुलाई, 1992 को उनके द्वारा संबोधित एक पत्र दायर किया गया है श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी का समर्थन करते हुए

श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी ने इसे स्वीकार करते हुए उस पत्र में उल्लिखित स्थिति को सही करें। श्री कपिल

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील सिब्लल कहते हैं कि श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी द्वारा लिए गए इस रुख को ध्यान में रखते हुए

स्थिति यह है कि यह रिट याचिका सार में है विद्वान न्यायाधीश ने स्वयं अपनी पत्नी के माध्यम से दायर किया जिसे दिखाया गया है

याचिकाकर्ता के रूप में "।

(जोर दिया गया)

परिणाम यह है कि यह रिट याचिका सार में है

विद्वान न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी ने स्वयं अपनी पत्नी, याचिकाकर्ता श्रीमती के माध्यम से याचिका दायर की। अपने पति न्यायमूर्ति श्री वी. रामास्वामी की ओर से दावा की गई राहत के लिए सरोजिनी रामास्वामी। इस रिट याचिका को यहां उठाए गए बिंदुओं को तय करने के उद्देश्य से तदनुसार माना जाता है।

उत्तरदाताओं, अर्थात् संघ को नोटिस जारी करने के अलावा,

भारत सरकार और अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत नियुक्त जांच समिति, हमने विद्वान अटॉर्नी जनरल से भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में अदालत में उपस्थित होने और उनकी सहायता करने का भी अनुरोध किया। हमने याचिकाकर्ता की ओर से श्री कपिल सिब्बल और जांच के लिए श्री एफ. एस. नरीमन को सुना है।

समिति और महान्यायवादी श्री जी. रामास्वामी।

इनके द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने से पहले

विद्वान अधिवक्ता, हम 1992 के श्री कृष्ण स्वामी बनाम की रिट याचिका (सिविल) संख्या 149 का संक्षिप्त संदर्भ देना उचित समझते हैं। भारत संघ और अन्य।, जो पहले दायर किया गया था और जिसका संदर्भ इस रिट याचिका के साथ-साथ श्री न्यायमूर्ति वी. के बीच पत्राचार में दिया गया है।

रामास्वामी और समिति।

1992 की रिट याचिका संख्या 149 एम. कृष्णा द्वारा न्यायालय में दायर की गई थी।

स्वामी, दसवीं लोकसभा के सदस्य, उसमें निर्दिष्ट कई राहतों के लिए। ये राहतें नियुक्त समिति द्वारा की गई उपरोक्त जांच से संबंधित हैं।

श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए अधिनियम के तहत। याचिकाकर्ता एम. कृष्ण स्वामी ने दावा किया कि

बेटा दसवीं लोकसभा के सदस्य के साथ-साथ मद्रास के एक वकील के रूप में रुचि रखता है जो लंबे समय से न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के लिए जाना जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. पी. के लिए प्रतिकूल समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में वैधताएँ।

1 एस सी आर।

विद्वान न्यायाधीश न्यायमूर्ति V.Ramaswami और इसके आधार पर, न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति में निर्णय पर पुनर्विचार करने के अलावा, समिति द्वारा बनाए गए आरोपों को रद्द करने और यह घोषणा करने की भी मांग की कि समिति की कार्यवाही अमान्य है। उस रिट याचिका को शुरू में तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक खंड पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिसने रिट याचिका को एक बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई के लिए भेजा था। इस प्रकार 1992 की रिट याचिका संख्या 149 इस पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। आई. डी. 1 पर, एक पक्ष के रूप में न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी की अनुपस्थिति में उस रिट याचिका की स्थिरता के सवाल पर विचार करते हुए, उस रिट याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने भी उस याचिका में श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी को एक पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए एक आवेदन करने में समय लिया। हालांकि, आई. डी. 1 पर श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं करना चाहते थे और उन्होंने उस रिट याचिका को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। तदनुसार, उस रिट याचिका की सुनवाई विद्वान न्यायाधीश न्यायमूर्ति को आरोपित किए बिना उसमें दावा की गई राहतों को प्रदान करने के लिए इसकी स्थिरता के सवाल पर की गई थी।

वी. रामास्वामी, जो निस्संदेह निर्णय से सीधे प्रभावित होंगे उसमें उठाए गए प्रश्नों के गुण-दोष पर। हम रिट याचिका का निपटारा कर रहे हैं।

1992 का सं. 149 याचिकाकर्ता द्वारा उस याचिका का अनुसरण करने के लिए श्री न्यायमूर्ति वी. रामास को शामिल करने से इनकार करने के लिए उसमें लिए गए निश्चित रुख पर भी अलग से।

इस उद्देश्य के लिए दिए गए अवसर के बावजूद वामी। श्रीमती द्वारा 1992 की वर्तमान रिट याचिका संख्या 514। इन परिस्थितियों में समिति द्वारा जांच के समापन पर सरोजिनी रामास्वामी को दायर किया गया।

अधिनियम के तहत अभिनिर्धारित।

इस रिट याचिका में निर्णय के लिए मुख्य बिंदु-1992 की रिट याचिका संख्या 154-है: चाहे न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति के निर्णय के परिणामस्वरूप, न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी को इस अधिनियम की धारा 4 (2) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से पहले समिति की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने का अधिकार है।

कानून की अदालत में इस स्तर पर उसके खिलाफ निष्कर्ष, यदि कोई हो? याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल का कहना है कि न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी का यह अधिकार न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति के निर्णय का एक तार्किक परिणाम है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करने और इसे विचार के लिए सदन के समक्ष रखे जाने की प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के लिए वैधानिक विषय है। विद्वान वकील का आगे निवेदन यह है कि इसके विपरीत दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप विद्वान न्यायाधीश प्रतिकूल एस. एम. टी. को चुनौती देने के अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

139

प्रक्रिया का संसदीय भाग शुरू होने के बाद 'दोषी' का पता लगाना, यदि कोई हो। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसके बाद हटाने का आदेश संसदीय प्रक्रिया की पराकाष्ठा होने की चुनौती से मुक्त होगा और इसलिए, विद्वान न्यायाधीश को प्रक्रिया के वैधानिक भाग की न्यायिक समीक्षा की मांग करने के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, भले ही यह बाद के संसदीय भाग की नींव हो। श्री सिब्ल ने आग्रह किया कि इस प्रक्रिया के प्रभावी होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने का आदेश संसदीय प्रक्रिया की पराकाष्ठा न्यायिक समीक्षा से मुक्त होगा और इसलिए, जब तक कि विद्वान न्यायाधीश को प्रक्रिया के संसदीय भाग के प्रारंभ से पहले न्यायिक समीक्षा की मांग करने का अवसर नहीं मिलता है, उनका संवैधानिक अधिकार, समिति के प्रतिकूल निष्कर्षों में समाप्त होने वाली प्रक्रिया में किसी भी अवैधता के बावजूद, पहले के निर्णय में की गई कानून की घोषणा के बावजूद पराजित हो जाएगा। अंत में, श्री सिब्ल ने तर्क के इस भाग को थोड़ा संशोधित करते हुए कहा कि यह मानते हुए भी कि अनुच्छेद 124 (4) के तहत राष्ट्रपति द्वारा हटाए गए आदेश को अवैधता के अनुमेय आधार पर न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं माना जा सकता है, जो विद्वान वकील के अनुसार बेहद संदिग्ध है, अनुच्छेद 124 (4) के तहत हटाने का आदेश देने के बाद तक न्यायिक समीक्षा के चरण को स्थगित करने से विद्वान न्यायाधीश के लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा होगा यदि अवैधता समिति की रिपोर्ट में 'दोषी' के निष्कर्ष से जुड़ी है। संक्षेप में, श्री कपिल सिब्ल के अनुसार, समिति के निष्कर्षों की वैधता का परीक्षण करने के लिए न्यायिक समीक्षा

संसदीय प्रक्रिया शुरू होने से पहले या तो 'अभी' उपलब्ध है।

अधिनियम 'या कभी नहीं' की धारा 4 (2) के तहत अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर। श्री सिब्ल के अनुसार, यह एक वैधानिक प्राधिकरण समिति को अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले विद्वान न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश देने का कारण है। अधिनियम की धारा 4 (2) के साथ। इसलिए सवाल यह है: क्या मूल आधार जिस पर तर्क आधारित है, अर्थात् न्यायिक समीक्षा 'अभी या कभी नहीं' सही है या कानून यह है कि-अनुमेय आधारों पर न्यायिक समीक्षा अब नहीं है, बल्कि बाद में ही है यदि संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के तहत राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश दिया जाता है? क्या यह है कि संवैधानिक योजना में अनुज्ञेय चुनौती वास्तव में अनुच्छेद 124 (4) के तहत राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने के आदेश के लिए है जो हटाने की समग्र प्रक्रिया पर आधारित है जिसमें प्रारंभिक वैधानिक भाग शामिल है जो प्रक्रिया के लिए पूर्व शर्त प्रदान करता है, और प्रक्रिया का संसदीय भाग।

इसके बाद?

श्री एफ. एस. नरीमन, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील।

1 एस सी आर।

140

समिति ने न्यायिक समीक्षा के अनुमेय आधार पर प्रक्रिया के वैधानिक भाग की न्यायिक समीक्षा की मांग करने के विद्वान न्यायाधीश के अधिकार पर विवाद नहीं किया, जैसा कि पहले के निर्णय में घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि जांच पूरी होने पर रिपोर्ट में निष्कर्षों को दर्ज किया जाए। संवैधानिक अधिकारियों के बीच सौहार्द का सिद्धांत यह आवश्यक है कि अदालतों को रिपोर्ट में निष्कर्ष दर्ज होने के बाद अधिनियम द्वारा विचार की गई प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए; और न्यायिक समीक्षा केवल उस स्थिति में होनी चाहिए जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के तहत हटाने का आदेश दिया जाता है यदि -

संसद 'दोषी', यदि कोई हो, के प्रतिकूल निष्कर्ष पर कार्रवाई करने का विकल्प चुनती है जैसा कि निर्धारित किया गया है, हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करके समिति की रिपोर्ट। श्री नरीमन ने कहा कि विद्वान न्यायाधीश एक अवसर के हकदार हैं

संसदीय प्रक्रिया के दौरान प्रतिकूल निष्कर्षों पर हमला करना और इस तरह संसद को समिति की रिपोर्ट की प्राप्ति पर प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मामले पर ठीक से विचार करने में सुविधा प्रदान करना, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में न्यायमूर्ति एंजेलो वस्ता के महाभियोग के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया थी, जहां प्रक्रिया पूरी तरह से संसदीय है। श्री नरीमन ने कहा कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि संसद विद्वान न्यायाधीश को ऐसा अवसर नहीं देगी या प्रस्ताव पर मतदान करने से पहले विद्वान न्यायाधीश द्वारा उठाए गए निष्कर्षों पर आपत्तियों पर उचित रूप से विचार नहीं करेगी और यदि उन आपत्तियों को स्वीकार कर लिया जाता है और प्रस्ताव विफल हो जाता है, तो कार्यवाही विद्वान न्यायाधीश के पक्ष में समाप्त हो जाएगी, जिसके लिए उन्हें न्यायिक समीक्षा द्वारा निवारण की आवश्यकता नहीं होगी। श्री नरीमन ने आगे कहा कि भले ही वह एक निश्चित निवेदन नहीं कर सके कि हटाने का अंतिम आदेश, यदि कोई हो, न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, फिर भी उन्होंने कहा कि

सिद्धांत या प्राधिकरण में कोई स्पष्ट सीमा खोजने में असमर्थ

शक्ति

राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने के आदेश के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा

संविधान का अनुच्छेद 124 (4) अवैधता के अनुमेय आधारों पर जिसके आधार पर केवल विद्वान न्यायाधीश संविधान के प्रतिकूल निष्कर्षों पर हमला कर सकते हैं।

इस स्तर पर समिति, यह मानते हुए कि उसे ऐसा करने का अधिकार है, बैठक से पहले

संसदीय प्रक्रिया का सुदृढीकरण।

विद्वान महान्यायवादी ने शुरुआत में श्री कपिल सिब्बल के तर्कों को पूरी तरह से अपनाया और याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन किया। हालांकि, विद्वान महान्यायवादी के अंतिम रुख को संशोधित किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 124 (4) के तहत राष्ट्रपति द्वारा हटाए गए आदेश को चुनौती देने के विद्वान न्यायाधीश के अधिकार को संदिग्ध होने के कारण, यह उचित है कि प्रतिकूल निष्कर्ष, यदि कोई हो, के मामले में न्यायिक समीक्षा की मांग करने के उनके अधिकार को विफल करने से बचने के लिए, विद्वान न्यायाधीश को 141 की एक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत अध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले इस स्तर पर समिति की रिपोर्ट। विद्वान महान्यायवादी श्री एफ. एस. नरीमन से पूरी तरह सहमत थे कि समिति द्वारा प्रतिकूल निष्कर्ष की स्थिति में, विद्वान न्यायाधीश अपने खिलाफ निष्कर्ष पर हमला करने के लिए समान दायित्व प्रक्रिया के दौरान एक अवसर का हकदार होगा और इस तरह संसद को प्रस्ताव पर ठीक से विचार करने में सुविधा होगी।

जैसा कि ऊपर संक्षेप में बताया गया है, प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों से यह स्पष्ट है कि

यदि विद्वान न्यायाधीश को संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के तहत उनके खिलाफ हटाने का आदेश दिया जाता है, तो न्यायिक समीक्षा की मांग करने का अधिकार होगा, और न्यायिक समीक्षा के अनुमेय आधार जो भी इस स्तर पर हों, वे तब अप्रभावित रहेंगे, संसदीय प्रक्रिया शुरू होने से पहले समिति की रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता का मुख्य कारण गायब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, एकमात्र अन्य प्रश्न यह होगा: क्या हटाने का आदेश, यदि कोई हो, दिए जाने के बाद तक उस अधिकार के प्रयोग को स्थगित करने से कोई अतिरिक्त पूर्वाग्रह है? यह आगे का सवाल तभी उठेगा जब संवैधानिक योजना में अब और अंत में विद्वान न्यायाधीश के लिए न्यायिक समीक्षा के उपाय की परिकल्पना की गई हो। यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि संवैधानिक योजना संबंधित न्यायाधीश द्वारा समिति की रिपोर्ट में अभिलिखित 'दोषी' के प्रतिकूल निष्कर्ष को केवल तभी चुनौती देने की परिकल्पना करती है और अनुमति देती है जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के तहत हटाने का आदेश दिया जाता है और इससे पहले नहीं, तो यह विचार किया जा रहा है कि संसदीय प्रक्रिया के दौरान संबंधित न्यायाधीश को इस उद्देश्य के लिए एक अवसर दिया जाएगा ताकि संसद न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर मतदान करने से पहले संबंधित न्यायाधीश की प्रतिकूल निष्कर्षों पर आपत्तियों, यदि कोई हो, को ध्यान में रख सके, तो मध्यवर्ती स्तर पर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रतिबंध को इस तरह के मामले में बाहर रखा जाएगा जहां अभियान और प्रक्रिया का शीघ्र समापन अत्यधिक सार्वजनिक महत्व का है। तब योजना यह होगी कि समिति द्वारा 'दोषी' के प्रतिकूल निष्कर्ष के मामले में, संसद संबंधित न्यायाधीश को प्रतिकूल निष्कर्षों के आधार पर उन्हें हटाने के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर देती है और प्रस्ताव पर मतदान के लिए इसे विचार में लेती है ताकि यदि वह संबंधित न्यायाधीश की आपत्तियों को स्वीकार कर

ले, तो प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा और मामला वहीं रह जाएगा। विद्वान न्यायाधीश को तब संसदीय प्रक्रिया से पहले की प्रक्रिया के वैधानिक भाग को चुनौती देने के लिए न्यायालय में निवारण की मांग करने की आवश्यकता नहीं होगी।

142

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

तथापि, यदि संबंधित न्यायाधीश द्वारा उठाए गए निष्कर्षों पर आपत्तियों के बावजूद प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के तहत हटाने का आदेश दिया जाता है, तो केवल संबंधित न्यायाधीश के लिए प्रतिकूल निर्णय पर हमला करने का अवसर होता है।

'दोषी' का पता लगाना और न्यायिक समीक्षा के अनुमेय आधारों पर उससे पहले की वैधानिक प्रक्रिया, उस आधार पर अदालत में हटाने के आदेश को चुनौती देकर। लोक हित में इस तरह की कार्यवाही के शीघ्र समापन की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए, ऐसी संवैधानिक योजना व्यापक लोक हित के साथ सामंजस्य स्थापित करना अनुचित नहीं होगा।

स्वयं संबंधित न्यायाधीश के व्यक्तिगत हित के साथ। पहला बिंदु

इसलिए, विचार के लिए है: संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के तहत राष्ट्रपति द्वारा हटाए गए आदेश के संबंधित न्यायाधीश में न्यायिक समीक्षा के अधिकार का अस्तित्व, यदि। और जब इसे बनाया जाता है।

श्री कपिल सिब्बल का एक और निवेदन, वास्तव में, ऊपर बताए गए अपने मुख्य निवेदन को पुष्ट करने के लिए, यह है कि एस. सी. के तहत गठित समिति

अधिनियम की धारा 3 (2) एक न्यायाधिकरण है और इसलिए, इसके निष्कर्ष संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में अपील के अधीन हैं। यह तर्क यह भी दावा करने के लिए है कि विद्वान न्यायाधीश अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत अध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले रिपोर्ट की एक प्रति का हकदार है ताकि वह रिपोर्ट में 'दोषी' के प्रतिकूल निष्कर्ष, यदि कोई हो, के खिलाफ अपील करने के अधिकार का प्रयोग कर सके। संविधान और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संवैधानिक योजना, जिसे अधिनियम के तहत बनाए गए न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 के साथ संविधान के अनुच्छेद 124 (5) के तहत बनाया गया था, पर विचार किया गया था और न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति के पहले के निर्णय में इसका संकेत दिया गया था। हालाँकि, न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 और न्यायाधीश (जाँच) नियम, 1969 में योजना को दोहराना उपयोगी है।

न्यायिक उत्तरदायित्व पर उप-समिति में की गई विधि की घोषणा के आधार पर निर्णय के लिए अब उत्पन्न होने वाले प्रश्न के संदर्भ में इसके तहत किया गया है। हम विज्ञापन देने से पहले ऐसा करने के लिए आगे बढ़ते हैं

पहले के निर्णय में की गई कानून की विशिष्ट घोषणा।

अनुच्छेद 124 (5) एक न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और सबूत में देरी करने के लिए एक संसदीय कानून के अधिनियमन को अनिवार्य करता है।

खंड (4) के तहत और इसके अनुसरण में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। जैसा कि एस. एम. टी. न्यायिक लेखा पर उप-समिति में कहा गया है।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

143

क्षमता, अनुच्छेद 124 के निर्माण पर, 'नीति यह प्रतीत होती है कि दुर्व्यवहार या अक्षमता के प्रमाण तक का पूरा चरण, आरोप लगाए जाने पर जांच शुरू करने से शुरू होकर, अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून द्वारा शासित है और अनुच्छेद 121 में प्रदान किए गए प्रतिबंधों को देखते हुए, कि तंत्र संसद के बाहर होना चाहिए और उसके भीतर नहीं होना चाहिए' और 'संसद तभी तस्वीर में आती है जब उस तंत्र द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच शुरू की गई है। साबित हुआ'। संविधान के अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 को इस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, इसके प्रावधान का अर्थ उसी प्रकाश में लगाया जाना चाहिए।

न्यायाधीश (इंक्युरी) अधिनियम, 1968 में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया तभी शुरू की जा सकती है जब राष्ट्रपति को संबोधित करने के लिए एक प्रस्ताव का नोटिस, जिस पर लोक सभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्य परिषद के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।

अध्यक्ष/सभापति अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसार। न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई अन्य तरीका स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। अध्यक्ष/सभापति को प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है 'ऐसे व्यक्तियों से परामर्श करने के बाद, यदि कोई हो, जो वह उचित समझता है और ऐसी सामग्री पर विचार करने के बाद, यदि कोई हो, जो उसके पास उपलब्ध हो'। संकेत यह है कि अध्यक्ष/सभापति को ऐसे व्यक्तियों से परामर्श करने का अधिकार है जो वह उचित समझते हैं और प्रस्ताव को स्वीकार करने या स्वीकार करने से इनकार करने का निर्णय लेने के लिए उनके पास उपलब्ध सामग्री पर विचार करने की आवश्यकता है। यह मान लेना उचित होगा कि ऐसे व्यक्ति से परामर्श किया जाएगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, जो

भारतीय न्यायपालिका का प्रमुख होने के अलावा उच्चतम न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के एक वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत गठित समिति के सदस्यों के रूप में चुनने और उपलब्ध कराने में भी शामिल होगा, यदि प्रस्ताव अध्यक्ष/अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है। धारा 3 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष/सभापति, यदि प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, तो प्रस्ताव को लंबित रखेंगे और उन आधारों की जांच करने के उद्देश्य से, जिनके आधार पर प्रस्ताव को हटाया गया है, जल्द से जल्द गठन करेंगे।

न्यायाधीश के लिए प्रार्थना की जाती है, तीन सदस्यों की एक समिति जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से होगा, एक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होगा। इसका अर्थ है कि निर्दिष्ट सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. द्वारा दिए गए प्रस्ताव के नोटिस में उन आधारों की जांच जिसके आधार पर किसी न्यायाधीश को हटाने का अनुरोध किया गया है।

1 एस सी आर।

जाँच 'और अध्यक्ष/सभापति' रिपोर्ट को, जितनी जल्दी हो सके, लोक सभा और परिषद के समक्ष रखेगा। राज्यों का। वर्तमान संदर्भ में, इस स्तर पर यह आवश्यकता है, 'जांच के समापन पर', जब समिति की रिपोर्ट तैयार की गई है, जो सवाल उठाती है: क्या, न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति में पहले के निर्णय के परिणामस्वरूप, समिति को अधिनियम की धारा 4 (2) द्वारा आदेशित अध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले संबंधित न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?

अधिनियम की धारा 6 समिति द्वारा अध्यक्ष/अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद के चरण का प्रावधान करती है। धारा 6 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि यदि समिति अपनी रिपोर्ट में संबंधित न्यायाधीश को दोषमुक्त करती है और यह निष्कर्ष दर्ज करती है कि न्यायाधीश 'किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है', तो संसद के किसी भी सदन में आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा और 'सदन में लंबित प्रस्ताव।

के साथ आगे बढ़े। धारा 6 की उप-धारा (1) से यह स्पष्ट है कि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज 'दोषी नहीं' का निष्कर्ष समाप्त करता है -

संबंधित न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया इसके अनुसार शुरू की गई

अधिनियम की धारा 3 (1), प्रक्रिया का वह हिस्सा जो वैधानिक है, और अध्यक्ष/अध्यक्ष द्वारा धारा 4 (3) के अनुसार सदन के समक्ष रखी जा रही समिति की रिपोर्ट पर शुरू की गई प्रक्रिया का संसदीय हिस्सा शुरू नहीं होता है। यह इन अभिव्यक्तियों से स्पष्ट है कि 'तब किसी भी सदन में आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा. और प्रस्ताव सदन में लंबित है।

अधिनियम की धारा 6 (1) में सदन की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

एसएमटी में। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

145

न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति, यह निम्नानुसार आयोजित की गई थी:

यदि, तथापि, निष्कर्ष द्वारा पहुँचा गया

अधिनियमित कानून में प्रदत्त तंत्र यह है कि-

यह साबित नहीं होता है, मामला समाप्त हो जाता है और कोई ओ. सी. नहीं होता है

अनुच्छेद के अनुसार प्रस्ताव पेश करने का मामला।

124 (4) . "

(पी पर पैरा 74। 744)

धारा 6 की उप-धाराएँ (2) और (3) ऐसी स्थिति प्रदान करती हैं जहाँ

समिति की रिपोर्ट में एक निष्कर्ष है कि न्यायाधीश दोषी है। कोई दुर्व्यवहार या किसी असमर्थता से पीड़ित। उप-धारा (2) में यह निर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत अध्यक्ष/सभापति द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव पर सदन द्वारा एक साथ विचार किया जाएगा।

समिति की रिपोर्ट के साथ। इस स्थिति में और इस तरह से किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का संसदीय भाग यह मानता है कि सदन को न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता है। उप-धारा (3) में कहा गया है कि यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अनुच्छेद 124 के खंड (4) के प्रावधान के अनुसार प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो न्यायाधीश का दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हुई मानी जाएगी और न्यायाधीश को हटाने का अनुरोध करने वाला संबोधन वह निर्धारित तरीके से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार, हटाने की प्रक्रिया के संसदीय भाग की शुरुआत पहले के वैधानिक भाग की समाप्ति के बाद होती है, केवल उस स्थिति में जब समिति की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष मिलता है कि न्यायाधीश किसी दुर्व्यवहार के लिए 'दोषी' है या किसी असमर्थता से पीड़ित है और अन्यथा नहीं। हटाने की पूरी प्रक्रिया प्रकृति में समग्र है।

न्यायाधीशों के प्रासंगिक प्रावधानों का एक संक्षिप्त संदर्भ (जांच)

उपरोक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियम, 1969 जो वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, अब बनाए जा सकते हैं। नियम 9 जांच समिति की रिपोर्ट से संबंधित है। उप-नियम (1) में कहा गया है कि जहां जांच समिति के सदस्य सर्वसम्मत नहीं हैं, वहां अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट सदस्यों के बहुमत के निष्कर्षों के अनुसार होगी। उप-नियम (2) जांच समिति के पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा करता है कि वह निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट डुप्लिकेट, ड्यूटी ऑथेन्टी में अध्यक्ष/अध्यक्ष को भेजे, जिनके

द्वारा समिति का गठन किया गया था। उप-नियम (3) के अनुसार जाँच समिति की रिपोर्ट की एक प्रमाणित प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी चाहिए। उप नियम (4)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

146

अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ तीसरे सदस्य के निष्कर्ष को भी अग्ररेषित किया जाएगा। उप-नियम (5) में तीसरे सदस्य द्वारा किए गए 'दोषी नहीं' के विपरीत निष्कर्ष की एक प्रामाणिक प्रति की आवश्यकता होती है। ऐसे मामले में भी संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। इस प्रकार, उप-नियम (4) और (5) में यह अपेक्षा की गई है कि जहां 'दोषी' का निष्कर्ष सर्वसम्मत नहीं है, बल्कि केवल बहुमत से है, तो संबंधित न्यायाधीश के पक्ष में तीसरे सदस्य की विपरीत राय भी संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष विचार के लिए रखी जाएगी, जो न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय बहुमत द्वारा 'दोषी' के निष्कर्ष वाली रिपोर्ट के साथ संसद को उपलब्ध होगी। उप-नियम (6) उस विपरीत स्थिति के लिए प्रावधान करता है जहां जांच समिति के अधिकांश सदस्यों का निष्कर्ष यह है कि न्यायाधीश 'दोषी नहीं' है, लेकिन तीसरा सदस्य इसके विपरीत निष्कर्ष निकालता है। इसमें प्रावधान है कि ऐसी स्थिति में जहां जांच समिति के अधिकांश सदस्यों को लगता है कि न्यायाधीश 'दोषी नहीं' है, तो 'जांच समिति ऐसे तीसरे सदस्य द्वारा संसद या किसी अन्य प्राधिकरण, निकाय या व्यक्ति को दिए गए निष्कर्ष का खुलासा नहीं करेगी'। (जोर दिया गया)

यह स्पष्ट है कि यदि 'दोषी नहीं' का निष्कर्ष बहुमत से भी है और सर्वसम्मत नहीं है, तो तीसरे सदस्य द्वारा 'दोषी' का विपरीत निष्कर्ष भी नहीं है।

संसद या किसी अन्य प्राधिकारी, निकाय या व्यक्ति को प्रकट किया जाना किसी के द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए बहुत कम कार्रवाई की गई। नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 6 में सन्निहित योजना यह है कि जहां जांच समिति का निष्कर्ष 'दोषी नहीं' है, चाहे वह सर्वसम्मत हो या जांच समिति के सदस्यों के बहुमत द्वारा, न्यायाधीश को हटाने की पूरी प्रक्रिया उस निष्कर्ष के साथ समाप्त हो जाती है जो न्यायाधीश द्वारा सभी अफवाहों को दरकिनार करते हुए दुर्व्यवहार के आरोप को शांत करता है और प्रस्ताव को संसद द्वारा विचार के लिए लेने की भी आवश्यकता नहीं है ताकि प्रक्रिया का संसदीय भाग जांच समिति द्वारा इसके प्रारंभ के लिए आवश्यक 'दोषी' होने की पूर्व शर्त के अभाव में शुरू न हो। ऐसी स्थिति में जब 'दोषी नहीं' का निष्कर्ष केवल सदस्यों के बहुमत द्वारा निकाला जाता है, तो तीसरे सदस्य द्वारा दोषी के विपरीत निष्कर्ष को संसद सहित किसी भी प्राधिकरण या व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं किया जाता है क्योंकि उन आरोपों के आधार पर संबंधित न्यायाधीश के आचरण पर सभी बहस समाप्त होनी चाहिए। योजना यह है कि मामला अंत में वहाँ समाप्त होना चाहिए, किसी को भी, यहाँ तक कि संसद को भी, 'दोषी नहीं' के निष्कर्ष पर विचार करने, बहस करने या जांच करने का अधिकार या अधिकार नहीं होना चाहिए।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

147

अतः यह स्पष्ट है कि जाँच समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है -

अधिनियम की धारा 3 (2) संबंधित न्यायाधीश को हटाने के प्रश्न पर एकमात्र और अंतिम मध्यस्थ बन जाती है जहां न्यायाधीश द्वारा निष्कर्ष पर पहुँचा गया था। समिति, चाहे सर्वसम्मत हो या बहुमत से, यह है कि न्यायाधीश 'दोषी नहीं' है। धारा 6 (1) के साथ पठित नियम 9 (6) समिति द्वारा 'दोषी नहीं' के निष्कर्ष की सीमा और व्यापक विस्तार को इंगित करता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि असंतुष्ट तीसरे सदस्य द्वारा 'दोषी' के विपरीत निष्कर्ष

बहुमत द्वारा 'दोषी नहीं' के निष्कर्ष का खुलासा संसद सहित किसी को भी नहीं किया जाएगा। विचार यह है कि यदि समिति बहुमत से भी 'दोषी नहीं' का निष्कर्ष दर्ज करती है, तो तीसरे सदस्य की विपरीत राय के बावजूद, मामला वहां समाप्त हो जाना चाहिए, किसी को भी, यहां तक कि संसद को भी, 'दोषी नहीं' के निष्कर्ष की शुद्धता या वैधता की बहुत कम जांच करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इन प्रावधानों से स्पष्ट इरादा यह है कि यदि जांच समिति यह निष्कर्ष निकालती है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार के लिए 'दोषी नहीं' है, तो उस निष्कर्ष की किसी भी आगे की जांच को संवैधानिक योजना में शामिल नहीं किया गया है, और तीसरे सदस्य द्वारा संसद में भी दोषी पाए जाने के विपरीत निष्कर्ष का खुलासा करके कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जा रहा है, इसका खुलासा 'दोषी नहीं' की बहुमत राय के साथ निषिद्ध है, जो संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोप को शांत करता है। तीसरे सदस्य द्वारा दोषी की असहमत राय को बंद करने से संबंधित न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को अनावश्यक रूप से नुकसान होगा, भले ही हटाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई हो और बहुमत ने उसे 'दोषी नहीं' पाया हो।

अधिनियम और नियमों में ये प्रावधान एक मजबूत संकेत हैं

कि संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) के अनुसार एक न्यायाधीश को हटाने के लिए संवैधानिक योजना और अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित समान दायित्व कानून न्यायिक समीक्षा द्वारा भी सभी जांच को बंद कर देता है, जहां जांच समिति सर्वसम्मति से या यहां तक कि

बहुमत यह निष्कर्ष निकालता है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार के लिए 'दोषी नहीं' है। जाहिर है, संबंधित न्यायाधीश अपने पक्ष में 'दोषी नहीं' के निष्कर्ष से व्यथित नहीं हो सकता है और यदि ऐसा निष्कर्ष सर्वसम्मत नहीं है, लेकिन बहुमत से, नियमों के नियम 9 (6) के अनुसार दोषी की असहमति वाली राय का खुलासा न करना, यहां तक कि संसद को भी, असहमति वाली राय से संबंधित न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को किसी भी संभावित नुकसान से बचाता है और इसलिए, अघोषित असहमति वाली राय से उसे कोई वैध शिकायत नहीं हो सकती है। इस कारण से, संबंधित न्यायाधीश को उस स्थिति में न्यायिक समीक्षा के बहिष्कार के खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती है।

148

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

संवैधानिक योजना इंगित करती है कि यह केवल इसके सदस्य हैं

निर्दिष्ट न्यूनतम संख्या में संयुक्त रूप से कार्य करने वाली संसद जो किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकती है, अन्य सभी तरीके

और व्यक्तियों को बाहर रखा जा रहा है। नियम 9 (6) में 'दोषी' की असहमति वाली राय का संसद में भी खुलासा न करने का प्रावधान आगे इंगित करता है कि संसद के सदस्यों सहित किसी को भी, जिन्होंने हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत प्रस्ताव का नोटिस दिया था, उस स्थिति में जांच करने का कोई अधिकार नहीं है।

जांच समिति द्वारा दर्ज किया गया 'दोषी नहीं' का निष्कर्ष, यहाँ तक कि बहुमत से भी। नियमों के नियम 9 (6) के साथ पठित अधिनियम की धारा 6 (1) इस दिशा में एक स्पष्ट संकेत है। इस प्रकार, न्यायिक समीक्षा का कुल बहिष्करण हैसंबंधित न्यायाधीश और पार लाइमेंट के सदस्यों सहित किसी का भी उदाहरण, जिसने प्रस्ताव की सूचना दी, साथ ही संसद में भी कोई बहस, यदि जांच समिति द्वारा निष्कर्ष, चाहे वह यूनानी हो या बहुमत से, यह है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार के लिए 'दोषी नहीं' है। समिति की रिपोर्ट की स्थिति में यह स्थिति है

कम से कम उस स्थिति में समिति के लिए अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत अध्यक्ष/अध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले संबंधित न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। संबंधित न्यायाधीश के पास कोई शिकायत नहीं होने के कारण, न्यायिक समीक्षा की मांग करने के उनके अधिकार का सवाल ही नहीं उठता है। हालाँकि, सवाल उस विपरीत स्थिति में इस दायित्व का है जहाँ समिति संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ 'दोषी' का निष्कर्ष निकालती है।

अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत अध्यक्ष/अध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले नियुक्त न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने के लिए समिति में किसी भी दायित्व का अभाव न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति में घोषित कानून के अनुरूप है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अध्यक्ष द्वारा पहले रिपोर्ट रखे जाने तक वैधानिक है। संसद अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) और (3) के अनुसार समिति द्वारा उसे प्रस्तुत करने पर। पहले से दिए गए कारणों के लिए रिपोर्ट में 'दोषी नहीं' पाए जाने के मामले में न्यायिक समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है, 'दोषी नहीं' का निष्कर्ष किसी भी कारण से मुक्त है।

अपनाई गई संवैधानिक योजना की जांच में, संबंधित न्यायाधीश को रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने की कोई बाध्यता नहीं है। द.

न्यायाधीश के व्यथित न होने और अन्य सभी को बाहर रखे जाने पर जब निष्कर्ष 'दोषी नहीं' होता है, तो अदालत द्वारा किसी भी प्रतिबंध को स्वचालित रूप से खारिज कर दिया जाता है, तब तक की प्रक्रिया वैधानिक होने के बावजूद। वैधानिक प्रक्रिया की घटनाओं पर इस परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए।

149

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

इस पृष्ठभूमि में, अब निर्णय के लिए पढ़ा जाने वाला प्रश्न है: क्या

निष्कर्ष यह है कि न्यायाधीश 'दोषी' है जबकि अन्य आरोपों पर निष्कर्ष यह है कि न्यायाधीश 'दोषी नहीं' है, तो प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष के संबंध में जो परिणाम सामने आएंगे, वे उसकी प्रकृति पर निर्भर करेंगे। में। दूसरे शब्दों में, जिस आरोप के संबंध में न्यायाधीश को 'दोषी नहीं' पाया जाता है, उसके परिणाम ऊपर बताए गए अनुसार होंगे -

अधिनियम की धारा 6 (1) और नियमों के नियम 9 (6) और

उन आरोपों से संबंधित निष्कासन किसी भी आगे की जांच या न्यायिक समीक्षा के अधीन हुए बिना संकेतित तरीके से समाप्त हो जाएगा जैसा कि एक न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों के संबंध में 'दोषी नहीं' के निष्कर्ष के मामले में होता है।

इस स्तर पर, सब-कॉम में पहले के निर्णय से कुछ उद्धरण

न्यायिक जवाबदेही पर समिति v. भारत संघ और अन्य, [1991] 4 एस. सी. सी. 699 को सुविधा के लिए उद्धृत किया जा सकता है। इस याचिका में उठाए गए मुद्दे पर मुख्य रूप से पहले के निर्णय के इन हिस्सों के संदर्भ में बहस की गई थी। ये उद्धरण इस प्रकार हैं:

" लेकिन भारत में संवैधानिक योजना चाहता है कि

राजनीतिक और न्यायिक का एक विवेकपूर्ण मिश्रण प्राप्त करना

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रियाएँ। हालांकि यह दिखाई देता है

पहली दृष्टि कि संविधान की कार्यवाही खंड (4) और (5) को अपनाने से संबंधित सभा

अनुच्छेद 124 इसके विपरीत और स्पष्ट रूप से इंगित करता प्रतीत होता है।

और एक न्यायिक द्वारा निर्धारण को बाहर करने का इरादा

गलत के आरोपों की शुद्धता की प्रक्रिया

अधिक सावधानीपूर्वक जाँच पर व्यवहार या अक्षमता
 यह सही निष्कर्ष नहीं है। "(पी पर पैरा 44) 731)
 " संविधान सभा में कार्यवाही, वहाँ
 इससे पहले, यह संकेत न दें कि खंड (4) को अपनाने में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1

और संविधान के अनुच्छेद 124 के (5), इरादे
 संविधान सभा की जाँच को बाहर करना था और न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता का प्रमाण
 न्यायिक निकाय द्वारा हटाने की मांग की गई। ध्यान रखें।

श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर,

जो मसौदा समिति के सदस्य थे, जबकि

श्री एम. अन्नान द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का विरोध

ऐसी जाँच के लिए तंत्र के संबंध में और सबूत एक ऐसा मामला था जिसे इसमें शामिल करने की
 आवश्यकता नहीं थी

संविधान और यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए प्रावधान किया जा सकता है

संसद द्वारा कानून द्वारा बनाया जाए।

(पी पर पैरा 46। 733)

उपलब्ध संवैधानिक विकल्पों का उल्लेख डी में किया गया था

च दूसरा जिसे बहुमत की राय में स्वीकार किया गया था

एच.

दूसरा। - चूंकि एक पता प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव

अनुच्छेद 121 और 124 (4) में निर्दिष्ट राष्ट्रपति को दुर्व्यवहार और अक्षमता को 'साबित' करने के
 आधार पर होना चाहिए, ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दुर्व्यवहार या
 अक्षमता से संबंधित आरोप पहले संसद के किसी भी सदन के बाहर किसी मंच पर साबित नहीं हो जाते।

मन में। अनुच्छेद 124 (5) के तहत कानून अनिवार्य है और जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती है और कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच के लिए प्रावधान नहीं करती है और उसके लिए प्रक्रिया को विनियमित नहीं करती है, तब तक अनुच्छेद 124 (4) के तहत न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा और संसद के सदनों को तब तक चर्चा में नहीं लाया जाएगा जब तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर कोई प्राधिकरण गलत निर्णय दर्ज नहीं करता है। व्यवहार या अक्षमता। 'सिद्ध' अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है।

(पी पर पैरा 68। 741)

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

दूसरे दृष्टिकोण की स्वीकृति इस प्रकार बताई गई थी -

" दूसरे दृश्य की अपनी सराहनीय विशेषताएं हैं।

यह विभिन्न प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ने में सक्षम बनाता है।

और, एक साथ, के पोषित मूल्यों के साथ लगातार

न्यायिक स्वतंत्रता। यह उचित मान्यता भी प्रदान करता है अनुच्छेद 124 (4) में "सिद्ध" शब्द। यह दृश्य भी होगा

संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया की एकरूपता सुनिश्चित करना।

कार्यवाही में मनमानेपन को समाप्त करने के लिए काम करें और सेवा करें

एक न्यायाधीश को हटाने के लिए। यह दोहराव से बचेगा

दोनों सदनों में जाँच और जाँच। आओ हम।

इस पर विस्तार से "।

(पी पर पैरा 71। 742)

वह गति जो बार को ऊपर उठाती है

अनुच्छेद 121 वास्तव में इस तरह के निष्कासन के लिए एक प्रस्ताव है अनुच्छेद 124 का खंड (4) सदन में पेश किया गया

कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हुई है संसद द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार

अनुच्छेद 124 का खंड (5)। इस संयोजन में, बराबर

दायित्व प्रक्रिया गलत होने के प्रमाण के बाद ही शुरू होती है। कानून के अनुसार व्यवहार या अक्षमता खंड (5) के तहत अधिनियमित, जांच के लिए तंत्र

और दुर्व्यवहार या अक्षमता के प्रमाण का पता लगाना वैधानिक होने के नाते, पूरी तरह से कानून के प्रावधानों द्वारा शासित

खंड (5) के अधीन अधिनियमित। यह लेख को भी सुसंगत बनाता है।

121. स्थिति यह होगी कि गलत का आरोप

एक न्यायाधीश का व्यवहार या अक्षमता बनाई जानी चाहिए,

बाघ और कानून के अनुसार साबित पाया गया

अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा अधिनियमित: 124 (5) बिना

संसद उस स्तर तक शामिल की जा रही है;

न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या असमर्थता साबित हुई

उस विधि द्वारा उपबंधित तरीके से, वर्तमान के लिए एक प्रस्ताव

न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करना उस आधार पर प्रत्येक सदन में आगे बढ़ाया जाएगा

अनुच्छेद 124 (4); प्रस्ताव के बाद इस तरह पेश किया जा रहा है दुर्व्यवहार या असमर्थता का प्रमाण और इसके लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत करना।

1

न्यायाधीश द्वारा अनुच्छेद 121 में निहित चर्चा पर लगी रोक हटा ली जाती है और संसद में चर्चा हो सकती है।

न्यायाधीश के आचरण के संबंध में; और आगे का परिणाम संसद के किसी सदन में प्रस्ताव के आने के आधार पर होगा। यदि, तथापि, में प्रदान की गई मशीनरी द्वारा प्राप्त निष्कर्ष

अधिनियमित कानून यह है कि आरोप साबित नहीं होता है, मामला समाप्त हो जाता है और प्रस्ताव को पेश करने का कोई अवसर नहीं होता है।

अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार।

(पी पर पैरा 74। 744)

" दूसरा विचार यह है कि अनुच्छेद 124 का खंड (4) संसद को न्यायाधीश को हटाने के लिए कार्य करने की शक्ति देता है। यदि मामला इस स्तर पर उसके समक्ष लाया जाता है तो निर्धारित तरीके से साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर; और उस स्तर तक पहुंचने के लिए संसद से उस उद्देश्य के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने वाले खंड (5) के तहत एक कानून बनाने के लिए फिर से कहा जाता है। इसका अर्थ है कि आरोप लगाना, कार्यवाही शुरू करना, जांच करना और न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता का प्रमाण।

सबूत अनिवार्य रूप से संसद के बाहर होना चाहिए और नहीं उसके भीतर। दूसरे शब्दों में, सबूत जिसमें न्यायाधीश के आचरण की चर्चा शामिल है, एक ऐसे निकाय द्वारा होना चाहिए जो अनुच्छेद 121 की सीमा से बाहर है। 'सिद्ध' शब्द हमारी कानूनी प्रणाली में समझे जाने वाले तरीके से सबूत को भी दर्शाता है, यानी न्यायिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप। नीति यह प्रतीत होती है कि दुर्व्यवहार या असमर्थता के प्रमाण तक का पूरा चरण, जो आरोप लगाए जाने पर जांच शुरू करने से शुरू होता है, अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून द्वारा शासित होता है और अनुच्छेद 121 में प्रदान किए गए प्रतिबंधों को देखते हुए, उस तंत्र को

एफ एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

संसद के बाहर रहें, न कि उसके भीतर। अगर ऐसा है तो

न ही इसमें प्रदान की गई मशीनरी पर इसका कोई नियंत्रण है अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून। संसद आती है।

तस्वीर में केवल तभी जब कोई निष्कर्ष निकलता है

मशीनरी जो कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता है

साबित कर दिया गया। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 अधिनियमित

अनुच्छेद 124 (5) के तहत ही संकेत मिलता है कि संसद

इस प्रकार अनुच्छेद 121 की एकीकृत योजना को समझा गया,

124 (4) और 124 (5)। अधिनियम की सामान्य योजना

- इस दृष्टिकोण के लिए रूप।

एच.

(पी पर पैरा 76।745)

" यदि यह सही स्थिति है, तो कानून की वैधता अनुच्छेद 124 के खंड (5) के तहत संसद द्वारा अधिनियमित और तदनुसार जांच के समापन तक का चरण उस कानून के पूरी तरह से कानून द्वारा शासित होने के साथ संसदीय प्रक्रिया के रूप में न्यायिक समीक्षा के लिए खुला अनुच्छेद 124 (4) निष्कर्ष दर्ज होने के बाद ही शुरू होता है।

कि कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता में साबित होता है

अधिनियमित कानून के अनुसार की गई जांच

खंड (5)। इस कारण से विशिष्टता पर आधारित तर्क प्रक्रिया और प्रगति पर संसद का अधिकार क्षेत्र न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत जांच और मामले में इस न्यायालय की अधिकारिता का बहिष्कार

इस स्तर पर उत्पन्न नहीं होता है। "

(पी पर पैरा 77।746)

(सु पर जोर दें

यह इंगित करता है कि इस क्षेत्र को खुला नहीं छोड़ा गया है।

जो भी एक सूचक है कि जिस स्तर पर बार अंदर है

अनुच्छेद 121 हटा दिया गया है, संसद का प्रारंभिक बिंदु है

सिद्ध; द्वारा प्रक्रिया की शुरुआत से चरण आरोप, उसका तरीका, जांच और सबूत बनाना

खंड (5) के तहत अधिनियमित कानून द्वारा कवर किए जाते हैं; मामले में सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एसयूपीपी।

आरोप साबित नहीं हुआ है, शर्त पूर्ववर्ती हैखंड (4) के तहत संसद की अधिकारिता का आह्वान करना, मौजूद नहीं है, जो 1968 के अधिनियम की धारा 6 के ऐसा कहने का कारण है; और यदि यह साबित हो जाता है, तो खंड (4) के तहत प्रक्रिया शुरू होती है, जो उसमें दिए गए परिणाम में समाप्त होती है।

(पी पर पैरा 79। 747)

" तदनुसार, योजना यह है कि पूरी प्रक्रिया

निष्कासन दो भागों में होता है-पहला खंड (5) के तहत दीक्षा से लेकर जांच तक और दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार का प्रमाण। अक्षमता एक अधिनियमित कानून द्वारा कवर की जाती है, संसद की भूमिका केवल विधायी है जैसा कि उसके द्वारा अधिनियमित सभी कानूनों में है; और दूसरा भाग खंड (4) के तहत सबूत के बाद ही संसद में है, वह प्रक्रिया खंड (5) के तहत अधिनियमित कानून के अनुसार सबूत पर ही शुरू होती है। इस प्रकार पहला भाग पूरी तरह से वैधानिक है जबकि दूसरा भाग अकेले संसदीय प्रक्रिया है।

संविधान का उद्देश्य एक स्पष्ट प्रावधान था -

पहला भाग पूरी तरह से अधिनियमित कानून द्वारा कवर किया गया है, जिसकी वैधता और उसके तहत प्रक्रिया न्यायिक के अधीन है

किसी भी राजनीतिक रंग से स्वतंत्र समीक्षा और सबूत के बाद इसका उद्देश्य एक संसदीय प्रक्रिया होना था। यह बात है।

एक न्यायाधीश को हटाने के लिए हमारी संवैधानिक योजना में किया गया संश्लेषण।

(पैरा 81 और 82 पीपी पर। 747-748)

" वास्तव में, यह अधिनियम संवैधानिक दर्शन को दर्शाता है

हटाने की प्रक्रिया के न्यायिक और राजनीतिक दोनों तत्वों का। अंतिम अधिकार इस अर्थ में संसद के पास रहता है कि भले ही अभियोग समिति इस निष्कर्ष को दर्ज करती है कि न्यायाधीश आरोपों के लिए दोषी है, फिर भी संसद को हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत नहीं करने का निर्णय लेने के लिए खुला है। लेकिन अगर समिति यह निष्कर्ष दर्ज करती है कि न्यायाधीश दोषी नहीं है, तो हटाने की प्रक्रिया में राजनीतिक तत्व के पास कोई और विकल्प नहीं है। यह कानून वास्तव में एक सभ्य कानून है जो 155 की जवाबदेही की अवधारणा का मिलान करता है।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

न्यायाधीश और न्यायिक स्वतंत्रता के मूल्य "।

(पैरा 97 पीपी पर। 751-752)

" इसलिए, विवाद बी, सी और पर हमारे निष्कर्ष

डी निम्नानुसार है:

न्यायाधीश को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया

प्रस्ताव के प्रवेश के बिंदु तक, का संविधान

समिति और कॉम द्वारा निष्कर्षों की रिकॉर्डिंग

मिट्टी, सख्ती से, के सदनों में कार्यवाही नहीं है संसद। अध्यक्ष के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है

एक्ट करें। उस बिंदु तक यह नहीं कहा जा सकता है कि मामला बना रहेगा।

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर। विषय-वस्तु बी का उत्तर दिया गया है

तदनुसार।

कानून के अनुसार दुराचार का पूर्व प्रमाण

अनुच्छेद 124 (5) के तहत बनाया गया एक पूर्ववर्ती शर्त है

चर्चा के खिलाफ अनुच्छेद 121 के तहत प्रतिबंध को हटाना

संसद में न्यायाधीशों का आचरण। अनुच्छेद 124 (4)

वास्तव में केवल इसके तहत बनाए गए कानून के साथ ही सार्थक हो जाता है

अनुच्छेद 124 (5)। इस तरह के कानून के बिना संवैधानिकन्यायाधीश को हटाने की योजना और प्रक्रिया बनी रहती है

चुनें। सामग्री सी का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

(पैरा 99 और 100 पीपी पर। 752-753)

कार्यवाही के वैधानिक होने का अर्थ है कि यह उस भाग में शासित होती है।

अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून द्वारा और यह इस अर्थ में वैधानिक है कि यह संसद के बाहर है जबकि उसके बाद 'दोषी' पाए जाने के मामले में

समिति द्वारा, कार्यवाही संसद में होती है।

अनुच्छेद के खंड (4) और (5) द्वारा इंगित संवैधानिक योजना

124 और अनुच्छेद 124 (5) के तहत संसद द्वारा अधिनियमित कानून में परिलक्षित होता है, जैसा कि न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति में संकेत दिया गया है, 'न्यायाधीशों को हटाने के लिए राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का एक विवेकपूर्ण मिश्रण' है और इसलिए, हमें पहले इन प्रावधानों को देखना चाहिए ताकि इस संदर्भ में उठाए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रदान किया जा सके। हटाने के लिए विभिन्न योजनाएं अन्य देशों में न्यायाधीश हमारे सामने समस्या का उत्तर नहीं देते हैं और वे केवल मामूली पूर्ववर्ती मूल्य के होते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों में अभ्यास और उदाहरण, मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

केवल हमारी संवैधानिक योजना में प्रक्रिया के राजनीतिक भाग के संबंध में जो जांच समिति द्वारा 'दोषी' पाए जाने के बाद शुरू होती है और रिपोर्ट अधिनियम की धारा 4 (3) के तहत संसद के समक्ष रखी जाती है। इसलिए, हमें मुख्य रूप से संविधान के प्रावधानों और अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून से अपने सामने समस्या का संकेत खोजना चाहिए। भारत में संवैधानिक योजना में 'राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रियाओं के विवेकपूर्ण मिश्रण' को देखते हुए, यदि जांच समिति यह निष्कर्ष निकालती है कि न्यायाधीश दोषी नहीं है, तो सभी के कहने पर न्यायिक समीक्षा के बहिष्कार पर किसी को भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट संकेत यह है कि संसद के सदस्यों की निर्दिष्ट न्यूनतम संख्या द्वारा निर्धारित तरीके से लगाए गए आरोप की जांच एक जांच समिति द्वारा की गई है जिसमें उच्च न्यायिक अधिकारी शामिल हैं और उनके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार के लिए 'दोषी नहीं' है, मामले को सभी अफवाहों को दरकिनार करते हुए समाप्त किया जाना चाहिए, बिना किसी को भी 'दोषी नहीं' के निष्कर्ष की शुद्धता की जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

जब समिति की रिपोर्ट में निष्कर्ष यह है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार के लिए 'दोषी' है, तो अधिनियम की धारा 6 (2) में आदेश दिया गया है कि न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को सदन द्वारा धारा 4 (2) के अनुसार प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट के साथ विचार के लिए लिया जाएगा और अधिनियम की धारा 4 (3) के तहत उसके समक्ष रखा जाएगा। नियमों के नियम 9 (1) में प्रावधान है कि जहां जांच समिति के सदस्य नहीं हैं

सर्वसम्मति से, समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उसके सदस्यों के बहुमत के निष्कर्ष के अनुसार होगी। हम पहले ही नियम 9 (6) में प्रावधान और इसके वास्तविक महत्व का संकेत दे चुके हैं जहां अधिकांश सदस्य यह निष्कर्ष निकालते हैं कि न्यायाधीश दोषी नहीं है। नियम 9 (4) अन्य स्थिति के लिए प्रावधान करता है जहां समिति के अधिकांश सदस्य यह निष्कर्ष निकालते हैं कि न्यायाधीश दुर्व्यवहार का दोषी है लेकिन तीसरा सदस्य इसके विपरीत निष्कर्ष निकालता है। उप-नियम (6) के विपरीत, जिसमें तीसरे सदस्य की असहमतिपूर्ण राय के प्रकटीकरण के खिलाफ एक स्पष्ट निषेध है, जब बहुमत की राय है कि न्यायाधीश दोषी नहीं है, तो उप-नियम (4) में यह अपेक्षा की गई है कि जहां बहुमत की राय है कि न्यायाधीश दोषी

है, तो तीसरे सदस्य द्वारा किए गए इसके विपरीत निष्कर्ष को भी जांच समिति द्वारा अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ भेजा जाएगा, जिसमें बहुमत के निष्कर्षों के अनुसार कि न्यायाधीश दोषी है, जैसा कि नियम 9 (1) द्वारा आवश्यक है। दोनों स्थितियों में यह अंतर महत्वपूर्ण है। जबकि नियम 9 (6) के अनुसार, तीसरे सदस्य की असहमत राय का खुलासा भी नहीं किया जाना है।

संसद सहित कोई भी, जहां 157 सदस्यों का बहुमत है

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

जांच समिति यह निष्कर्ष निकालती है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है, जहां बहुमत न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का 'दोषी' पाता है, इसके विपरीत तीसरे सदस्य की असहमत राय, यानी 'दोषी नहीं' को अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। नियम 9 के उप-नियम (5) में आगे कहा गया है कि उप-नियम (4) में निर्दिष्ट तीसरे सदस्य द्वारा किए गए निष्कर्ष की एक प्रमाणित प्रति भी संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। जाहिर है, आवश्यकता का उद्देश्य

साथ में प्रस्तुत किए जाने वाले तीसरे सदस्य द्वारा दोषी नहीं होने की असहमति की राय

धारा 4 (2) के तहत रिपोर्ट के साथ और आगे की आवश्यकता यह है कि इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष भी रखा जाना चाहिए, ताकि जांच समिति के अधिकांश सदस्यों द्वारा दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय संसद को यह तय करने में सक्षम बनाया जा सके कि दोषी की बहुमत की राय पर कार्य करना है या नहीं। नियम 10 (2) में जांच समिति द्वारा प्राप्त साक्ष्य की एक प्रति को रिपोर्ट के साथ प्रत्येक सदन के समक्ष रखने की आवश्यकता है। ये प्रावधान यह निर्णय लेने से पहले कि प्रस्ताव को अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार अपनाया जाना है या नहीं, न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद द्वारा विचार करने के तरीके को इंगित करते हैं क्योंकि यह केवल संसद के प्रत्येक सदन में अपेक्षित बहुमत द्वारा इस तरह से स्वीकार किए जाने वाले प्रस्ताव पर है कि दुर्व्यवहार या न्यायाधीश की क्षमता को अधिनियम की धारा 6 (3) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार साबित माना जाएगा।

संसद ने हटाने के प्रस्ताव पर विचार करते हुए

प्रस्ताव को स्वीकार करना है या नहीं, यह तय करने के लिए न्यायाधीश निर्णय लेता है

जांच समिति के तीसरे सदस्य की रिपोर्ट के साथ-साथ असहमत राय, यदि कोई हो, यदि बहुमत की राय है कि न्यायाधीश दोषी है, तो जांच समिति द्वारा प्राप्त पूरे साक्ष्य के साथ, जिसके आधार पर जांच समिति के दोषी का निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद जांच समिति के लिए अपने निष्कर्ष को प्रतिस्थापित नहीं करती है या यदि वह आवश्यक बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का

निर्णय लेती है ताकि न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव विफल हो जाए और कार्यवाही समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा करते हुए वह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लेती है क्योंकि वह अपने सामने रखी गई सामग्री के आधार पर मुद्दे पर बहस करने के बाद समिति की रिपोर्ट में दर्ज दोषी के निष्कर्ष को स्वीकार करने और उस पर कार्रवाई करने से इनकार करती है।

ये अनुच्छेद 124 (4) के तहत अधिनियमित कानून में स्पष्ट प्रावधान हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. पी. की शुद्धता सहित गुणों पर पूरा विचार किया जाएगा।

1 एस सी आर।

158

संसद के समक्ष सामग्री के आधार पर जांच समिति द्वारा किए गए 'दोषी' के निष्कर्ष पर संसद के दौरान विचार किया जाता है।

प्रक्रिया का हिस्सा एक न्यायाधीश को हटाना। के निष्कर्ष के बावजूद

' जाँच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में 'दोषी' ठहराए जाने पर, संसद अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर मामले पर पूर्ण विचार करने के बाद यह चुन सकती है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव को अपनाने के लिए जो समाप्त कर देगा

हटाने की प्रक्रिया। इस योजना के अनुरूप, जो अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून के प्रावधानों से स्पष्ट है, यह आवश्यकता है कि संसद को भी जांच समिति की रिपोर्ट में उनके खिलाफ 'दोषी' पाए जाने पर संबंधित न्यायाधीश की टिप्पणियों, यदि कोई हो, का लाभ मिलना चाहिए। जाँच समिति द्वारा प्राप्त सामग्री को पार्लिया के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने की आवश्यकता के अलावा

नियम 10 (2) के अनुसार, जांच समिति के तीसरे सदस्य द्वारा असंतुष्ट राय की नियम 9 के उप-नियम (4) और (5) में आवश्यकता को भी संसद को उपलब्ध कराया जाना एक स्पष्ट संकेत है कि जब संसद 'जांच समिति द्वारा किए गए दोषी' के निष्कर्ष वाली रिपोर्ट के साथ न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करती है, तो संसद के पास न केवल जांच समिति द्वारा प्राप्त पूरी सामग्री होनी चाहिए, जिस पर उसका 'दोषी' का निष्कर्ष आधारित है, बल्कि समिति के तीसरे सदस्य द्वारा उसी सामग्री पर दर्ज की गई दोषी नहीं होने की विपरीत राय भी होनी चाहिए। यदि संबंधित न्यायाधीश इस अवसर का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है तो वह समिति की रिपोर्ट में दर्ज दोषी के निष्कर्ष के खिलाफ अपने दृष्टिकोण का संकेत देकर इस संबंध में संसद के कार्य को सुगम बनाने की स्थिति में होगा। इसलिए, अनुच्छेद 124 (4) में उपबंधित न्यायाधीश को हटाने के लिए संवैधानिक योजना और अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून में यह निहित है कि संसद को जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए गए उसके खिलाफ 'दोषी' के निष्कर्ष पर संबंधित न्यायाधीश के दृष्टिकोण और टिप्पणियों, यदि कोई हो, का लाभ भी

मिलना चाहिए, जब संसद जांच समिति की रिपोर्ट और उसे उपलब्ध कराई गई अन्य प्रासंगिक सामग्रियों के साथ विचार के लिए न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लेती है। इस अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए और संसद को इस स्तर पर रिपोर्ट में दिए गए 'दोषी' के निष्कर्ष के खिलाफ कारण दिखाने के संबंधित न्यायाधीश के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए, अध्यक्ष/अध्यक्ष का स्पष्ट दायित्व है कि वे संबंधित न्यायाधीश को जांच समिति की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करें, जबकि इसे एस. एम. टी. के रूप में धारा 4 (3) के तहत संसद के समक्ष रखा जाए।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

159

धारा 4 (2) के तहत इसे जमा करने पर जितनी जल्दी हो सके। इस दृष्टिकोण का लाभ यह भी है कि संबंधित न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के संसदीय भाग के दौरान अपना दृष्टिकोण रखने और मतदान से पहले संसद द्वारा विचार के लिए जांच समिति द्वारा उनके खिलाफ किए गए 'दोषी' के निष्कर्ष पर टिप्पणी, यदि कोई हो, देने का अवसर प्रदान करता है।

न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर।

इसके बाद सवाल यह है कि इस अवसर की प्रकृति क्या है?

हम संबंधित न्यायाधीश को अवसर की आवश्यकता के बारे में श्री नरीमन की प्रस्तुति की शुद्धता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। इसे अपनाने या न अपनाने का निर्णय लेने के लिए न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय संसद द्वारा विचार के लिए समिति द्वारा 'दोषी' पाए जाने के खिलाफ अन्य उपलब्ध सामग्रियों के साथ अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ अपना दृष्टिकोण रखना। इसलिए, हमारी राय है कि किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए उसके तहत अधिनियमित संवैधानिक प्रावधानों और कानून द्वारा परिलक्षित और प्रतिबिंबित भारत में संवैधानिक योजना में यह निहित है कि संबंधित न्यायाधीश को ऐसा अवसर दिया जाए जब संसद समिति की रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों के साथ विचार के लिए उसे हटाने का प्रस्ताव ले। हम पहले ही अध्यक्ष/सभापति के दायित्व का संकेत दे चुके हैं कि वे इस सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] के एक भाग के रूप में धारा 4 (3) के तहत संसद के समक्ष पेश करते समय संबंधित न्यायाधीश को रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करें।

1 एस सी आर।

160

इस उद्देश्य के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो समिति की रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर संबंधित न्यायाधीश के दृष्टिकोण और टिप्पणियों, यदि कोई हो, की संसद के प्रत्येक सदन को उपलब्धता

सुनिश्चित करे, जब वह हटाने के प्रस्ताव पर विचार के लिए विचार करे। न्यायाधीश, ऐसी प्रक्रिया जो संबंधित न्यायाधीश के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करती है और विद्वान न्यायाधीश द्वारा आयोजित उच्च पद की गरिमा के अनुरूप है।

यह पहलू संबंधित न्यायाधीश के लिए उपलब्ध न्यायिक समीक्षा के अधिकार से संबंधित होने के कारण और हमारी उपरोक्त राय को ध्यान में रखते हुए कि संसदीय प्रक्रिया के दौरान न्यायाधीश को एक अवसर संवैधानिक योजना में स्पष्ट रूप से निहित है, ऑस्ट्रेलिया में न्यायमूर्ति वास्ता के मामले में दिए गए अवसर की प्रकृति का एक संक्षिप्त संदर्भ एक अनुसरणकारी उदाहरण के रूप में सहायक होगा।

न्यायमूर्ति एंजेलो वस्ता को ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद से हटाने के लिए एक कार्यवाही का सामना करना पड़ा। संसदीय (न्यायाधीश) जांच आयोग अधिनियम, 1988 के तहत एक जांच आयोग का गठन किया गया था। अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार आयोग का कार्य क्वींसलैंड की विधान सभा से पूछताछ करना और सलाह देना था कि क्या न्यायमूर्ति वस्ता के व्यवहार के कारण उन्हें पद से हटाने की आवश्यकता है। आयोग का गठन ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीशों से किया गया था। आयोग को ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति लियोनेल मर्फी के आचरण में ऑस्ट्रेलियाई संसदीय जांच आयोग की विशेष रिपोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया था।

ऑस्ट्रेलियाई की धारा 72। संविधान। आयोग ने क्वींसलैंड की विधान सभा को सलाह दी कि आयोग के सदस्यों की राय में, निर्दिष्ट मामलों के संबंध में न्यायमूर्ति वास्ता के व्यवहार के कारण उन्हें क्वींसलैंड के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद से हटाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति वेस्ता से संबंधित जांच आयोग की रिपोर्ट 30 मई, 1989 को सदन के पटल पर रखी गई थी। पृष्ठ 5146 से संसदीय बहस संख्या 16,1988-89, क्वींसलैंड की विधान सभा द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को इंगित करता है

जाँच आयोग की रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी जा रही है। 30 मई, 1989 को प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री एम. जे. अहर्न ने इस मामले में सदन का रुख किया और कहा कि न्यायमूर्ति वस्ता एस. एम. टी. होंगे।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

कारण दिखाने के लिए कि उसे क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए

जी प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने कहा:

आयुक्तों ने पाया और पार्लिया को सूचित किया कि न्यायाधीश द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया है कि उन्हें पद से हटाना आवश्यक है। उन परिस्थितियों में कोई भी जिम्मेदार पार लाइमेंट न्यायाधीश से कारण दिखाने के लिए कहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था कि उसे क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। यह पाठ्यक्रम इतिहास, परंपरा, कानून और उचित संवैधानिक अभ्यास के अनुरूप है। सरकार द्वारा

प्रस्तावित प्रस्ताव न्यायाधीश को उन मामलों की इतनी बारीकी से और सावधानी से फिर से जांच शुरू किए बिना कारण दिखाने का पूरा और उचित अवसर देगा।

आयुक्तों द्वारा जाँच (एस. आई. सी.)।

XXX

XXX

मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ

न के हितों में एक समान विवेकाधिकार अपनाना

न्यायाधीश और हमारे सामने उपस्थित होने के उसके अधिकार को पूर्वाग्रहित करना

कारण दिखाने का प्रयास करें।

(पी पर। 5147)

(जोर दिया गया)

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, न्याय मंत्री और ए

1 , श्री पी. जे. क्लॉसन ने कहा:

11XXXXXX

XXX

XXX

संसदीय न्यायाधीश आयोग की स्थापना करके,

उस निकाय को सौंप दी गई सभा कठिन और कठिन थीसाक्ष्य को सुनने, प्रश्नों का निर्धारण करने का कार्य

श्रेय और कानून, और सिफारिशें करना जो हम करते हैं

टैरी आयोग की स्थापना संसद की सहायता के लिए की गई थी, नहीं इसकी महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका को पूर्व-खाली करना।

XXX

XXX

XXX सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

162

उसे व्यक्तिगत रूप से या हमें संबोधित करने की अनुमति देने का कर्तव्य अपने कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा, क्या वह ऐसा चाहेगा; लेकिन

इस विशेषाधिकार का उद्देश्य हमारे कठिन समय में हमारी सहायता करना है।

विचार-विमर्श।

अंत में, मैं माननीय सदस्यों पर भी जोर देना चाहता हूँ।

कि इस स्तर पर ऐसा होना अनुचित होगा

आयोग के निष्कर्षों पर बहस और यह होगा

इस सदन की गरिमा और निष्पक्षता दोनों के लिए बेहतर

इससे पहले कि मामले पर पूरी तरह से बहस हो और निर्णय लिया जाए सभा द्वारा "।

(पीपी में। 5147-48)

(जोर दिया गया)

संसदीय बहसों से आगे पता चलता है कि न्यायमूर्ति वास्ता को दिया गया था

ऐसा अवसर जिसका उन्होंने लाभ उठाया। वर्तमान मामले में न्यायमूर्ति वास्ता के खिलाफ कार्यवाही का कोई और संदर्भ देना आवश्यक नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि की कार्यवाही से संबंधित सामग्री

न्यायमूर्ति वास्ता को हटाना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्हें एक अवसर दिया गया था

संसद द्वारा न्यायाधीश के रूप में उन्हें हटाए जाने के खिलाफ कारण दिखाएँ

जब उसने जाँच आयोग की उस सिफारिश पर विचार किया जिसमें उसे दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया था जिसके कारण उसे

निष्कासन; और न्यायमूर्ति वास्ता द्वारा विधानमंडल के समक्ष दिखाया गया कारण

विधानसभा को अंतिम निर्णय लेने में विचार में लिया गया था।

हम भारत में अपनाई गई संवैधानिक योजना में कोई कारण नहीं पाते हैं,

संबंधित न्यायाधीश को ऐसा अवसर नहीं दिया जाना चाहिए जब -

संसद ने उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया

के तहत गठित समिति द्वारा 'दोषी' होने का निष्कर्ष निकाला जा रहा है न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968। इस तरह का अवसर सुसंगत है और है

निष्पक्षता की आवश्यकता, किसी भी प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक विशेषता नागरिक परिणामों वाले निर्णय। हमें इस पहलू पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

हम अपनी उपरोक्त राय को ध्यान में रखते हुए यह कहना आवश्यक समझते हैं और

श्री एफ. एस. नरीमन का निवेदन जिसके साथ विद्वान महान्यायवादी

इस बात पर सहमति व्यक्त की कि इस तरह की प्रक्रिया की संसद से अपेक्षा की जाती है

के लिए और वर्तमान मामले में पालन करने की संभावना है, के लिए अवसर उत्पन्न होता है

यदि समिति एस. एम. टी. का पता लगाती है तो संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

163

विद्वान न्यायाधीश दुर्व्यवहार के 'दोषी' हैं।

यदि संवैधानिक योजना, जैसा कि हमने माना है, परिकल्पना करती है और प्रदान करती है

ताकि संबंधित न्यायाधीश को जांच समिति द्वारा दर्ज किए गए 'दोषी' के निष्कर्ष पर उसे पद से हटाने के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर संसद के समक्ष विचार के लिए रखा जा सके और संसद को 'दोषी' के निष्कर्ष को स्वीकार करने का निर्णय लेने से पहले इसे ध्यान में रखना चाहिए और अपेक्षित बहुमत से हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करके या उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करके कार्रवाई करनी चाहिए जो समाप्त हो जाएगा।

हटाने की कार्यवाही, यह इंगित करेगी कि योजना में कारण दिखाने का इस तरह का अवसर अंतिम निर्णय लेने के चरण से पहले दोषी के अनुचित निष्कर्ष के खिलाफ है, जो अकेले न्यायिक समीक्षा के अधीन होना आवश्यक है। स्पष्ट इरादा यह है कि ऐसी स्थिति में संसद को ही पहले इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए और उस स्तर पर न्यायिक समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ऐसी बात है।

क्योंकि धारा 6 (3) के अनुसार दुर्व्यवहार को साबित माना जाता है।

अधिनियम का, केवल तभी जब संसद निर्धारित तरीके से प्रस्ताव को स्वीकार करती है। संबंधित न्यायाधीश के लिए न्यायिक समीक्षा का उपाय केवल तभी उपलब्ध होता है जब उसके दुर्व्यवहार को कानून में 'साबित' माना जाता है, न कि जांच समिति द्वारा किए गए 'दोषी' के अनुचित निष्कर्ष के खिलाफ, जिस पर संसद द्वारा कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने का एक अन्य कारण यह

प्रतीत होता है कि किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही को जनहित में जल्द से जल्द समाप्त करने की आवश्यकता होती है और इसलिए, जांच समिति द्वारा 'दोषी' के अनुचित निष्कर्ष के चरण में प्रक्रिया पर कोई प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं किया जाता है। उस स्तर पर संबंधित न्यायाधीश को 'दोषी' के उस अनुचित निष्कर्ष के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर भी उस स्तर पर न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता के बिना उसके हित की पूरी तरह से रक्षा करता है, समिति के दोषी पाए जाने की संसद की जांच की गुंजाइश बहुत व्यापक है।

भले ही जांच समिति द्वारा किए गए 'दोषी' के निष्कर्ष की न्यायिक समीक्षा केवल वैधता से संबंधित सीमित आधारों पर अनुमत हो सकती है, फिर भी संसद की शक्ति इतनी सीमित नहीं होगी जब तक कि

हटाने के प्रस्ताव पर विचार करते हुए क्योंकि संसद को अपने समक्ष की पूरी सामग्री पर विचार करने पर समिति द्वारा किए गए 'दोषी' के निष्कर्ष के बावजूद प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का अधिकार है, जो इसे उस सामग्री के संभावित मूल्य में जाने में सक्षम बनाता है, जिस पर निष्कर्ष आधारित है और किसी दिए गए मामले में प्रस्ताव को अपनाने की वांछनीयता तय करने में सक्षम बनाता है। संसद प्रस्ताव पर मतदान करके निर्णय लेती है और यह सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एसयूपीपी नहीं है।

1 एस सी आर।

164

यदि वह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का विकल्प चुनता है तो अपने निर्णय के लिए कोई भी कारण देना आवश्यक है। हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि संबंधित न्यायाधीश को संसद के समक्ष अपने निष्कासन के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि संसद संवैधानिक योजना में अपने दायित्व का निर्वहन उतनी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ नहीं करेगी जितनी किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में शामिल राज्य के किसी अन्य अंग या प्राधिकरण से उम्मीद की जाती है। इस प्रक्रिया में संसद को सौंपी गई शक्ति की प्रकृति और विस्तार राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश देने के बाद तक न्यायिक समीक्षा के बहिष्करण को इंगित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है, यदि संसद आवश्यक बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार करती है। समिति द्वारा किया गया 'दोषी' का निष्कर्ष केवल संसद को अपनी प्रक्रिया शुरू करने और उस पर कार्रवाई करने की सिफारिश है जो निष्कर्ष, अधिनियम की धारा 4 के तहत रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के चरण में, सबसे अच्छा, अस्थायी और अयोग्य है।

इसके विपरीत दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप एक गंभीर विसंगति होगी। यदि समिति द्वारा किए गए 'दोषी' का निष्कर्ष अपने आप में अनुच्छेद 124 (4) के उद्देश्य के लिए 'साबित दुर्व्यवहार' के बराबर है, तो विसंगत स्थिति उत्पन्न होगी यदि संसद इसके बाद हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है। उस स्थिति में प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और 'साबित दुर्व्यवहार' के निष्कर्ष के बावजूद, न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता है। 'साबित दुर्व्यवहार' के निष्कर्ष के बावजूद हटाने की प्रक्रिया के अंत में ऐसी

तीखी स्थिति पर योजना में कभी विचार नहीं किया जा सकता था और इसलिए, एक ऐसा निर्माण जो उस बेतुकेपन का कारण बन सकता है, उसे त्याग दिया जाना चाहिए।

ऐसा होने पर, संबंधित न्यायाधीश के लिए न्यायिक समीक्षा का उपाय संसद द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने पर उनके 'साबित दुर्व्यवहार' के चरण तक पहुंचने के बाद ही होना चाहिए, जो अनिवार्य रूप से

अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने का आदेश। संबंधित न्यायाधीश द्वारा समय के बीच न्यायिक समीक्षा का सहारा लें

यह निर्माण संबंधित न्यायाधीश के हितों की रक्षा करते हुए सभी उच्च गणमान्य व्यक्तियों की भूमिका को पूर्ण प्रभाव और उचित महत्व देता है। हटाने की प्रक्रिया में शामिल होने के कारण, इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि उनमें से प्रत्येक अपनी भूमिका के महत्व और संवैधानिक योजना के तहत दायित्व की सीमा के लिए पूरी तरह से जीवित होगा। यदि, हालांकि, कोई अवैधता एसएमटी होती है।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

165

फिर भी, प्रक्रिया के अंत में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान प्रक्रिया को बीच में बताए बिना इसके सुधार की अनुमति देता है।

हम इस स्तर पर श्री कपिल की दूसरी प्रस्तुति पर विचार कर सकते हैं।

सिब्ल ने कहा कि जांच समिति संविधान के अनुच्छेद 136 के उद्देश्य के लिए एक न्यायाधिकरण है।

श्री कपिल सिब्ल ने आग्रह किया है कि समिति द्वारा गठित

अध्यक्ष/सभापति न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 (2) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 136 के उद्देश्य के लिए एक 'न्यायाधिकरण' है और चूंकि उक्त समिति के निष्कर्षों के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की जाएगी, इसलिए समिति की रिपोर्ट संबंधित न्यायाधीश को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ताकि वह उस अधिकार का प्रयोग कर सके। श्री सिब्ल ने बताया कि अपने द्वारा बनाए गए आरोपों पर अपने निष्कर्षों को दर्ज करते समय समिति न्यायिक कार्यों का प्रयोग करती है। अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों का उल्लेख यह दिखाने के लिए किया गया है कि समिति के पास अदालत के अधिकार हैं। भारत बैंक लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए। भारत बैंक लिमिटेड के कर्मचारी, [1950] एससीआर 459; दुर्गा शंकर मेहता बनाम। ठाकुर रघुराज सिंह और अन्य।, [1955] 1 एस. सी. आर. 267; भारत-चीन स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड v. जसजीत सिंह; [1964] 6 एससीआर 594 और देव सिंह और अन्य। वी. पंजीयक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य।, [1987] 2 एस. सी. आर. 1005, श्री सिब्ल ने तर्क दिया है कि

समिति यह निर्धारित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षणों को पूरा करती है कि क्या कोई प्राधिकरण अनुच्छेद 136 के उद्देश्य के लिए एक न्यायाधिकरण है। विद्वान महान्यायवादी ने श्री सिब्ल का समर्थन किया है।

इस सवाल से निपटने से पहले कि क्या समिति में

वर्तमान मामला यह निर्धारित करने के लिए परीक्षणों को पूरा करता है कि क्या कोई विशेष निकाय एक न्यायाधिकरण है, हम संक्षेप में इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें इस प्रश्न पर विचार किया गया है।

जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम लक्ष्मीचंद और ओआरएस।, [1963] सप. 1

एससीआर 242, पी. 260, जिस संदर्भ में यह अनुच्छेद 136 में आता है, 'निर्धारण' अभिव्यक्ति का अर्थ "राय का एक प्रभावी अभिव्यक्ति है जो किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा विवाद या विवाद को समाप्त करता है जिसे यह निपटान के वैध कानून के तहत प्रस्तुत किया जाता है"। यह भी माना गया कि "आदेश" अभिव्यक्ति का भी एक समान अर्थ होना चाहिए, सिवाय इसके कि इसे विवाद को समाप्त करने के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। सुलह अधिकारी, श्रमिकों के रोजगार की शर्तों को बदलने की अनुमति देते या अस्वीकार करते समय,

166 में जारी आदेश के खंड 29 द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत अनुच्छेद 136 के तहत एक न्यायाधिकरण नहीं माना गया था, हालांकि सुलह अधिकारी को न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता थी। यह देखा गया:

" उसे यह निर्धारित करने के लिए छुट्टी देने में माना जाता है कि क्या

बर्खास्तगी या आरोपमुक्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला है

कर्मचारी या रोजगार की शर्तों में परिवर्तन के लिए, और क्या नियोक्ता अनुचित उद्देश्यों से प्रेरित है; वह

यह तय नहीं करना है कि क्या निर्वहन का प्रस्तावित कदम है

या कर्मचारी की बर्खास्तगी के अधिकारों के भीतर था

नियोक्ता। उनका आदेश केवल एक वैधानिक प्रतिबंध को हटा देता है।

एक के सामान्य कानून के अधिकार पर निर्धारित कुछ संभावनाएँ
नियोक्ता की शर्तों को खारिज करना, निर्वहन करना या बदलना
पक्षों के बीच अनुबंध के अनुसार रोजगार।

सुलह अधिकारी को निस्संदेह न्यायिक रूप से कार्य करना होता है
सी. एल. के तहत एक आवेदन से निपटने में। 29 , लेकिन वह नहीं है
राज्य की न्यायिक शक्ति के साथ निवेश: वह नहीं कर सकता
इसलिए अर्थ के भीतर एक न्यायाधिकरण के रूप में माना जाए
संविधान के अनुच्छेद 136 "।

(पी पर। 262)

(जोर दिया गया)

मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड के कामगार बनाम। मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड और अन्र. ,

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एन इस दृष्टिकोण पर एक न्यायाधिकरण नहीं है कि
उक्त शक्ति का प्रयोग करने वाली उपयुक्त सरकार या प्राधिकरण की स्थिति सुलह अधिकारी से बहुत
अलग नहीं थी। जिसे जसवंत शुगर मिल्स में न्यायाधिकरण नहीं माना गया था। लिया गया विचार यह था
कि धारा 25-एन (2) के तहत किसी आदेश को अंतिम रूप देने वाला कोई प्रावधान नहीं था और ऐसी
छंटनी के लिए अनुमति देने वाले आदेश के अनुसरण में छंटनी से प्रभावित श्रमिकों के लिए यह
अनुमत था।

औद्योगिक विवाद को उठाना और ऐसे विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित करने के लिए उपयुक्त
सरकार के लिए भी खुला होना। इसमें विचार किए गए पहले के निर्णयों का उल्लेख करना अनावश्यक है।

इस न्यायालय के निर्णयों से संकेत मिलता है कि एक विचार

जिसने एक वैधानिक प्राधिकरण को 167 रखने के लिए न्यायालय के साथ वजन किया है

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

अनुच्छेद 136 के तहत न्यायाधिकरण अंतिमता या निर्णायकता और ऐसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारण की
बाध्यकारी प्रकृति है।

देव सिंह और ओआरएस में यह बताया जा सकता है। वी. पंजीयक, पंजाब

पंजाब उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के अध्याय 18-ए में नियम X (2) के तहत खंड I, जिला न्यायाधीश द्वारा लगाए गए दंड के विरुद्ध मंत्रि सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही विशुद्ध रूप से प्रशासनिक रूप से कार्य कर रही थी और एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर रही थी क्योंकि यह दो विरोधियों के बीच किसी भी विवाद या विवाद को हल नहीं कर रही थी, बल्कि केवल अधीनस्थ न्यायपालिका पर अपने नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग कर रही थी। यह देखा गया:

" कुछ मामलों में न्यायाधीशों को भी प्रशासनिक कार्य करना पड़ता है।

सक्रिय रूप से और ऐसा करने में अर्ध-न्यायिक रूप से कार्य करना पड़ सकता है

उन्हें सौंपे गए मामलों से निपटना। केवल वह जहाँ

अधिकारियों को न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है या तोकानून के प्रावधानों को या आवश्यक निहितार्थ द्वारा व्यक्त करें

कि इस तरह के प्राधिकरण के निर्णय की राशि होगी एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के लिए। जब न्यायाधीश अभ्यास में होते हैं

उनके प्रशासनिक कार्यों से उन मामलों का फैसला होता है जो वे नहीं कर सकते

कहा जा सकता है कि उनके निर्णय या तो न्यायिक या अर्ध हैं

न्यायिक निर्णय। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में,

उच्च न्यायालय अपनी प्रक्रिया का पालन कर रहा था, एक प्रो

न्यायिक मामलों में आमतौर पर अनुज्ञा का पालन नहीं किया जाता है। द हाई

न्यायालय के बीच किसी भी विवाद या विवाद का समाधान नहीं हो रहा था।

दो विरोधी। दूसरे शब्दों में, इस अपील पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई याचिका नहीं थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि

यह निर्णय लेते समय केवल अपनी नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करें अपील करें "।

(पीपी में। 1028-29)

(जोर दिया गया)

हम पहले इस प्रक्रिया में संवैधानिक योजना का संकेत दे चुके हैं

अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून के प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) द्वारा परिकल्पित न्यायाधीश को हटाने का। यह उस संवैधानिक योजना के संदर्भ में है कि इस तर्क को होना चाहिए

जाँच की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

168

इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधीश के खिलाफ उसके द्वारा बनाए गए आरोपों की जांच करते समय, समिति को न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति में कहा गया है, उक्त प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के अधीन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कार्य को लागू करने में समिति एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करती है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समिति द्वारा किए गए निर्धारण की प्रकृति की जांच करना आवश्यक है।

इस संदर्भ में, पहले बताई गई योजना को याद करना प्रासंगिक होगा। समिति द्वारा यह निर्धारण कि न्यायाधीश दोषी नहीं है

दुर्व्यवहार, अकेले अंतिम है क्योंकि यह कार्यवाही को समाप्त कर देता है। हालांकि, उस मामले में समिति द्वारा किए गए 'दोषी नहीं' के निष्कर्ष की न्यायिक समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है। यह पहलू नकारता है कि

केवल इसी कारण से न्यायाधिकरण का चरित्र। दूसरी स्थिति में जब समिति का दृढ़ संकल्प यह है कि न्यायाधीश दुर्व्यवहार का 'दोषी' है, तो वह निष्कर्ष अनुचित है जिस पर संसद द्वारा कार्रवाई की जा सकती है या नहीं भी। समिति द्वारा किए गए 'दोषी' का पता लगाना सिफारिशकर्ताओं के स्वभाव में है

संसद को अपनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए दान देना और यह अपने आप में नहीं है फलते-फूलते। इस प्रकार, समिति द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष जहाँ वह पाता है

संसद द्वारा स्वीकार किए जाने के अधीन किसी भी दुर्व्यवहार के लिए दोषी न्यायाधीश अंतिम नहीं है और इसलिए निर्णायक नहीं है।

प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए यदि समिति को पता चलता है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है। उस स्थिति में यदि

समिति को अनुच्छेद 136 के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में माना जाना चाहिए

कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करता है और यह भी अनामोलेस परिणाम की ओर ले जाएगा कि

समिति को एक न्यायाधिकरण के रूप में माना जाना चाहिए यदि वह पाता है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है, लेकिन इसे एक न्यायाधिकरण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए यदि वह पाता है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी है। समिति का चरित्र एक न्यायाधिकरण के रूप में यह उन निष्कर्षों पर निर्भर नहीं हो सकता है जो अंततः उसके द्वारा दर्ज किए जाते हैं।

न्यायाधीश के दुर्व्यवहार को अधिनियम की धारा 6 (3) के अनुसार तभी 'साबित माना जाता है' जब न्यायाधीश द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

संसद और अन्यथा नहीं। कोरामिट टी द्वारा किए गए 'दोषी' का निष्कर्ष अपने आप में उस परिणाम को नहीं लाता है। एक आवश्यक परीक्षण

निष्कर्ष की निर्धारक प्रकृति, न्यायाधिकरण की एक विशेषता का अभाव है।

देव सिंह (ऊपर) में किसी भी विवाद या विवाद की अनुपस्थिति का संकेत दिया गया है।

दो विरोधियों के बीच का संबंध इस तर्क को भी नकारता है कि एस. एम. टी.

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [VEP.MA, J.]

169

टीई अनुच्छेद 136 के उद्देश्य के लिए एक न्यायाधिकरण है।

वास्तव में, जांच समिति की रिपोर्ट जिसमें एक निष्कर्ष शामिल है

यह कि न्यायाधीश दुर्व्यवहार का दोषी है, उसे हटाने के लिए सिफारिश की प्रकृति का है, जिस पर संसद द्वारा किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटाने के प्रस्ताव पर विचार करते समय कार्रवाई की जा सकती है या नहीं, जो न्यायाधीश के निश्चित कार्यकाल को कम करने का एकमात्र तरीका है। यह कार्यकाल की सुरक्षा के लिए है और इस तरह उच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। समिति की रिपोर्ट इस तरह की होने के कारण, हमारी राय में, जांच समिति को संविधान के अनुच्छेद 136 के उद्देश्य के लिए 'न्यायाधिकरण' के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस कारण से, अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि समिति द्वारा रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित न्यायाधीश को अध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले प्रदान की जाए, जैसा कि अधिनियम की धारा 4 द्वारा नियमों में निर्धारित तरीके से आवश्यक है।

यदि समिति द्वारा न्यायाधीश को रिपोर्ट की एक प्रति की आपूर्ति

अध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून द्वारा विचार किया गया था कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत रूप से प्रावधान करते हुए कानून में किए गए प्रावधानों में क्षेत्र को खाली नहीं छोड़ा जाएगा।

अधिनियम की धारा 4 और उसके तहत बनाए गए नियम 9 में प्रतियों की संख्या सहित अपने तरीके के साथ। इस कानून में इस तरह के प्रावधान का अभाव जानबूझकर है और उस आवश्यकता के अभाव पर जोर देने के लिए एक अनजाने में चूक नहीं है जो संसद द्वारा न्यायाधीश को हटाए जाने के खिलाफ कारण दिखाने के अवसर की आवश्यकता सहित संवैधानिक योजना के हमारे द्वारा किए गए निर्माण से भी मेल खाती है।

अधिनियम और नियमों के उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और

विशेष रूप से यह तथ्य कि समिति के सदस्य द्वारा दर्ज किए गए कुछ निष्कर्षों को दी गई परिस्थितियों में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है और समिति द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी है, अंतिम और निर्णायक नहीं है, यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

कि समिति संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक न्यायाधिकरण है। इसलिए श्री सिब्लल के इस तर्क को खारिज कर दिया जाता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति को संबोधित करने के प्रस्ताव पर

संसद के प्रत्येक सदन में न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुरोध करते हुए निर्धारित तरीके से आवश्यक बहुमत द्वारा अपनाया जा रहा है, न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता को साबित माना जाता है और अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर न्यायालय की रिपोर्ट [1992] का समर्थन किया जाएगा।

1 एस सी आर।

170

फॉलो करें। सवाल यह है: क्या यह जांच समिति द्वारा किए गए 'दोषी' के निष्कर्ष को चुनौती देने के लिए संबंधित न्यायाधीश के लिए खुला है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश दिए जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश दिया जाता है? श्री नरीमन का निवेदन था कि हटाने के आदेश की न्यायिक समीक्षा को बाहर नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कह सकते। विद्वान महान्यायवादी के साथ-साथ श्री सिब्लल ने प्रस्तुत किया कि यह संभावना है कि न्यायिक समीक्षा का उपाय हो सकता है

हटाने का आदेश दिए जाने के बाद संबंधित न्यायाधीश को उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन यह बेहद संदिग्ध था। श्री सिब्लल ने संसद में यह बात कही। प्रक्रिया के हस्तक्षेप के हिस्से के रूप में, यह अधिक

संभावना नहीं थी कि राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश दिए जाने के बाद संबंधित न्यायाधीश को ऐसा उपाय उपलब्ध होगा।

विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर अपना चिंतित विचार करने पर, हम सिद्धांत या अधिकार में यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई बाधा नहीं पाते हैं कि भारत में अपनाई गई संवैधानिक योजना में, प्रक्रिया के वैधानिक भाग के दौरान जांच समिति द्वारा दर्ज किए गए दोषी के निष्कर्ष की न्यायिक समीक्षा की अनुमति नहीं है, उसके बाद अस्थायी निष्कर्ष 'साबित दुर्व्यवहार' में परिपक्व हो जाता है जो हटाने के क्रम में समाप्त होता है। 'अभी या कभी नहीं' का तर्क हमें आकर्षित नहीं करता है और जो संवैधानिक योजना में अधिक सुसंगत प्रतीत होता है वह यह है कि अनुमेय आधारों पर न्यायिक समीक्षा अभी नहीं बल्कि हटाने के आदेश के बाद प्रक्रिया के अंत में उपलब्ध है, यदि वह स्तर पहुँच गया है। हमारे विचार में, यह निष्कर्ष संबंधित न्यायाधीश के अधिकार की पर्याप्त रूप से रक्षा करता है, निर्धारित तरीके से शुरू होने के बाद प्रक्रिया के त्वरित समापन को सुनिश्चित करता है और इस दृष्टिकोण के अनुरूप है। कि यह योजना 'न्यायाधीशों को हटाने के लिए राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का एक विवेकपूर्ण मिश्रण' है। यह विद्वान न्यायाधीश के अधिकार, हित और गरिमा का संरक्षण सुनिश्चित करता है और इस प्रक्रिया में शामिल सभी संस्थानों और कार्यकर्ताओं की गरिमा के अनुरूप है। इसमें व्यस्त निकायों द्वारा प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप को भी शामिल नहीं किया गया है, जिसमें संसद के सदस्य, अध्यक्ष/अध्यक्ष और संबंधित न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायिक पदाधिकारी शामिल हैं, यदि आरोप केवल निर्धारित तरीके से लगाए जाने की अनुमति दी जाती है, तो न्यायाधीश के आचरण की जांच को उचित ठहराया जाता है।

अनुच्छेद 124 (4) के तहत राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश दिए जाने की स्थिति में, अनुमेय आधारों पर न्यायिक समीक्षा की मांग करने का संबंधित न्यायाधीश का अधिकार एसएमटी द्वारा दिए गए 'दोषी' के निष्कर्ष के आधार पर उसके खिलाफ दिए गए हटाने के आदेश को रद्द करने के लिए होगा।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. 1. [वर्मा, जे।]

171

जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट में, जो संसद द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने पर 'साबित दुर्व्यवहार' में परिपक्व हो गई थी, एक अवैधता से ग्रस्त है, जिसके परिणामस्वरूप इसे अमान्य कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हटाने के लिए संसदीय प्रक्रिया के संयोजन के लिए पूर्ववर्ती शर्तें समाप्त हो गई हैं। जिसे न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करने के प्रस्ताव पर विचार करने या उसे स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है और इसलिए राष्ट्रपति को हटाने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है।

'दोषी' के निष्कर्ष की न्यायिक समीक्षा के लिए अनुमेय आधार

एक सांविधिक प्रक्रिया द्वारा पहुँचा जाना अच्छी तरह से तय किया गया है और किसी दिए गए मामले में चुनौती का आधार इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध है या नहीं, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का सवाल

होगा। जाँच समिति के समक्ष कार्यवाही के समापन और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के बाद इस याचिका में उठाए गए सीमित प्रश्न को देखते हुए, हमारे लिए वर्तमान मामले में 'दोषी' के निष्कर्ष, यदि कोई हो, पर हमले के आधारों की जाँच करने का कोई अवसर नहीं है। वह प्रश्न वर्तमान कार्यवाही में हमारे द्वारा विचार के लिए उत्पन्न नहीं होता है और इसलिए, हमें इस पहलू पर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

हालाँकि, हम यह जोड़ सकते हैं कि संसदीय भाग का हस्तक्षेप

प्रक्रिया के संबंध में, यदि कोई दोषी पाया जाता है, जो श्री सिब्ल के अनुसार उसके बाद न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से बाहर कर देगा, एक गलतफहमी है क्योंकि केशव सिंह [1965] 1 एस. सी. आर. 413 में इस न्यायालय के फैसले के बाद उस क्षेत्र में भी सीमित न्यायिक समीक्षा संदेह में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (5) के अर्थ और दायरे पर विचार करते हुए न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति में भी इस पहलू का उल्लेख किया गया था। उसमें इस प्रकार कहा गया है:

" अनुच्छेद 124 (5) एक विशेष प्रावधान की प्रकृति का है।

न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को विनियमित करने का इरादा

अनुच्छेद 124 (4) के तहत जो सामान्य का हिस्सा नहीं है

सदन का व्यवसाय लेकिन विशेष प्रकृति का होता है व्यवसाय। यह हटाने से संबंधित पूरे क्षेत्र को शामिल करता है

एक न्यायाधीश। अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए नियम लागू नहीं होते हैं।

इस क्षेत्र में।

अनुच्छेद 124 (5) की अनुच्छेद 119 से कोई तुलना नहीं है।

अनुच्छेद 118 और 119 एक ही क्षेत्र में कार्य करते हैं।, सामान्यघर का व्यवसाय। इसलिए यह आवश्यक था कि

विशेष रूप से निर्धारित करें कि अनुच्छेद 119 के तहत बनाया गया कानून सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. के तहत बनाई गई प्रक्रिया के नियमों पर हावी होगा।

1 एस सी आर।

172

विभिन्न क्षेत्रों में अनुच्छेद में निहित प्रावधान 119 आवश्यक नहीं था और इस तरह के एक के अभाव में भी

प्रावधान, अनुच्छेद 124 (5) के तहत बनाया गया कानून ओवरराइड करेगा

अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए नियम और दोनों के लिए बाध्यकारी होंगे संसद के सदन। इस कानून का होगा उल्लंघन

अवैधता का गठन करता है और न्यायिक से मुक्त नहीं हो सकता है

अनुच्छेद 122 (1) के तहत जांच।

(पी पर पैरा 95 और 96। 751)

(जोर दिया गया)

इस स्तर पर, न्यायिक समीक्षा की प्रकृति और दायरे का एक संदर्भ

जैसा कि समान स्थितियों में समझा जाता है, सहायक होता है। प्रशासनिक कानून में (छूटा)संस्करण) एच. डब्ल्यू. आर. वेड द्वारा, "संविधान की संवैधानिक नींव" अध्याय में

'संसद की संप्रभुता' शीर्षक के तहत न्यायालयों की शक्तियों के बारे में संसद के हस्तक्षेप का प्रभाव इस प्रकार बताया गया है:

..... ऐसे कई मामले हैं जहाँ कुछ प्रशासनिक

कानून द्वारा अनुमोदित होने के लिए आदेश या विनियमन की आवश्यकता होती है।

सदनों के संकल्पों द्वारा। लेकिन यह प्रक्रिया किसी भी तरह से नहीं आदेश या विनियम की निंदा होने से बचाता है

गणना द्वारा, अति अधिकार के सिद्धांत के तहत, यदि यह नहीं है

अधिनियम के अनुसार सख्ती से। क्या चुनौती है

सदनों द्वारा अपनी मंजूरी देने से पहले या बाद में किया जाता है यह महत्वहीन है "।

(पी पर। 29)

(जोर दिया गया)

बाद में पी। 411 , वेड ने कहा है कि संवैधानिक के अनुसार

सिद्धांत रूप में, संसदीय अनुमोदन न्यायिक समीक्षा के सामान्य संचालन को प्रभावित नहीं करता है। पी. 870 न्यायिक समीक्षा पर चर्चा करते हुए, वेड इस प्रकार स्थिति का संकेत देते हैं

" जैसा कि इन मामलों से पता चलता है, न्यायिक समीक्षा किसी भी तरह से नहीं है।

इस तथ्य से बाधित है कि नियम या विनियम बनाए गए हैं

संसद के समक्ष रखा गया और पारित किया गया, फैसले के बावजूद

हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कहना है कि अनुचितता का परीक्षण एसएमटी।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

173

दोनों सदनों द्वारा, 'अदालतें बिना किसी संदेह के काम करेंगीयह विचार करने के लिए कि आदेश ठीक से था या नहीं

अंतर अधिकार होने के अर्थ में बनाया गया '।

इसलिए, स्पष्ट संकेत यह है कि केवल संसदीय अनुमोदन

किसी कार्रवाई या यहाँ तक कि किसी बाहरी प्राधिकरण द्वारा एक रिपोर्ट जब इस तरह की मंजूरी के बिना, कार्रवाई या रिपोर्ट अपने आप में अप्रभावी है, अनुमेय आधारों पर न्यायिक समीक्षा को बाहर करने का प्रभाव। वर्तमान संदर्भ में, हमारे लिए विचार करने के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या न्यायिक

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत गठित जांच समिति की रिपोर्ट में दोषी पाए जाने की समीक्षा, जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद द्वारा हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश दिए जाने के बाद न्यायिक जांच के उपलब्ध आधारों पर अनुमत होगी। यह मानने का कोई आधार नहीं है कि न्यायिक समीक्षा इस कारण से वर्जित है।

हमारी राय में, विद्वान न्यायाधीश को न्यायिक समीक्षा की उपलब्धता,

राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने के आदेश के परिणामस्वरूप आवश्यकता उत्पन्न होती है, इस तरह के आदेश के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्यापक शक्तियों को देखते हुए संदेह नहीं किया जा सकता है।

न्यायिक समीक्षा न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग है -

किसी कार्रवाई की वैधता का निर्धारण करना और उपयुक्त राहत प्रदान करना और इस तरह कानून के शासन को बनाए रखना। इस शक्ति के प्रयोग के लिए आगे किसी वैधानिक प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है जो भारत के संविधान द्वारा उच्च न्यायालयों को दी गई है। यह विचार रखने का कोई कारण नहीं है कि एक आदेश

संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए न्यायाधीश को हटाना अनुमत आधारों पर न्यायिक समीक्षा से मुक्त है -

हटाने के लिए वैधानिक प्रक्रिया के दौरान जांच समिति द्वारा किए गए दोषी के निष्कर्ष की वैधता की जांच करें जो संसदीय प्रक्रिया के प्रारंभ के लिए पूर्ववर्ती शर्त है जो बनाने में समाप्त होती है।

राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश।

रेजिना वी। इंग्लैंड के लिए सीमा आयोग, पूर्व पक्ष फुट और

अन्य, रेजिना बनाम। इंग्लैंड के लिए सीमा आयोग, एक्स पार्टी गेट्सहेड बरो काउंसिल और अन्य [1983] 1 क्यू. बी. 600, सी. ए., अपील न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. पी. पर विचार करने की अनुमति है।

1 एस सी आर।

174

क्या सीमा आयोग ने हाउस ऑफ कॉमन्स (सीटों का पुनर्वितरण) अधिनियम, 1979 की शर्तों के तहत अपनी रिपोर्ट में संसद द्वारा दिए गए अनुदेशों का उचित ढंग से पालन किया था। पी पर अपील न्यायालय का निष्कर्ष। 635 गुण-दोष की जाँच करने पर निम्नानुसार था:

' संसद ने इंडे की स्थापना को सही माना है

विचाराधीन सलाहकार निकाय, सीमा आयोग, को

इसे सलाह दें और, ऐसा करते हुए, इसने आयोग दिए हैं

सीमा की सलाह या प्रस्तावित सलाह से अदालतें आयोगों।

इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद करने का कर्तव्य सौंपा जाता है

कि संसद के निर्देशों का पालन किया जाए। यह है।

न्यायिक समीक्षा के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। सटीक रूप से न्यायालय द्वारा किसी मामले में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, यदि कोई हो

विशेष मामला उस मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

विशेष रूप से, निर्देशों की प्रकृति सहित जो संसद द्वारा मंत्री को दिए गए हैं,

संबंधित निकाय का अधिकार "।

(जोर दिया गया)

उस निष्कर्ष पर, अपील न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने आगे की अपील को खारिज कर दिया। संसद द्वारा सलाह देने के लिए स्थापित एक स्वतंत्र सलाहकार निकाय की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा इस निर्णय से स्पष्ट रूप से इंगित होती है।

नॉटिघमशायर काउंटी काउंसिल और पर्यावरण राज्य सचिव, ब्रैडफोर्ड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल शहर और पर्यावरण राज्य सचिव, [1986] 1 ए. सी. 240 में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन के मामले में न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को निर्दिष्ट किया, जो राज्य सचिव और हाउस ऑफ कॉमन्स के राजनीतिक निर्णय के लिए एक था, जो स्पष्ट रूप से इस तरह के मामले में समीक्षा की शक्ति के अस्तित्व का संकेत देता है, जबकि इसकी सीमाओं को सीमित करता है। हम वर्तमान में 175 के आसपास हैं।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

केवल ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अस्तित्व के साथ और इसकी सीमाओं की सीमा नहीं।

यह अपील न्यायालय के फैसले से भी संकेत है

रेजिना वी। महामहिम का कोषागार, पूर्व पक्ष स्मैडली, [1986] 1 क्यू. बी. 657,

ए. जिसमें प्रासंगिक परिच्छेद निम्नानुसार हैं:

इसलिए अदालतों को हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए।

अतिक्रमण से बचने की सर्वोपरि आवश्यकता है

संसद का प्रांत या, जहाँ तक यह हो सकता है

टाल दिया, यहाँ तक कि ऐसा करते हुए भी दिखाई दिया। हालांकि यह एक नहीं है

मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं उम्मीद और उम्मीद करूँगा कि संसद

से बचने की आवश्यकता के प्रति समान रूप से संवेदनशील होगा

अदालतों के प्रांत पर अतिक्रमण "। (पी पर। 666)

" मैंने कुछ हद तक इन अंतरों पर काम किया है

संसद और महामहिम के संबंधित कार्य

वर्तमान मामले में परिषद, के उद्देश्य के लिए

कुछ हद तक सीमित भूमिका का प्रदर्शन जो आवंटित की गई है

1972 के अधिनियम की धारा 1 (3) द्वारा संसद को। यह भूमिका वीटो की शक्ति के समान है। यदि यह अपनी मंजूरी रोकता है परिषद में मसौदा आदेश से, आदेश नहीं हो सकता है बनाया गया। यदि, तथापि, संसद की मंजूरी दी जाती है, परिषद में महामहिम के पास एक विवेकाधिकार बचा है कि क्या या आदेश नहीं देना। कोई संभव सवाल नहीं है अभ्यास को नियंत्रित करने या करने में सक्षम होने के लिए अदालत का वीटो की संसदीय शक्ति। लेकिन मैं देख सकता हूँ कोई कारण नहीं है कि अंतिम उल्लिखित विसंगति का अभ्यास क्यों किया जाता है

परिषद में महामहिम को दिया गया प्रस्ताव खुला नहीं होना चाहिए न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया द्वारा न्यायालयों पर हमला करना,

इस तरह के किसी भी हमले पर सख्त प्रतिबंधों के अधीन जो वेड्सबरी के रूप में जाना जाने लगा है उसके द्वारा लगाया गया सिद्धांत (एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड v. वेड्सबरी निगम, [1948] 1 के. बी. 223,229)। "

(पी पर। 672)

यह तर्क कि न्यायिक समीक्षा का उपाय नहीं होगा प्रक्रिया के संसदीय भाग के बाद विद्वान न्यायाधीश के लिए उपलब्ध च हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. पी. की रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर शुरू होती है।

1 एस सी आर।

176

जाँच समिति, भले ही यह संसदीय प्रक्रिया के हस्तक्षेप के कारण उसके खिलाफ हटाने का आदेश देने की ओर ले जाए, हमारी राय में, एक गलतफहमी पर आधारित है और इसलिए, हमें स्वीकार्य नहीं है।

हम कुछ अन्य देशों में इसी तरह की स्थितियों में न्यायिक समीक्षा के उपलब्ध संकेत का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं और दोनों का भी उल्लेख कर सकते हैं। हालस्टेड एल. रिटर बनाम में निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका, 84 सी. सी. एल. एस. 293 और एडम क्लेटन पॉवेल बनाम। जॉन डब्ल्यू. मैककॉर्मेक, 23 एल. एड। 2 डी। 491 : 395 यूएस 486। रिटर संयुक्त राज्य अमेरिका में जिला न्यायालय के न्यायाधीश थे जो थे

1936 में उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने इसके खिलाफ महाभियोग के लेखों को अपनाया

जिसे महाभियोग के उच्च न्यायालय के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के समक्ष विधिवत प्रस्तुत किया गया था। रिटर ने उस अवधि के लिए अपने वेतन की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया जिसमें महाभियोग के मामले में संयुक्त राज्य सीनेट के निष्कर्ष की समीक्षा करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का सवाल उठा।

एक न्यायाधीश। रिटर का मुकदमा खारिज कर दिया गया क्योंकि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसके पास सीनेट में आयोजित महाभियोग की कार्यवाही की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि सीनेट एकमात्र न्यायाधिकरण है जो उस निकाय को प्रस्तुत महाभियोग के लेखों का अधिकार क्षेत्र ले सकता है और इसका निर्णय अंतिम है। इस तथ्य के अलावा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून काफी प्रभावित हुआ है। रिटर के मामले के बाद से परिवर्तन, यह हमें प्रतीत होता है कि रिटर स्पष्ट रूप से अलग है क्योंकि वहाँ एक न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से राजनीतिक थी, इसका कोई हिस्सा वैधानिक नहीं था, और अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद I में कहा गया है कि सदन के पास 'महाभियोग की एकमात्र शक्ति होगी' और 'सीनेट के पास सभी महाभियोगों का परीक्षण करने की एकमात्र शक्ति होगी'। इसके विपरीत, भारत में संवैधानिक योजना, जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, यह है कि यह योजना वैधानिक और समान का एक विवेकपूर्ण मिश्रण है

दायित्व घटक।

एडम क्लेटन पॉवेल बनाम। जॉन डब्ल्यू. मैककॉर्मेक, 23 एल. एड। 2 डी 491 1969 में दिया गया एक निर्णय है। यह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया था कि

प्रतिनिधि सभा के पास संघीय संविधान में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विधिवत निर्वाचित व्यक्ति को अपनी सदस्यता से बाहर करने की कोई शक्ति नहीं है और ऐसा व्यक्ति सदन के प्रस्ताव द्वारा सदस्यता से बाहर होने पर एक घोषणात्मक निर्णय का हकदार है कि उसका

बहिष्कार गैरकानूनी था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि मामला न्यायोचित था क्योंकि प्रतिनिधि सभा के पास अपनी सदस्यता से किसी भी व्यक्ति को बाहर करने की कोई शक्ति नहीं थी जो विधिवत निर्वाचित हुआ था और जो एस. एम. टी. निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता था।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

177

संविधान, जिसमें से बहिष्करण के बीच एक अंतर है

एसएस और वहाँ से निष्कासन। यह पॉवेल में आयोजित किया गया था जब

न्यायसंगतता और 'राजनीतिक प्रश्न सिद्धांत' से संबंधित

और ":

" उत्तरदाताओं का पहला तर्क है कि यह मामला प्रस्तुत करता है

एक राजनीतिक प्रश्न क्योंकि कला के तहत। आई, एस. 5, वहाँ है

एक "लिखित रूप से प्रदर्शन योग्य संवैधानिक प्रतिबद्धता" रहा है रोकने के लिए "न्यायनिर्णायक शक्ति" के सदन को

पॉवेल की योग्यताओं का ध्यान रखें। अतः यह तर्क दिया जाता है कि

सदन और अकेले सदन के पास यह निर्धारित करने की शक्ति है कि कौन

सदस्य बनने के लिए योग्य है।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई पाठ है

सरकार के एक समन्वित विभाग के प्रति प्रतिबद्धता

बल्कि, हमें संविधान की व्याख्या करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में,

हमें पहले यह निर्धारित करना होगा कि संविधान की क्या शक्ति है।

कला के माध्यम से सदन को प्रदान करता है। आई, एस. 5, हमसे पहले

यह निर्धारित कर सकता है कि इसका अभ्यास किस हद तक, यदि कोई हो

शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

XXX

XXX

" दूसरे शब्दों में, क्या कोई "पाठगत रूप से" है

इस मुद्दे की संवैधानिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन

सरकार के राजनीतिक विभाग का समन्वय करना और क्या
 क्या इस तरह की प्रतिबद्धता का दायरा ऐसे सवाल हैं जो हमें करने चाहिए
 इस मामले में पहली बार हल करें। के लिए, जैसा कि हमने बताया
 बेकर वी। कैर, सुप्रा ", यह तय करते हुए कि क्या कोई बात है
 संविधान द्वारा किसी भी उपाय के लिए प्रतिबद्ध किया गया है
 सरकार की एक और शाखा, या क्या उस की कार्रवाई
 शाखा जो भी अधिकार दिया गया है, उससे अधिक है
 स्वयं संवैधानिक व्याख्या में एक नाजुक अभ्यास, और
 अंतिम दुभाषिया के रूप में इस न्यायालय की जिम्मेदारी है
 संविधान "।

(पैरा 22 और 23 पीपी पर। 515-517)

(जोर दिया गया)

पॉवेल का मामला कुछ स्थितियों में न्यायिक समीक्षा की उपलब्धता का संकेत देता है जहां पूरी प्रक्रिया
 सदन के भीतर है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

178

सल्लेह अबास बनाम। अब्दुल हामिद, 1988 एल. आर. सी. 25 से संबंधित एक मामला था

पद अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार के अलावा; खंड (3) दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर, शरीर
 या मन की दुर्बलता या किसी अन्य कारण से, अपने पद के कार्यों का ठीक से निर्वहन करने के लिए हटाने
 का प्रावधान करता है और खंड (4) के अनुसार एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति निर्धारित करता है जब
 ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है; और तभी न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। न्यायाधिकरण। खंड (4)
 उसमें विनिर्दिष्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति द्वारा न्यायाधिकरण की संरचना निर्धारित करता है। अनुच्छेद
 125 (3) के तहत नियुक्त न्यायाधिकरण को अपनी सिफारिशें या उसके द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट
 प्रस्तुत करने से रोकने के लिए न्यायालय की अधिकारिता पर सवाल उठा।

मलेशिया के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के संबंध में। मलेशिया के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना सर्वसम्मत विचार निम्नानुसार व्यक्त किया:

" अनुच्छेद के तहत नियुक्त न्यायाधिकरण का कार्य
125 (3) संविधान की जाँच और जाँच करना है
प्रतिनिधित्व और फिर यांग डी-पर्टुआन को रिपोर्ट करें
वह जो भी सिफारिश कर सकता है, उसे स्वीकार करें। द.

न्यायाधिकरण एक ऐसा निकाय है जो जाँच करता है और निर्णय नहीं लेता है।

यह एक संवैधानिक कार्य कर रहा है। न्यायाधिकरण

इसलिए इसे करने से रोका नहीं जाना चाहिए

संवैधानिक कार्य।

अंत में, न्यायाधिकरण के सदस्य यांग डी-पर्टुआन अगोंग के नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 125 की भाषा से यह स्पष्ट है कि यांग डी-पर्टुआन अगोंग न्यायाधिकरण की रिपोर्ट का हकदार है। रोकने के लिए

न्यायाधिकरण अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से प्रभावी है ताकि महामहिम को रिपोर्ट प्राप्त करने से रोका जा सके।

। (पी पर। 28)

(जोर दिया गया)

अनुच्छेद 125 (3) के तहत गठित न्यायाधिकरण द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।

179

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. {वर्मा, जे.]

औल बर्जर, महाभियोग: संवैधानिक समस्याएं (1973),

'न्यायिक समीक्षा' से संबंधित तृतीय अध्याय में इस प्रकार कहा गया है:

' यदि वास्तव में न्यायपालिका के बीच कोई संघर्ष है

"सभी मामलों" में अधिकार क्षेत्र और सीनेट का "एकमात्र"

के लिए शक्ति

सभी महाभियोगों का प्रयास करें ", हमारे पाठ्यक्रम को चिह्नित किया गया है

मुख्य न्यायाधीश मार्शल: " जब दो सिद्धांत आते हैं

एक-दूसरे के साथ संघर्ष, अदालत को उन दोनों को एक देना चाहिए

उचित निर्माण, ताकि दोनों को संरक्षित किया जा सके

उचित सीमा ", एल्ब्रज गेरी द्वारा पहले उद्धृत एक कैनन

पहली कांग्रेस में। हमें केवल शक्ति को पढ़ने की आवश्यकता है " पहले मामले में मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र के अनुदान के रूप में प्रयास करें।

उदाहरण के लिए, सर्वोच्च को एक अपील अछूती छोड़ते हुए अधिकारिता से अधिक कार्रवाई से न्यायालय-एक मामला "उत्पन्न हो रहा है"

संविधान के तहत।

" सीनेट द्वारा उल्लंघन की अपील के साथ "मुकदमा"

संवैधानिक सीमाओं के साथ सामंजस्य होगा

पॉवेल का मानना है कि अनुच्छेद I, S: 5 (1) प्रावधान है कि

" प्रत्येक सदन इन योग्यताओं का न्यायाधीश होगा -

इसके अपने सदस्य "अत्यधिक कार्रवाई की जांच पर रोक नहीं लगाते हैं।

अधिकारिता।

एच.

(पीपी में। 111-112)

(जोर दिया गया)

महाभियोग की कार्यवाही के संदर्भ में आगे न्यायिक समीक्षा गाना

औल बर्जर पी पर कहते हैं। 116 कि यह कभी इरादा नहीं था कि कांग्रेस

अपनी शक्तियों और आय की सीमाओं के अंतिम न्यायाधीश बनें

इस प्रकार -

" इसके लिए यह जवाब दिया जा सकता है कि बस अंतिम रूप से इस बात की गारंटी है कि न्यायपालिका सीमा से बाहर नहीं जाएगी न्यायालय का आत्म-संयम, इसलिए सीनेट को भी होना चाहिए निष्पक्ष निर्णय, और के झोंकों के अधीन नहीं गुट, और कुछ और फिर से आत्म-संयम की उम्मीद करने के लिए इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में असमर्थ रहा है निर्णय लेते समय पक्षपातपूर्ण विचारों को दूर करना मन में। सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] सहायता के संबंध में आत्म-संयम पर भरोसा किया जा सकता है।

1

न्यायपालिका क्योंकि, हैमिल्टन के शब्दों में, उनके पास "न तो बल है और न ही इच्छा, बल्कि केवल निर्णय है", और

इसलिए राजनीतिक अधिकारों के लिए सबसे कम खतरनाक थे।

संविधान "।

संवैधानिक सीमाएँ, पॉवेल बनाम। मैककॉर्मेक, हमें फिर से याद दिलाता है, न्यायिक प्रवर्तन के अधीन हैं; और मैं आग्रह करूंगा कि कांग्रेस की मनमानी इच्छा से अन्य शाखाओं को बचाने के लिए महाभियोग की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है। यह शायद ही संभव है कि "नियंत्रण और संतुलन" के प्रति इतने समर्पित फ्रेमर्स, जिन्होंने इतनी मेहनत से कांग्रेस की एक जाँच को दूसरे पर ढेर कर दिया, शक्तियों के विभाजन के तंत्रिका केंद्र में एक महत्वपूर्ण जाँच को अस्वीकार कर देंगे। वे शायद ही इस बात पर विचार किया कि जब कांग्रेस अपनी "न्यायिक" टोपी पहनती है तो उनकी बुद्धिमान सावधानियां टूटनी चाहिए, ताकि तब कांग्रेस अन्य शाखाओं को उनके आधार पर हिलाने के लिए स्वतंत्र हो। इस तरह के परिणामों को निगलने से पहले, फ्रेमर्स का इरादा कांग्रेस के उल्लंघन को रोकने का था

महाभियोग पर उनके द्वारा लगाई गई "सीमाओं" को साबित किया जाना चाहिए, आकस्मिक रूप से नहीं माना जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान "शक्ति के सभी मनमाने प्रयोग" की निंदा करता है; "हमारी संवैधानिक प्रणाली में शक्ति के लिए कोई जगह नहीं है।

मनमानी शक्ति का प्रयोग "। "प्रयास करने की एकमात्र शक्ति" उस सिद्धांत से एकमात्र की तुलना में अधिक छूट नहीं देती है।

कानून बनाने की शक्ति, जिसे किसी उद्धरण की आवश्यकता नहीं है, मनमाने कृत्यों तक विस्तारित नहीं है।

अंत में, यदि यह माना जाता है कि "प्रयास करने की एकमात्र शक्ति" ने समीक्षा से इन्सुलेशन प्रदान किया है, तो इसे मान लेना चाहिए बाद के पाँचवें संशोधन का प्रावधान है कि "किसी भी व्यक्ति" को "कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।" यदि संविधान वास्तव में महाभियोग की शक्ति पर सीमाएं लगाता है, तो उनसे परे कार्रवाई करें।

सीमाएँ अपने प्रारंभिक अर्थों में "कानून की उचित प्रक्रिया" के बिना हैं: "जब इंग्लैंड के महान बैरनों ने राजा जॉन से यह रियायत मांगी कि न तो उनके जीवन और न ही उनकी संपत्ति का निपटान ताज द्वारा किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि जैसा प्रावधान किया गया हो।

देश के कानून के अनुसार, उनका अर्थ 'देश के कानून' से था जो अंग्रेजी लोगों के प्राचीन और प्रथागत कानून थे। हमारे एसएमटी में।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.

प्रणाली "प्राचीन और प्रथागत कानूनों" का स्थान थासंविधान द्वारा लिया गया; और अनुच्छेद VI, धारा 2, स्पष्ट रूप से

संविधान को "देश का सर्वोच्च कानून" बनाता है।

संविधान द्वारा अधिकृत नहीं की गई हानिकारक कार्रवाई है

"देश के कानून" के विपरीत और इसके द्वारा निषिद्ध है

नियत प्रक्रिया खंड "। उचित प्रक्रिया है " न्यायालय द्वारा "अंदर के संरक्षण" के रूप में चित्रित किया गया

सेवाओं के भीतर एक "व्यक्ति" होना बंद नहीं होता है पाँचवाँ संशोधन; और अपराधों के लिए महाभियोग पक्ष संवैधानिक प्राधिकरण उसे अस्वीकार कर देगा

"उचित प्रक्रिया" द्वारा प्रदत्त संरक्षण। यह गुजर जाएगा

यह निष्कर्ष निकालना अजीब है कि एक नागरिक न्यायिक का आह्वान कर सकता है

" एक बीस-डॉलर के जुमाने के खिलाफ लेकिन एक के खिलाफ नहीं

असंवैधानिक महाभियोग, हटाने और स्थायी

संघीय पद धारण करने के लिए अयोग्यता। यहाँ की सुरक्षा

व्यक्ति के पृथक्करण के संरक्षण के साथ मेल खाता है

शक्तियाँ; और न्यायाधीश के रूप में हमला की गई शाखा के हित

जॉर्ज वाइथ को माना जाता है कि वे "के हित में हैं

पूरा समुदाय "। वे रुचियाँ हमें पूरा देने की सलाह देती हैं न्यायपालिका के पक्ष में मजबूत अमेरिकी पूर्वाग्रह का दायरा

की अवज्ञा में महाभियोग की समीक्षा से निरोध को अस्वीकार करेंसंवैधानिक सीमाएँ "।

(पीपी में। 118-121)

(जोर दिया गया)

अमेरिकन बार एसोसिएशन जर्नल, वॉल्यूम। 60 (जून 1974) लेख "क्या महाभियोग की न्यायिक समीक्षा आ रही है?" ज़नेक द्वारा, जिसमें पूरी तरह से पी. एस. के मामले में न्यायिक समीक्षा पर चर्चा की गई है। इसका एक अंश इस प्रकार है:

बेकर और पॉवेल ने दरवाजा खोला

यदि पॉवेल वैधता की न्यायिक समीक्षा के हकदार थे

सदन से उनके बहिष्कार के कारण, यह देखना मुश्किल है कि क्योंराष्ट्रपति न्यायिक समीक्षा की मांग नहीं कर सकता है

उसका महाभियोग और दोषसिद्धि। हर के राउल बर्जर

वार्ड, शायद कानून सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. पी. पर देश का प्रमुख प्राधिकरण।

1 एस सी आर।

182

महाभियोग, उनकी 1973 की पुस्तक, महाभियोग में समाप्त हुआ

विचार: संवैधानिक समस्याएं, कि बेकर बनाम। कैर और

पॉवेल बनाम। मैककॉर्मेक ने मिलकर न्यायपालिका के लिए रास्ता खोला महाभियोग प्रक्रिया की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कि

संवैधानिक मानकों के लिए रूप "। (पी पर। 681)

पॉवेल के प्रभाव पर टेक्सास लॉ रिव्यू, वॉल्यूम में भी विचार किया गया है।

68 , नंबर 1, नवंबर 1989, पी। 97 'महाभियोगों की न्यायिक समीक्षा' शीर्षक के तहत। इसका एक उपयोगी उद्धरण इस प्रकार है:

" पॉवेल बनाम में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। मैककॉर्मिक

यह भी इंगित करता है कि किसी की न्यायिक समीक्षा हो सकती है

उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि क्या प्रतिनिधि सभा संवेदकों ने अपवर्जन में उचित प्रक्रिया का पालन किया

एडम क्लेटन पॉवेल सदन में अपनी सीट लेते हुए

यह कोई राजनीतिक सवाल नहीं था। पॉवेल कोर्ट ने भी माना कि हालांकि कांग्रेस के पास निष्कासित करने की दोहरी शक्तियाँ हैं और

अपने सदस्यों को बाहर करने के लिए, कांग्रेस को अधिकार नहीं है

एक को बाहर करने के लिए कार्यवाही में निष्कासन मानकों को लागू करें

प्रतिनिधि।

पॉवेल का सबक यह है कि सुप्रीम कोर्ट कर सकता है

यह निर्धारित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का उपयोग करें कि क्या कांग्रेस ने इसका पालन किया

राजनीतिक निर्णय लेने के लिए उचित प्रक्रिया

संविधान द्वारा इसे लागू किया गया। इसके अलावा, पॉवेल के तहत

संघीय अदालतें तय कर सकती हैं कि क्या कांग्रेस ने चुना है

अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सही प्रक्रिया।

(पीपी में। 99-100)

(जोर दिया गया)

एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, [1981] सप। एससीसी 87 वेंकटरमैया,

जे. जैसा कि वे तब थे, यह कहने के बाद कि 'राजनीतिक प्रश्न का सिद्धांत जो संयुक्त राज्य अमेरिका में लंबे समय से क्षेत्र में था अब विस्फोट किया गया ', बेकर बनाम में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख किया गया। कैर, 369 यूएस 186: 7 एल. एड. 2 डी 663 (1962) और पॉवेल बनाम।

मैककॉमैक, 395 यूएस 486: 23 एल. एड. 2 डी. 491 (1969) के साथ-साथ आर. बर्जर की राय और फिर भारत में स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया गया:

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

" हमारे देश में, जो एक लिखित संविधान द्वारा शासित है, कई प्रश्न जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक रंग के प्रतीत होते हैं, न्यायिक प्रश्नों के चरित्र को ग्रहण करने के लिए बाध्य हैं। राजस्थान राज्य में v. भारत संघ [1978] 1 एस. सी. आर. 1, सरकार का दावा है कि अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्णय की वैधता

365 (1) संविधान का चरित्र में राजनीतिक होना उस एकमात्र आधार पर न्यायोचित नहीं था जिसे इसके द्वारा खारिज कर दिया गया था। अदालत। न्यायमूर्ति भगवती ने अपने निर्णय के दौरान उस मामले में एस. सी. आर. पृष्ठ 80-81 में इस प्रकार टिप्पणी की: (एस. सी. सी पी. 661 , पैरा

इसलिए, यह देखा जाएगा कि केवल इसलिए कि किसी प्रश्न का राजनीतिक रंग होता है, न्यायालय निराशा में अपने हाथ नहीं मोड़ सकता है और "न्यायिक हाथ बंद" घोषित नहीं कर सकता है। जब तक कोई सवाल उठता है कि क्या संविधान के तहत किसी प्राधिकरण ने अपनी शक्ति की सीमाओं के भीतर काम किया है या पार किया है। यह निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है। वास्तव में ऐसा करना उसका संवैधानिक दायित्व होगा। विशेष रूप से हाल के इतिहास के संदर्भ में स्पष्ट शब्दों में यह कहना आवश्यक है कि संविधान सर्वोच्च है, जो देश का सर्वोच्च कानून है, और इसके ऊपर या उससे परे सरकार का कोई विभाग या शाखा नहीं है। सरकार का प्रत्येक अंग, चाहे वह कार्यपालिका हो या विधायिका या न्यायपालिका, अपना अधिकार संविधान से प्राप्त करता है और उसे अपने अधिकार की सीमाओं के भीतर कार्य करना होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी उच्च पद पर हो या कोई भी उच्च अधिकारी, यह दावा नहीं कर सकता कि वह संविधान के तहत अपनी शक्ति की सीमा का एकमात्र न्यायाधीश होगा या क्या उसकी कार्रवाई संविधान द्वारा निर्धारित ऐसी शक्ति की सीमा के भीतर है। यह न्यायालय संविधान का अंतिम दुभाषिया है और इस न्यायालय को यह निर्धारित करने का नाजुक कार्य सौंपा गया है कि प्रत्येक को क्या शक्ति प्रदान की गई है

सरकार की शाखा, क्या यह सीमित है, और यदि है, तो क्या सीमाएँ हैं और क्या उस शाखा की कोई कार्रवाई ऐसी सीमाओं को पार करती है। यह इस न्यायालय का काम है कि वह संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखे और संवैधानिक नियमों को लागू करे। सीमाएँ। यही कानून के शासन का सार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

आपत्ति है कि इन पेटी में शामिल प्रश्न

राज्य केवल इस आधार पर गैर-न्यायोचित हैं कि वे

राजनीतिक चरित्र को नकारना होगा। लेकिन यह है।

स्पष्ट किया कि अदालतें जांच करने की हकदार नहीं हैं

बिना किसी सीमा के हर प्रकार का प्रश्न। अभी भी है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे प्रश्नों का एक निश्चित वर्ग,

राष्ट्रीय सुरक्षा जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है

अदालत। प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करना न्यायालय का काम है कि क्याकिसी विशेष प्रश्न पर उससे पहले बहस की जानी चाहिए या नहीं।

(पीपी पर पैरा 997 और 998। 776-777)

(जोर दिया गया)

उपरोक्त चर्चा न्यायिक स्वीकार करने की आधुनिक प्रवृत्ति का संकेत देती है।

निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर कुछ स्थितियों में समीक्षा, यहां तक कि जहां पूरी प्रक्रिया

'राजनीतिक सवालिया सिद्धांत' के बाद से राजनीतिक है, जैसा कि

पॉवेल में चूसा गया, इस पाठ्यक्रम की अनुमति देता है। ऐसे मामलों में जहां पूरी प्रक्रिया राजनीतिक है, निष्कर्ष पर अनुमेय सीमा तक न्यायिक समीक्षा

राजनीतिक प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं है। सैद्धांतिक रूप से ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि भारत में न्यायाधीश को हटाने की पूरी प्रक्रिया के अंत में न्यायिक समीक्षा, जहां यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसका राजनीतिक प्रक्रिया केवल एक हिस्सा है, को राजनीतिक प्रक्रिया सहित पूरी प्रक्रिया के समापन के बाद बाहर रखा जा सकता है। यह हमें प्रतीत होता है कि हम

जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्य प्रणालियों में कानून द्वारा प्रबलित किया जाता है।

इस याचिका की सुनवाई की शुरुआत में, विद्वान

महान्यायवादी ने बयान दिया कि अध्यक्ष हमारे निर्णय में की गई कानून की घोषणा का इंतजार करेंगे और इसका पालन करेंगे। जाँच समिति की ओर से श्री एफ. एस. नरीमन ने भी इस आशय का एक बयान दिया। विद्वान महान्यायवादी द्वारा दिए गए बयान के अनुरूप, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय भी बढ़ा दिया, ताकि सुनवाई के समापन के बाद हमें अपनी राय तैयार करने के लिए उचित समय मिल सके। यह भविष्य के लिए शुभ संकेत है।

विलिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक कानून (1936) में 'अंतिम'

सर्वोच्च न्यायालय के कार्य का मूल्यांकन इस प्रकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है:

" 185 के न्यायाधीशों के सक्रिय सहयोग के बिना

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

सुप्रीम कोर्ट, संविधान एक मृत पत्र होगा।

वे समान रूप से अपनी शक्तियों, कार्यकारी शक्तियों की रक्षा करते हैं,

और अतिक्रमणों और डिजाइनों के खिलाफ विधायी शक्तियाँ अन्य विभागों से। इसमें कोई सकारात्मक बात नहीं है

लेकिन कानून घोषित करने की नकारात्मक शक्ति, -जिसने रखा है सरकार का हमारा पूरा शक्तिशाली ताना-बाना

विनाश।

न्यायालय त्रुटिहीन नहीं रहा है। यह गलत किया है

लेता है। यह कभी-कभी जानबूझकर के विपरीत चला है और

समुदाय का बेहतर निर्णय। लेकिन अंतिम फैसला

अमेरिकी लोगों का निर्विवाद रूप से यह होगा कि उनके संघीय के हाथों में संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं

न्यायपालिका। संयुक्त राष्ट्र के पूरे इतिहास में

राज्यों, यह पर्याप्त परिणामों का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करता है

हमारी सरकार की किसी भी शाखा से। इसने कई ए को टाल दिया है

तूफान जिसने हमारी शांति को खतरे में डाल दिया है के बंधन में पूरे देश को एकजुट करने में शक्तिशाली सहायता

न्याय। विलियम विर्ट की भाषा की व्याख्या करने के लिए, "यदि न्यायपालिका को हमारी प्रणाली से हटा दिया गया था

बहुत कम मूल्य जो रहेगा। सरकार ऐसा नहीं कर सकती।

इसके बिना मौजूद है। सूर्य के बारे में बात करना उतना ही तर्कसंगत होगा।

सूर्य के बिना प्रणाली "के रूप में एक सरकार की बात करने के लिए

सर्वोच्चता के सिद्धांत के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका

सुप्रीम कोर्ट "।

(पीपी में। 114-115)

(जोर दिया गया)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका कम महत्वपूर्ण या व्यापक नहीं है

भूमिका के बाद अधिनियमित होने वाले संविधान में देखा गया

ई. यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने एक तुलनीय संवैधानिक योजना में

इतना समझने और सराहना करने के लिए।

इस संदर्भ में, आर. एस. पाठक की टिप्पणियों को याद करना भी उपयोगी है,

भारत संघ में संविधान पीठ के लिए बोलना और एक अन्य v.

उबीर सिंह (मृत) एल. आर. एस. आदि, [1989] 2 एस. सी. सी.-754 भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रकृति और ई के बारे में। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रकार कहा:

‘ सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1

यह विवादित हुआ करता था कि न्यायाधीश कानून बनाते हैं। आज, यह कोई संदेह की बात नहीं है कि नागरिकों के जीवन को नियंत्रित करने वाले कानून की एक बड़ी मात्रा और

राज्य के कार्यों को विनियमित करने से प्रवाह

उच्च न्यायालयों के निर्णय "। एक समय था, "ओब सर्व्ड लॉर्ड रीड", जब यह सुझाव देना लगभग अशोभनीय माना जाता था कि न्यायाधीश कानून बनाते हैं-वे केवल इसकी घोषणा करते हैं। लेकिन हम परियों की कहानियों में विश्वास नहीं करते हैं "। यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में, जहां संसद विधायी अंग के रूप में सर्वोच्च है और राज्य की संवैधानिक संरचना के शीर्ष पर है, न्यायिक कानून बनाने की भूमिका सीमित है।

XXX

XXX

XXX

और चेनी बनाम में थॉमस जे को छोड़ दिया। कोन को संदर्भित किया गया है

"कानून के उच्चतम रूप" के रूप में एक संसदीय कानून।

जो कानून के हर दूसरे रूप पर हावी है। लिखित संविधान के तहत स्थिति काफी अलग है जैसे कि वह जो हमें नियंत्रित करता है। भारत का संविधान, जो देश के सर्वोच्च कानून का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य के तीन अलग-अलग अंगों की परिकल्पना करता है, जिनमें से प्रत्येक के अपने अलग-अलग कार्य हैं, जिनमें से प्रत्येक राज्य का एक स्तंभ है। भारत की उच्च न्यायपालिका में मान्यता प्राप्त न्यायिक समीक्षा की सीमा शायद कानून की दुनिया में सबसे व्यापक और सबसे व्यापक है। न्यायिक शक्ति के इस प्रभावशाली विस्तार के साथ, यह केवल सही है कि भारत में उच्च न्यायालयों को भारी जिम्मेदारी के प्रति सचेत होना चाहिए

जो उन पर निर्भर करता है। यह उच्चतम न्यायालय के बारे में विशेष रूप से सच है, क्योंकि संपूर्ण न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में उसके द्वारा घोषित कानून, संविधान के अनुच्छेद 141 द्वारा, भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। (पैरा 7 पीपी पर। 765-766)

" कानून को नए आग्रहों के अनुकूल बनाने की यह आवश्यकता है।

समाज होमिसयन सूत्र की सच्चाई को घर लाता है कि "कानून का जीवन तर्क नहीं रहा है, यह अनुभव रहा है", और फिर जब उन्होंने एक अन्य अध्ययन में घोषणा की कि "कानून हमेशा जीवन से नए सिद्धांतों को अपना रहा है 187

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

एक छोर पर ", और दूसरे छोर पर पुराने को" बंद करना "।

कहा, जूलियस स्टोन ने विस्तार से बताया कि यह परिचय द्वारा है अनुभव से उभरने वाले नए अतिरिक्त-कानूनी प्रस्ताव

परिसर के रूप में सेवा करने के लिए, या अनुभव द्वारा-निर्देशित विकल्प

के बजाय प्रतिस्पर्धी कानूनी प्रस्तावों के बीच मौजूदा कानूनी, प्रस्तावों पर तर्क का संचालन, कि

कानून का विकास निर्धारित किया जाता है।

कानूनी मजबूरियों को मौजूदा कानूनी नियमों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है।

प्रस्ताव, क्योंकि वहाँ हमेशा होगा, परे

मौजूदा कानून की सीमाएँ, न्यायिक क्षेत्रों को आमंत्रित करने वाले नए क्षेत्र
जांच और न्यायिक चयन-जो अच्छी तरह से हो सकता है
मौजूदा कानूनी हठधर्मिता की वैधता को लागू करना। तलाश की जा रही है।
एक बदले हुए सामाजिक युग के लिए उत्तरदायी समाधानों में शामिल है -
न केवल कानून के प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों के बीच खोज करें, या
एक कानूनी प्रस्ताव, या तौर-तरीकों के प्रतिस्पर्धी संस्करण
एक अनिश्चितता जैसे "निष्पक्षता" या "उचित" नेस ", लेकिन निर्णय के बाहर के प्रस्तावों के बीच भी
अनुभवजन्य ज्ञान या ए. सी. के अनुरूप कानून
वर्तमान समय और स्थान के मान, के लिए प्रासंगिक
नए मानदंडों के भीतर न्याय का वितरण।
(पैरा 10 और 11 पीपी पर। 766-767)

(जोर दिया गया)

यह भारी संवैधानिक दायित्व है जिसे हमने उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा करने का प्रयास किया है जिनके भीतर अभ्यास किया जाना है।

हम पहले ही भारत में संवैधानिक योजना का संकेत दे चुके हैं और

अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून के साथ पठित अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) का वास्तविक महत्व, अर्थात् न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969, जो अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित न्यायाधीश को उनके खिलाफ कारण दिखाने का अवसर देने के प्रावधान पर विचार करते हैं।

संसद के समक्ष रिपोर्ट में 'दोषी' पाए जाने पर उसे हटाने के प्रस्ताव के साथ विचार के लिए लिया जाता है। साथ में

केशव सिंह के निर्णय को न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति में की गई घोषणा को पढ़ना होगा कि अनुच्छेद 124 (5) के तहत की गई घोषणा 188 होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है और यह संसद के दोनों सदनों के लिए बाध्यकारी होगा। इस तरह के कानून का उल्लंघन अवैध होगा और अनुच्छेद 122 (1) के तहत न्यायिक जांच से मुक्त नहीं हो सकता है। संबंधित न्यायाधीश द्वारा आदेश को अनुज्ञेय चुनौती देने का दायरा

न्यायिक समीक्षा में अनुच्छेद 124 (4) के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया निष्कासन

राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश दिए जाने के बाद इन विचारों पर विचार किया जाएगा। इस प्रश्न को कानूनी जांच की प्रक्रिया और प्रगति के संदर्भ में दर्ज करने से पहले जांच समिति की रिपोर्ट में निष्कर्ष इस मामले में सामने नहीं आते हैं और संबंधित मामले में भी संबंधित न्यायाधीश के कहने पर नहीं उठाए गए हैं। (ग) 1992 का सं. 149 श्री कृष्ण स्वामी बनाम। भारत संघ और अन्य।, जिसे दायर किया गया था और इसलिए, हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं

जांच के समापन से पहले उसकी प्रगति के दौरान न्यायिक समीक्षा के दायरे पर। उन प्रश्नों पर विचार करने से इनकार करने के कारण

संबंधित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में किसी तीसरे व्यक्ति का उदाहरण जांच हमारे द्वारा दिए गए अलग फैसले में दी गई है।

बात है। संक्षेप में, स्थिति यह है: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रत्येक न्यायाधीश को उनकी नियुक्ति के दौरान पद से हटाया नहीं जा सकता है।

कार्यकाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) में प्रदान की गई विधि को छोड़कर। अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून

124 (5) , अर्थात्, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और उसके तहत बनाए गए न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 को अनुच्छेद 124 (4) के साथ पढ़ा जाना चाहिए ताकि भारत में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम को हटाने के लिए अपनाई गई संवैधानिक योजना का पता लगाया जा सके।

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इस प्रकार अधिनियमित कानून

अनुच्छेद 124 (5) में प्रावधान है कि किसी मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ उसे पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया कोई भी आरोप केवल संसद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या से कम नहीं

अधिनियम में, अन्य सभी तरीकों को बाहर रखा गया है। प्रक्रिया की शुरुआत पर निर्धारित तरीके से, अध्यक्ष/सभापति को एक दशक तक का समय लगता है कि क्या आरोप की जांच की आवश्यकता है। यदि वह सदस्यों की निर्दिष्ट न्यूनतम संख्या द्वारा प्रस्ताव के रूप में लगाए गए आरोप पर कार्रवाई नहीं करने का विकल्प चुनता है

अध्यक्ष/सभापति, उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने पर और उसके बाद ऐसे व्यक्ति से परामर्श करना जो वह उचित समझता है, यह राय बनाता है कि न्यायाधीश के खिलाफ आरोप की जांच के लिए एक

प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, वह धारा 189 के अनुसार न्यायिक अधिकारियों की एक समिति का गठन करता है।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [वर्मा, जे.]

अधिनियम की धारा 3 (2)। यदि जांच समिति के निष्कर्ष पर

उसके द्वारा की गई जाँच एक निष्कर्ष दर्ज करती है कि न्यायाधीश 'दोषी नहीं' है, प्रक्रिया किसी के साथ समाप्त नहीं होती है, यहां तक कि संसद को भी, जाँच समिति द्वारा दर्ज 'दोषी नहीं' के निष्कर्ष पर बहुत कम सवाल पर विचार करने का अधिकार नहीं है। यदि जांच समिति द्वारा किया गया निष्कर्ष यह है कि न्यायाधीश 'दोषी' है, तो संसद समिति की रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध जानकारी के साथ न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करती है।

अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत अध्यक्ष/अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद संबंधित न्यायाधीश द्वारा उन्हें हटाने के खिलाफ दिखाए गए कारण, यदि कोई हो, सहित सामग्री, जिसके लिए उन्हें अवसर दिया जाना है। को।

प्रभावी होने पर, इस अवसर में अध्यक्ष/सभापति द्वारा संबंधित न्यायाधीश को रिपोर्ट की एक प्रति की आपूर्ति शामिल होनी चाहिए, जबकि इसे धारा 4 (3) के तहत संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। यदि संसद न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है, तो प्रक्रिया वहाँ समाप्त हो जाती है और किसी के लिए कोई चुनौती उपलब्ध नहीं होती है। यदि न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को संसद द्वारा अपेक्षित बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है, तो

संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश, तभी संबंधित न्यायाधीश के पास न्यायपालिका का उपाय होगा! हटाने के आदेश के खिलाफ अनुमेय आधारों पर उपलब्ध समीक्षा। प्रक्रिया का वैधानिक भाग, जिसके द्वारा जांच समिति द्वारा दोषी का निष्कर्ष निकाला जाता है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है जैसा कि न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति में आयोजित किया गया है, लेकिन इसमें बताए गए तरीके से, यानी केवल हटाने का आदेश दिए जाने की स्थिति में और फिर केवल पीड़ित न्यायाधीश के कहने पर। जाँच समिति चरित्र में वैधानिक है लेकिन संविधान के अनुच्छेद 136 के उद्देश्य के लिए एक न्यायाधिकरण नहीं है।

हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह बहुमत से पूरी तरह सहमत है।

न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति में राय है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का सांविधिक भाग न्यायिक समीक्षा के अधीन है। न्यायिक पुनर्विलोकन का उपाय किस स्तर और किस स्थिति में उपलब्ध होता है और किसके द्वारा इसका लाभ उठाया जा सकता है, इसका सवाल पहले के मामले में विचार के लिए नहीं उठा था और इसलिए, यह आगे का सवाल जो अब हमारे सामने आता है, उसमें नहीं उठाया गया था।

पहले के निर्णय में वास्तविक विवाद यह था कि क्या हमारी संवैधानिक योजना में एक न्यायाधीश को हटाने की पूरी प्रक्रिया संसदीय है ताकि नौवीं लोकसभा के विघटन पर विद्वान न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव में चूक के सिद्धांत को आकर्षित किया जा सके या इसका एक हिस्सा वैधानिक था जिसके लिए संसद में प्रस्तावों को रद्द करने के सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं हो सकता था।

यह इस सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. में था। 1 एस सी आर।

190

इस संदर्भ में कि उस निर्णय में बहुमत का विचार था कि प्रक्रिया वैधानिक थी जब तक कि संसद अपनी रिपोर्ट में जांच समिति द्वारा किए गए 'दोषी' के निष्कर्ष पर विचार के लिए प्रस्ताव नहीं लेती है जो संसद को प्रस्तुत की जाती है; और नौवीं लोकसभा संसदीय प्रक्रिया शुरू होने से पहले भंग हो गई थी।

उस स्तर पर प्रस्ताव के समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं है जो वैधानिक था।

उप-समिति में पहले के निर्णय को ध्यान से पढ़ने पर

न्यायिक जवाबदेही, हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि पहले के निर्णय का एकमात्र तार्किक परिणाम यह है कि संबंधित न्यायाधीश को पहले जांच समिति की रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है।

इस स्तर पर उन्हें सक्षम बनाने के लिए संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत यदि समिति ने अभिलिखित किया है तो न्यायिक समीक्षा के उपाय का लाभ उठाएँ

विद्वान न्यायाधीश के खिलाफ 'दोषी' का निर्णय। हमने पर्याप्त संकेत दिया है

कैसे निर्माण पर विद्वान न्यायाधीश के अधिकार पूरी तरह से संरक्षित हैं हमने प्रासंगिक प्रावधान किए हैं और जिस तरीके से हमने किया है

एक को हटाने के लिए भारत में अपनाई गई संवैधानिक योजना पढ़ें

अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) के अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीश। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक संवैधानिक पदाधिकारी और प्राधिकारी उतना ही चिंतित है जितना कि हमें सच्चाई का पता लगाना है।

प्रासंगिक संवैधानिक द्वारा परिकल्पित योजना का अर्थ और महत्व

और वैधानिक प्रावधान, ताकि किसी के द्वारा किसी भी विफलता को रोका जा सके

सीमाओं के उल्लंघन से बचने के लिए संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना

सीमांकित शक्तियों का। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ धूसर क्षेत्र हैं। हमारे पास है।

विद्वानों की सक्षम सहायता से उन्हें रोशन करने का प्रयास किया

वकील जो समान रूप से चिंतित हैं कि कानून स्पष्ट रूप से होना चाहिए

और इसके किसी भी संभावित दुरुपयोग से बचने के लिए सही ढंग से कहा गया है। यह सबहमारे लिए यह आवश्यक है कि हम सही संवैधानिक स्थिति की घोषणा करें

हम यह समझने में सक्षम हैं कि किसी विशिष्ट रिट को जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है या

किसी भी प्राधिकरण को निर्देश देना और राज्य के विभिन्न अंगों को छोड़ने के लिए

अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में आने वाले मामलों पर विचार करें और

'शक्तियाँ' जैसा कि पहले के मामले में किया गया था। हम उसी के अनुसार ऐसा करते हैं।

भाई कासलीवाल अपनी अलग राय में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे हमसे पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भाई के. रामास्वामी अलग थे।

किसी क्षेत्र में। के आलोक में मामले पर पुनर्विचार पर

भाई के. रामास्वामी द्वारा अपनी अलग राय में किए गए कानून की व्याख्या

हमें प्रसारित, हम पाते हैं कि काफी हद तक वह हमसे सहमत हैं, लेकिन 191 में

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [कासलिमल, जे।]

उनकी असहमति के क्षेत्र में, हम उनसे सहमत होने में अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त करते हैं।

नतीजतन, उपरोक्त कारणों से, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

निर्णय में निहित कानून को घोषित करके प्रस्तुत किया गया।

कासलिवाल, जे. मैंने अपने द्वारा तैयार किए गए निर्णय को पढ़ा है।

विद्वान भाई न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा और न्यायमूर्ति के. रामास्वामी। मैं न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा द्वारा तैयार किए गए फैसले से पूरी तरह सहमत हूँ और न्यायमूर्ति के. रामास्वामी द्वारा लिए गए विचार से सहमत होने में अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त करता हूँ। हालाँकि, उठाए गए प्रश्नों के मौलिक महत्व को देखते हुए, मैं इस मामले में भी अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा।

यह याचिका इस न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी की पत्नी ने दायर की है। मुझे इस मामले के तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

जो मेरे विद्वान भाइयों द्वारा तैयार किए गए निर्णय में पहले ही विस्तार से बताए जा चुके हैं। याचिका में उठाया गया संक्षिप्त विवाद अब नियुक्त समिति को निर्देश देने वाले रिट ऑफ मैडमस के मुद्दे से संबंधित है।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत रिपोर्ट की एक प्रति तैयार होने पर न्यायमूर्ति वी.

रामास्वामी। यह भी प्रार्थना की गई है कि समिति को एक साथ लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजने से रोकने का निर्देश दिया जाए, ताकि न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी को उक्त रिपोर्ट के सभी या किसी भी हिस्से को चुनौती देने की स्थिति में उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए उचित समय मिल सके।

उपरोक्त राहत मुख्य रूप से दो आधारों पर मांगी गई है: (1) कि इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अपने फैसले में

उप-न्यायिक जवाबदेही समिति v. भारत संघ और अन्य।, [1991] 4 एस. सी. सी. 699 पहले ही मान चुका है कि समिति के समक्ष कार्यवाही

अपनी स्थापना से लेकर संसद के समक्ष समिति की रिपोर्ट रखे जाने तक इसे संसद के बाहर की कार्यवाही माना जाता है और यह हिस्सा वैधानिक होने के कारण न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है।

(2) यदि रिपोर्ट की एक प्रति न्यायमूर्ति वी को नहीं दी जाती है। रामास्वामी से पहले कि इस तरह की रिपोर्ट को उचित कार्यवाही करने के उद्देश्य से माननीय अध्यक्ष को भेजा जाए, यह न केवल संविधान को पराजित करेगा न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी का राष्ट्रीय अधिकार, लेकिन यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

192

शुरुआत में यह ध्यान दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के पास समय नहीं है

चुनौती दी। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 या न्यायाधीश (जांच) नियम,

1969 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के अभ्यास में बनाया गया न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 की धारा 7 की उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ। इस प्रकार, हमें अधिनियम के प्रावधानों की योजना पर विचार करना है

और नियमों के साथ-साथ संविधान के प्रावधान, ताकियह तय करें कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत दी जा सकती है या नहीं।

केवल जांच और दुर्व्यवहार के प्रमाण से संबंधित है और नहीं न्यायाधीश की अपने कर्तव्यों का कुशलता से निर्वहन करने में असमर्थता के कारण

कोई भी शारीरिक या मानसिक अक्षमता। अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है -

दुर्व्यवहार की जांच और उस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि

इस तरह के प्रस्ताव के लिए सूचना कम से कम सौ सदस्यों द्वारा दी जानी चाहिए लोक सभा के सदन में दी गई ऐसी सूचना के मामले में

राज्य परिषद में दी गई सूचना के मामले में जनता और कम से कम पचास सदस्य। अध्यक्ष या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्तियों, यदि कोई हों, से परामर्श करने के बाद, जो वह उचित समझता है और ऐसी सामग्री, यदि कोई हो, जो उसके पास उपलब्ध हो, पर विचार करने के बाद या तो प्रस्ताव स्वीकार करता है या उसे स्वीकार करने से इनकार करता है। यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो प्रस्ताव इसे लंबित रखा जाएगा और निम्नलिखित तीन सदस्यों वाली एक समिति बनाई जाएगी।

इन आधारों की जांच करने के लिए सदस्यों का गठन किया जाएगा -

जिसे न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना की जाती है। इस समिति में शामिल होंगे -निम्नलिखित तीन सदस्य:

(क) मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों में से एक का चयन किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय;

(ख) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से एक का चयन किया जाएगा; और

(ग) एक व्यक्ति ऐसा होगा जो अध्यक्ष की राय में या, यथास्थिति, अध्यक्ष, एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो।

धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत समिति के लिए आवश्यक है -

न्यायाधीश के खिलाफ फ़्रैंक निश्चित आरोप जिनके आधार पर धारा 3 की उप-धारा (4) के तहत अभियोग लगाने का प्रस्ताव है, जैसे कि

उन आधारों के विवरण के साथ आरोप लगाए जाते हैं जिन पर प्रत्येक

आरोप आधारित है जिसे न्यायाधीश को सूचित किया जाएगा और उसे दिया जाएगा।

रक्षा एस. एम. टी. का लिखित बयान प्रस्तुत करने का एक उचित अवसर।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [कासलिवाल, जे.]

193

उस समय के भीतर जो समिति द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए। फिर धारा 3 की उप-धारा (8) के तहत समिति विचार कर सकती है।

न्यायाधीश का लिखित कथन, यदि कोई हो, उप-धारा (3) के तहत बनाए गए आरोपों में संशोधन करता है और ऐसे मामले में न्यायाधीश को बचाव का एक नया लिखित कथन प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा। के तहत धारा 3 की उप-धारा (9), केंद्र सरकार, एक

यदि अध्यक्ष या अध्यक्ष या दोनों, जैसा भी मामला हो, द्वारा आवश्यक हो, तो न्यायाधीश के खिलाफ मामला चलाने के लिए अधिवक्ता। अधिनियम की धारा 4 के तहत समिति को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति दी गई है।

जाँच को किसी भी नियम के अधीन बनाना। यह गवाहों की प्रतिपरीक्षा करने वाले न्यायाधीश को उचित अवसर देने का भी प्रावधान करता है। साक्ष्य देना और उसके बचाव में सुना जाना। धारा 4 की उप-धारा (2), जिससे हम सीधे तौर पर संबंधित हैं, निम्नानुसार है:

" जाँच के समापन पर समिति ने अध्यक्ष को या, जैसा भी मामला हो, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अध्यक्ष के लिए, या जहाँ समिति रही है

अध्यक्ष और सभापति द्वारा संयुक्त रूप से गठित, उन दोनों में से प्रत्येक पर अपने निष्कर्ष बताते हुए

समग्र रूप से इस तरह के अस्पष्टताओं के साथ अलग से आरोप

मामला जैसा वह उचित समझता है "।

इसके बाद अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 3 के तहत, अध्यक्ष या अध्यक्ष, या जहाँ समिति का गठन संयुक्त रूप से किया गया है

अध्यक्ष और सभापति, दोनों, यथासंभव जल्द से जल्द, क्रमशः लोक सभा और राज्य परिषद के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कराएंगे। धारा 5 एक दीवानी न्यायालय की तरह समिति की शक्तियों का प्रावधान करती है और किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को बुलाने और लागू करने और शपथ पर उसकी जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करने, जारी करने की आवश्यकता होती है।

गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षा और ऐसे अन्य मामलों के लिए आयोग जो निर्धारित किए जाएं। इसके बाद धारा 6 आती है जिसका हमारे सामने उठाए गए मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जैसा कि नीचे दिया गया है:

" 6. (1) यदि समिति की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष मिलता है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है या वह किसी असमर्थता से पीड़ित नहीं है, तो रिपोर्ट और सदन या सदनों में लंबित प्रस्ताव के संबंध में संसद के किसी भी सदन में आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

1 एस सी आर।

194

संसद की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी।

(2) यदि समिति की रिपोर्ट में कोई निष्कर्ष है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी है या किसी भी दुर्व्यवहार से पीड़ित है।

असमर्थता, तो, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट गति

धारा 3 का, आयोग की रिपोर्ट के साथ

सदन या सदन द्वारा विचार के लिए लिया जाए

संसद के वे सदन जिनमें यह लंबित है।

(3) यदि प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा स्वीकार किया जाता है

अनुच्छेद के खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार

124 या, जैसा भी मामला हो, उस खंड के अनुसार

संविधान के अनुच्छेद 218 के साथ पढ़ें, फिर, गलत

न्यायाधीश के व्यवहार या असमर्थता को माना जाएगा -

साबित किया गया है और हटाने के लिए प्रार्थना करने वाला एक पता है न्यायाधीश को निर्धारित तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।

संसद के प्रत्येक सदन द्वारा राष्ट्रपति को उसी में

सत्र जिसमें प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

धारा 7 नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। अब हम विचार करेंगे नियमों के प्रावधान जो निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक और आवश्यक हैं

न्यायाधीश के खिलाफ बनाए गए आरोप उस पर लगाए जाएंगे। नियम के तहत 6 जब न्यायाधीश उपस्थित होता है, तो वह लिखित रूप में पर्याप्तता पर आपत्ति कर सकता है

जाँच समिति, जाँच समिति के अधिकांश सदस्य आरोपों में संशोधन कर सकता है और न्यायाधीश को एक उचित अवसर दे सकता है -

बचाव का एक नया लिखित बयान प्रस्तुत करना। नियम 7 के तहत, यदि न्यायाधीश इस बात से इनकार करता है कि वह दुर्व्यवहार का दोषी है या यदि वह इनकार करता है, या छोड़ देता है, या असमर्थ है, तो अभिवचन या इच्छा है कि जांच की जानी चाहिए, तो जांच

समिति जाँच के साथ आगे बढ़ेगी। नियम 8 जाँच की अनुमति देता है।

समिति न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जांच के साथ आगे बढ़ेगी, यदि

न्यायाधीश उस पर नोटिस की सेवा के बाद उपस्थित नहीं होता है। नियम 9 से संबंधित है - जाँच समिति की रिपोर्ट और यह नियम प्रासंगिक है और

विवाद को तय करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 9. जाँच समिति की रिपोर्ट। — (1) कहाँ है मेम

जाँच समिति के सदस्य सर्वसम्मत नहीं हैं,

धारा के तहत जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

4 यह बहुमत एस. एम. टी. के निष्कर्षों के अनुसार होगा।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [कासलिवाल, जे.]

उसके सदस्यों से। (2) जाँच समिति का पीठासीन अधिकारी -

(क) इसकी रिपोर्ट को डुप्लिकेट में तैयार करने के लिए,

(ख) रिपोर्ट की प्रत्येक प्रति पर अपने हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित करें, और

(ग) उस तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, जिस दिन धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत बनाए गए आरोपों की एक प्रति न्यायाधीश को दी जाती है, या जहां न्यायाधीश के प्रकाशन की तारीख से ऐसी कोई सेवा नहीं की जाती है।

नियम 5 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूचना में प्राधिकरण ने अध्यक्ष या अध्यक्ष, जिनके द्वारा समिति का गठन किया गया था, या जहां उनके द्वारा संयुक्त रूप से समिति का गठन किया गया था, दोनों को रिपोर्ट की प्रतियां सौंपी:

बशर्ते कि अध्यक्ष या अध्यक्ष, या वे दोनों (जहां उनके द्वारा संयुक्त रूप से समिति का गठन किया गया था), पर्याप्त कारण के लिए, उस समय को बढ़ा सकते हैं जिसके भीतर जांच समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(3) जांच समिति की रिपोर्ट की एक प्रति, जिसे उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किया गया है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

किसी दुर्व्यवहार का दोषी या वह किसी क्षमता से पीड़ित है, लेकिन उसका तीसरा सदस्य इसके विपरीत निष्कर्ष निकालता है, जांच समिति का पीठासीन अधिकारी टीई, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तरीके से, ऐसे तीसरे सदस्य द्वारा किए गए निष्कर्ष को डुप्लिकेट में प्रमाणित करेगा और उसे रिपोर्ट के साथ अग्रेषित करेगा।

धारा 4 के तहत उसके द्वारा जारी किया गया। (5) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट तीसरे सदस्य द्वारा किए गए निष्कर्ष की एक प्रमाणित प्रति भी संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

196

(6) जहाँ जाँच के अधिकांश सदस्य

समिति इस आशय का निष्कर्ष निकालती है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है या वह पीड़ित नहीं है

किसी भी असमर्थता से, और उसका तीसरा सदस्य बनाता है

इसके विपरीत, जांच समिति ऐसा नहीं करेगी कि

ऐसे तीसरे सदस्य द्वारा किए गए निष्कर्ष को पार को प्रकट करें

देनदारी या किसी अन्य प्राधिकारी, निकाय या व्यक्ति के लिए।

नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य दर्ज करने का प्रावधान करता है जहां तक समिति द्वारा किसी भी गवाह की परीक्षा के लिए लागू हो सकता है। समिति द्वारा प्राप्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की एक प्रति प्रत्येक के समक्ष रखी जाएगी। अधिनियम की धारा 4 के तहत संसद के समक्ष रखी गई रिपोर्ट के साथ। नियम 11 के उप-नियम (1) में न्यायाधीश को अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और उसके द्वारा बचाव करने का अधिकार देने का प्रावधान है। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अलावा, संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 4 में यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा समर्थित भाषण और उस सदन में उपस्थित

और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा राष्ट्रपति को उसी सत्र में इस तरह के दुर्व्यवहार के आधार पर हटाने के लिए प्रस्तुत किए जाने के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पारित किया गया हो।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में सदन के 108 सदस्य

जनता ने एक प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे अध्यक्ष ने आई. डी. 1 पर स्वीकार कर लिया था और निम्नलिखित तीन व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया गया था (1) माननीय न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत, इस न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश (2) माननीय न्यायमूर्ति पी. डी. देसाई, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और (3) माननीय न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, एक प्रतिष्ठित न्यायविद की श्रेणी में इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश। लोकसभा को 13.3.1991 पर हल किया गया था। लोकसभा के नए चुनावों के बाद केंद्र सरकार ने पूर्ववर्ती लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय की सहायता के लिए कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और इस तरह न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति नामक एक निकाय द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी। उस मामले का फैसला 29 अक्टूबर, 1991 को किया गया था और उस मामले में बहुमत की राय थी कि

प्रक्रिया

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए दो चरण होते हैं। पहला चरण 197 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार जांच और सबूत का है।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [कासलिवाल, जे।]

अधिनियम के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने वाली अध्यक्ष द्वारा गठित समिति और दुर्व्यवहार के आरोप साबित होने के बाद दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरे चरण में जब प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर अनुच्छेद 121 के तहत प्रतिबंध हटा दिया जाता है और अनुच्छेद 124 (4) के तहत परिकल्पित प्रक्रिया को आकर्षित किया जाता है। पहला चरण न्यायिक समीक्षा के अधीन है, लेकिन दूसरा चरण न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है क्योंकि इसमें संसदीय प्रक्रिया शामिल है।

प्रक्रिया।

वर्तमान मामले में जांच रिपोर्ट पूरी बताई गई है।

और वर्तमान मामले में इस न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है। अधिनियम के प्रावधानों और ऊपर उल्लिखित नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि

समग्र रूप से प्रक्रिया वैधानिक प्रक्रिया के साथ-साथ संसदीय प्रक्रिया का एक समामेलन है। इस प्रक्रिया में कई नियंत्रण और सुरक्षा उपाय रखे गए हैं जहां मामला उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के एक वर्तमान न्यायाधीश के दुर्व्यवहार से संबंधित है जो उच्च संवैधानिक पदाधिकारी हैं। संसद ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम को लागू करते हुए,

1968 संविधान के लागू होने के 18 साल बाद किसी भी आरोप पर विचार करने के बारे में पूरी तरह से सचेत था।

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपित व्यवहार। यह ध्यान दिया जा सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 121 सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में संसद में किसी भी चर्चा के लिए एक स्पष्ट बाधा थी, सिवाय राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के जो न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 5 के तहत संविधान निर्माताओं ने संसद को एक अभिभाषण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को विनियमित करने और खंड (4) के तहत किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या क्षमता की जांच और प्रमाण के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार दिया। संविधान के निर्माताओं ने स्वयं संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 4 में यह निर्धारित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश के अलावा नहीं हटाया जाएगा, जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई के बहुमत से समर्थित संबोधन के बाद पारित किया गया हो। हटाने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने के मामले में

न्यायाधीश के साबित दुर्व्यवहार के आधार पर, उपरोक्त प्रावधान से पता चलता है कि संविधान के निर्माता स्वयं न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए प्रावधान करते हैं कि दुर्व्यवहार के किसी भी आरोप के मामले में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

न्यायाधीश को उसके पद से हटा नहीं दिया जाएगा सिवाय राष्ट्रपति के आदेश के जो उस प्रस्ताव के न केवल सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा समर्थित होने के बाद पारित किया गया हो, बल्कि उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा भी और उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना हो। संसद ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 को लागू करते समय दुर्व्यवहार के किसी भी आरोप की जांच और सबूत के लिए एक समिति का गठन करने के संबंध में एक समिति के गठन के लिए प्रावधान किया जिसमें केवल न्यायपालिका से संबंधित व्यक्ति शामिल थे। इतना ही नहीं समिति के सदस्यों में एक सदस्य शामिल था, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य में से चुना जाना था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से चुने जाने वाले और तीसरा एक प्रतिष्ठित न्यायविद। जांच का मामला एक उच्च न्यायिक प्राधिकरण को

सौंपा गया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल थे। इससे पता चलता है कि संसद का इरादा देश की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखना था।

न्यायपालिका और इस प्रकार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश के दुर्व्यवहार के संबंध में जांच पूरी तरह से न्यायिक निकाय को सौंपी गई थी जिसमें न्यायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति शामिल थे और किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण या न्यायपालिका के बाहर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप की अनुमति या अनुमति नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, संविधान, अधिनियम और नियमों के सभी प्रासंगिक प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जहां एक जांच समिति सर्वसम्मति से या बहुमत से न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का निष्कर्ष दर्ज करती है, तो मामला समाप्त हो जाता है और प्रस्ताव पर आगे चर्चा की आवश्यकता नहीं होती है।

संसद। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि नियम 9 के उप-नियम (6) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि जहां जांच समिति के अधिकांश सदस्य इस आशय का निष्कर्ष निकालते हैं कि न्यायाधीश किसी भी मामले में दोषी नहीं है।

दुर्व्यवहार और उसका तीसरा सदस्य कॉन को एक निष्कर्ष देता है

हालांकि, जांच समिति ऐसे तीसरे सदस्य द्वारा संसद या किसी अन्य प्राधिकरण, निकाय या व्यक्ति को दिए गए निष्कर्ष का खुलासा नहीं करेगी। यह

प्रावधान स्पष्ट रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सम्मान, गरिमा और रखरखाव को इंगित करता है और संसद सहित किसी भी प्राधिकरण, निकाय या व्यक्ति को तीसरे सदस्य द्वारा किए गए दोषी के विपरीत निष्कर्ष का खुलासा नहीं करता है और इस प्रकार संबंधित न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को बरकरार रखता है। उपरोक्त योजना के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह

विचार के लिए प्रस्ताव केवल तभी प्राप्त होता है जब उसे निष्कर्ष के साथ एक रिपोर्ट प्राप्त होती है -

एस. एम. टी. के सदस्यों के बहुमत या सर्वसम्मत राय द्वारा दर्ज किया गया दोषी।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [कासलिवाल, जे.]

199

प्रार्थना को आपस में मिलाया जाता है और याचिकाकर्ता के अनुसार और सही हैदूरे के बिना कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए कि संसद के समक्ष रिपोर्ट रखने के लिए अध्यक्ष को ऐसी रिपोर्ट भेजने से पहले जांच समिति द्वारा संबंधित न्यायाधीश को ऐसी प्रति की आपूर्ति के लिए अधिनियम या नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री सिब्ल का तर्क। यह है कि न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करना और समिति का गठन संसदीय प्रक्रिया के बाहर अध्यक्ष के वैधानिक कार्य हैं। जब तक संसद द्वारा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है और प्रस्ताव पर विचार किया जाता है, तब तक मामला संसदीय प्रक्रिया से बाहर है और कोई भी कार्रवाई जब तक कि ऐसा चरण संसदीय प्रक्रिया से बाहर नहीं है, न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान न्यायाधीश के प्रतिकूल निष्कर्षों पर सवाल उठाने का अधिकार है समिति द्वारा अभिलिखित दुर्व्यवहार, यदि कोई हो और यह केवल तभी किया जा सकता है जब रिपोर्ट की प्रति विद्वान न्यायाधीश को दी जाए और उसके बाद न्यायिक समीक्षा द्वारा इसे चुनौती देने के अधिकार का लाभ उठाने के लिए उचित समय दिया जाए। यह भी तर्क दिया गया है कि अधिनियम और नियमों में अध्यक्ष के लिए रिपोर्ट की एक प्रति विद्वान न्यायाधीश को प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। एक बार संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर एक रिपोर्ट रखे जाने के बाद, यह विशेष रूप से संसद के अधिकार क्षेत्र में है और यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि प्रस्ताव पर विचार करने के संबंध में संसद कौन सी प्रक्रिया अपना सकती है। इस मूल्यवान अधिकार को न तो लिया जा सकता है और न ही व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा निरर्थक बनाया जा सकता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

200

विद्वान महान्यायवादी श्री जी. रामास्वामी ने तर्क दिया कि समिति अध्यक्ष के अधीनस्थ प्राधिकरण की प्रकृति में है। द.

विद्वान न्यायाधीश समिति द्वारा रिपोर्ट में दर्ज प्रतिकूल निष्कर्षों, यदि कोई हों, को चुनौती देने का हकदार है, इससे पहले कि उन्हें विचार के लिए लिया जाए। संसद द्वारा। यह तभी किया जा सकता है जब ऐसी रिपोर्ट न्यायिक समीक्षा की मांग के लिए विद्वान न्यायाधीश को उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए नहीं है।

यह माननीय न्यायालय यह तय करेगा कि प्रस्ताव पर मतदान करने के उद्देश्य से संसद किस प्रक्रिया का पालन करेगी और न ही यह न्यायालय किसी भी तरह से संसदीय प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है। यह केवल संसद के लिए है कि

यह तय करें कि प्रस्ताव को कैसे निपटाया जाएगा और मामले में प्रस्ताव की एक प्रति

जांच रिपोर्ट इस स्तर पर विद्वान न्यायाधीश को मांग के लिए प्रस्तुत नहीं की जाती है।

न्यायिक समीक्षा, यह प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ होगा कि किसी व्यक्ति की निंदा न की जाए।

जहाँ तक न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति के मामले में निर्धारित कानून के प्रस्तावों का संबंध है, मैं इस निर्णय पर भार डालना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि इस पर बहुत विस्तार से विचार किया गया है।

न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा दिया गया निर्णय यह कहने के लिए पर्याप्त है कि उपरोक्त मामले में वर्तमान मामले में उठाया गया विवाद विवाद में नहीं था और न्यायालय ने उस मामले में

मामला प्रस्ताव का मनोरंजन करने के चरण से संबंधित था सदन के विचार और इस तरह के प्रस्ताव के भविष्य के लिए अध्यक्ष

लोकसभा का विघटन।

अब हम वर्तमान मामले में सीधे उठाए गए प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या इस न्यायालय को राष्ट्रपति को निर्देश देना चाहिए।

समिति रिपोर्ट की प्रति विद्वान न्यायाधीश को पहले प्रस्तुत करेगी

उसी को अध्यक्ष को भेजना और आगे निर्देश देना

एक उचित अवधि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को रोकें ताकि

विद्वान न्यायाधीश को चुनौती के उपाय का लाभ उठाने या न लेने के लिए समय मिल सकता है

न्यायिक समीक्षा के माध्यम से रिपोर्ट में प्रतिकूल निष्कर्षों को शामिल करना। इस प्रश्न का निर्णय लेने के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि किस सिद्धांत के तहत

जांच रिपोर्ट की प्रति देने के लिए अधिनियम या नियमों में अध्यक्ष को भेजने से पहले संबंधित न्यायाधीश। यह स्थिति समान है

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किया गया। अगर हम पूर्व एस. एम. टी.।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. एल [कासलिवाल, जे.]

201

अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना के विपरीत निष्कर्ष निकलता है। अधिनियम की धारा 4 (2) में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि जांच के समापन पर समिति अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उप-धारा (3) के तहत अध्यक्ष वर्तमान मामले में जितनी जल्दी हो सके, रिपोर्ट को लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत कराएगा। इसके अलावा नियम 9 (2) (सी) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जांच समिति का पीठासीन अधिकारी

उस तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट जिस पर एक प्रति

धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत बनाए गए आरोप न्यायाधीश पर लगाए जाते हैं, या जहां नियम 5 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूचना के प्रकाशन की तारीख से ऐसी कोई सेवा नहीं की जाती है। परंतुक के तहत, अध्यक्ष को पर्याप्त कारण के लिए समय बढ़ाने का अधिकार है। इस प्रकार, प्रावधानों की उपरोक्त योजना का इरादा एक त्वरित निपटान है।

यदि मामला नियम 9 (6) के दायरे में नहीं आता है, तो जांच समिति ऐसे तीसरे सदस्य द्वारा संसद या किसी अन्य प्राधिकरण, निकाय या व्यक्ति को दिए गए निष्कर्ष का खुलासा नहीं करेगी।

अब जांच किए जाने वाला दूसरा पहलू प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन है, यदि रिपोर्ट की प्रति न्यायाधीश को नहीं दी जाती है।

न्यायिक समीक्षा की मांग के लिए संबंधित है और यह प्रस्तुत करने का मुख्य आधार है जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से पूरी इमारत बनाई गई है। जहाँ तक ऑडियो अल्टरम पाटेंम का सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति की बिना सुने निंदा नहीं की जा सकती है, मेरे विचार में वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। कानून की वर्तमान योजना में संबंधित न्यायाधीश को सुनने का अधिकार केवल दो प्राधिकरणों के समक्ष उत्पन्न हो सकता है। एक जाँच समिति के समक्ष और दूसरा संसद के समक्ष। जहाँ तक समिति के समक्ष सुनवाई के अधिकार का संबंध है, वहाँ पर्याप्त अवसर है अधिनियम और नियमों के प्रावधानों में दिया गया है। दुर्व्यवहार की पूरी जांच संबंधित न्यायाधीश को नोटिस दिए जाने के बाद की जाती है। उन आधारों के बयान के साथ बनाए गए आरोप जिनके आधार पर ऐसा प्रत्येक आरोप आधारित है, न्यायाधीश को सूचित किया जाता है और उसे बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाता है। समिति न्यायाधीश के लिखित बयान पर विचार करने के बाद आरोपों में संशोधन कर सकती है और उसके बाद न्यायाधीश को फिर से बचाव का एक नया लिखित बयान प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाता है। जाँच करने में समिति को गवाहों की जिरह करने वाले न्यायाधीश को, साक्ष्य प्रस्तुत करने और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] का सदस्य होने का एक उचित अवसर देने की आवश्यकता होती है।

1 एस सी आर।

202

अपने बचाव में सुना। न्यायाधीश की याचिका दर्ज की जाती है, जिसका साक्ष्य

जाँच समिति द्वारा जाँच किए गए प्रत्येक गवाह को लिखित रूप में हटा लिया जाता है।

न्यायाधीश को परामर्श करने का अधिकार भी दिया जाता है, और एक कानूनी व्यक्ति द्वारा बचाव किया जाता है।

जांच समिति का संबंध है, उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट हैं। यह दर्शाता है कि न्यायाधीश को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है

वर्तमान मामला। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद अपना रास्ता अपनाने के लिए स्वतंत्र है प्रस्ताव पर विचार करते समय प्रक्रिया, लेकिन केवल वही नहीं हो सकता है

की रिपोर्ट के खिलाफ न्यायिक समीक्षा की मांग के लिए एक आधार के रूप में पक्षपाती

समिति। इससे पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं देने का सवाल

विद्वान न्यायाधीश के खिलाफ संसद द्वारा कोई कार्रवाई केवल की जा सकती है

संसद द्वारा न्यायाधीश के खिलाफ कोई निर्णय लिए जाने के बाद उत्पन्न होता है। द.

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन, यदि कोई हो, की जांच नहीं की जा सकती है अलगाव, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नहीं।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन पर आधारित तर्क हो सकता है इस धारणा पर विचार किया गया कि संसद एक प्रक्रिया अपना सकती है

जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है। विद्वान वकील

तर्कों के बाद के चरण में जनरल के साथ-साथ वकील समिति इस बात पर सहमत थी कि संसद

अंतिम निर्णय लेने से पहले विद्वान न्यायाधीश को सुनवाई का अवसर दें।

प्रस्ताव पर निर्णय और उसके आवश्यक परिणाम के रूप में

संसद द्वारा जांच रिपोर्ट विद्वान न्यायाधीश को दी जाएगी। इस प्रकार, यदि रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने के लिए निर्देश मांगा जा रहा है

प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत के कथित उल्लंघन का आधार

और इस तरह के लिए कोई नींव या आधार रखे बिना एक पुनर्निर्माण की भविष्यवाणी करना राहत मिलती है।

यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि प्राकृतिक न्याय के नियम सुआ क्यूज़ और ऑडी अल्टरम पार्टेम में निमो जूड्स के दोहरे सिद्धांतों में प्रकट होते हैं। हम यहाँ पूर्व के साथ चिंतित नहीं हैं क्योंकि पक्षपात का कोई मामला नहीं उठाया गया है। शिकायत यह है कि बिना सुने निंदा की जा रही है। ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम के कुछ पहलू हैं जिनमें से दो हैं (9) मामले का नोटिस जिसे पूरा किया जाना है; और (बी) व्याख्या करने का अवसर। एस. एम. टी. में कोई उल्लंघन नहीं है।

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [कासलिवाल, जे.]

ऑडियो अल्टरम के उपरोक्त दो पहलुओं में से किसी का भी वर्तमान मामला

पारटेम नियम। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और मेरे विचार में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वर्तमान मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन हुआ है।

प्राकृतिक सिद्धांतों के उल्लंघन के इस आधार का अगला अंग

याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया न्याय यह है कि यदि रिपोर्ट की प्रति विद्वान न्यायाधीश को नहीं दी जाएगी, तो यह उनके न्यायिक समीक्षा के अधिकार को विफल कर देगा। मुझे इस समर्पण में कोई ताकत नहीं मिलती है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत के तहत उभरता हुआ अधिकार नहीं है। इसे ऑडी अल्टरम पारटेम के नियम के बराबर नहीं माना जा सकता है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार अपने आप में एक अधिकार है जो केवल सीमित अनुमेय आधारों पर उपलब्ध है। न्यायिक समीक्षा की मांग करने का अधिकार प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

दिव्य मामला और कई कारकों पर निर्भर करेगा जो आवश्यक होंगे

विशेष आदेश या कार्रवाई को चुनौती देने से पहले जांच की जानी चाहिए। एक अमूर्त प्रस्ताव के रूप में न्यायिक समीक्षा की कोई मांग नहीं हो सकती है।

प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर कानून का

अधिनियम और नियमों की योजना में चरण। इस आधार पर कोई निर्देश नहीं मांगा जा सकता है कि यदि रिपोर्ट की प्रति इस पर प्रदान नहीं की गई है।

संविधान के किसी भी प्रावधान से यह दिखाया गया है कि ऐसा अधिकार है - संबंधित न्यायाधीश को उपलब्ध। न तो कोई उल्लंघन हुआ है

प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत और न ही अध्यक्ष को भेजने से पहले जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान न करने में किसी भी संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन। यह न्यायालय किसी को कोई आदेश नहीं दे सकता है।

प्राधिकरण जब तक यह नहीं दिखाया जा सकता है कि ऐसा प्राधिकरण उल्लंघन में काम कर रहा है कानून या संवैधानिक दायित्व के किसी भी प्रावधान का। इस प्रकार भले ही

यह माना जा सकता है कि समिति एक वैधानिक कार्य कर रही है।

न्यायिक समीक्षा में इस न्यायालय की अधिकारिता के लिए उत्तरदायी, यह होना चाहिए यह दर्शाता है कि यह किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन कर रहा है। वर्तमान मामले में

इसके बजाय जांच समिति अपने कानूनी कर्तव्य का पालन कर रही है और अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजने के वैधानिक दायित्व को पूरा कर रही है और इस तरह देरी करने या इसमें कोई बाधा डालने के लिए कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

समिति की ओर से वैध कार्रवाई।

मैं विद्वान वकील के प्रस्तुतिकरण से सहमत नहीं हूँ

सामान्य तौर पर कि इस मामले में जांच रिपोर्ट की तुलना की जा सकती है या सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. पी. की तुलना की जा सकती है।

1 एस सी आर।

204

लोक सेवक के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत दी गई मंजूरी के साथ। अधिनियम और आयोग के प्रावधानों के तहत गठित जांच समिति की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर संबंधित न्यायाधीश को अवसर देने के बाद अपने निष्कर्ष को दर्ज करने वाले उच्च न्यायिक अधिकारियों की मंजूरी के साथ तुलना या तुलना नहीं की जा सकती है।

एक लोक सेवक के संबंध में एक कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया।

संबंधित न्यायाधीश दुर्व्यवहार के बराबर नहीं था और प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का निर्णय ले सकता है। दूसरी ओर, यदि न्यायिक समीक्षा के दौरान यह न्यायालय जांच समिति द्वारा दर्ज किए गए ऐसे निष्कर्षों को इस न्यायालय का निर्णय होने के नाते मंजूरी देता है या पुष्टि करता है, तो यह संसद पर बाध्यकारी होगा। उस स्थिति में, संसद के लिए एक अलग दृष्टिकोण रखना संभव नहीं होगा और यह योजना के ढांचे में एक अतिरिक्त संवैधानिक हस्तक्षेप होगा। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान एक अन्य मामले में इस न्यायालय की समीक्षा जांच समिति द्वारा संचालित पूरी कार्यवाही को रद्द करने के निष्कर्ष पर आ सकती है और इसे एक नई जांच आयोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह के मामले में नियमों और अध्यक्ष द्वारा अनुमत अवधि से परे जांच जारी रखने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जांच समिति का जीवन और अस्तित्व स्वयं नियमों के नियम 9 (2) (सी) में निर्धारित 3 महीने की अवधि के साथ या जब तक अध्यक्ष उपरोक्त नियम के परंतुक के तहत पर्याप्त कारण के लिए समय नहीं बढ़ाता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद, समिति कार्य करना बंद कर देती है और न तो यह न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय जांच समिति के निष्कर्षों की न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में इस अवधि को बढ़ा सकता है। वैधानिक नियमों में ही 3 महीने की अवधि तय की गई है और अकेले अध्यक्ष को पर्याप्त कारण के लिए ऐसी अवधि बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है। मेरी विनम्र राय में यह न्यायालय ऐसी अवधि नहीं बढ़ा सकता है और न ही अध्यक्ष को ऐसा करने के लिए कोई निर्देश दे सकता है, और मामले को नई जांच के लिए रिमांड करने या मामले को लंबित रखने का कोई भी प्रयास तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि संबंधित न्यायाधीश न्यायिक समीक्षा के माध्यम से रिपोर्ट को चुनौती देने या उपरोक्त अवधि से परे न्यायिक समीक्षा के अभ्यास के तहत मामले को निर्णय के लिए लंबित रखने का निर्णय नहीं लेता है और यह अप्रत्यक्ष तरीके से नहीं किया जा सकता है जो सीधे नहीं

किया जा सकता है। इस न्यायालय के पास जांच समिति के जीवनकाल को 205 तक बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [कासलिवाल, जे.]

वैधानिक नियमों के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार न्यायिक आदेश।

इसके अलावा, यदि इस स्तर पर उनके खिलाफ न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी जाती है।

समिति द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को उस मामले में समिति द्वारा अभिलिखित दोषी नहीं होने के निष्कर्षों को भी उन व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है जिन्होंने प्रस्ताव शुरू किया था। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील की ओर से इस संबंध में यह तर्क दिया गया है कि समिति द्वारा दर्ज किए गए दोषी नहीं होने के निष्कर्षों को चुनौती देने का कोई सवाल ही नहीं है।

अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत अनुज्ञेय, जिसके अनुसार समिति की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष मिलता है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है, तो रिपोर्ट के संबंध में संसद के किसी भी सदन में आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। मुझे इस तरह के विवाद में कोई बल नहीं मिलता है क्योंकि यह केवल तभी लागू होगा जब न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा में भी दोषी नहीं होने के इस तरह के निष्कर्ष की पुष्टि की जाएगी। लेकिन यदि न्यायिक समीक्षा में इस तरह के निष्कर्ष को ही उलट दिया जाता है, तो समिति द्वारा दोषी नहीं होने का निष्कर्ष अब मौजूद नहीं है और इसे न्यायिक समीक्षा में दर्ज दोषी के निष्कर्ष के रूप में लिया जाएगा। इस प्रकार, कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिन्हें पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है और जो स्वयं संबंधित न्यायाधीश के हित के खिलाफ हो सकती हैं।

इस प्रकार, अधिनियम और नियमों और संविधान की योजना में ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में, जांच समिति को इस स्तर पर न्यायिक समीक्षा की मांग के लिए न्यायाधीश को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है, जब जांच पहले ही पूरी हो चुकी हो। जहाँ तक संसद में कार्यवाही के समापन के बाद के चरण का संबंध है, न्यायिक समीक्षा का उपाय हमेशा उपलब्ध रहता है, जो निश्चित रूप से उस समय सामने आने वाले मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और न्यायिक समीक्षा के मान्यता प्राप्त अनुमेय आधारों के अधीन होगा। इस मामले में पूरी संवैधानिक योजना से पता चलता है कि संसद को राज्य की स्वतंत्रता और गरिमा पर पूरा भरोसा था।

न्यायपालिका। जाँच केवल उच्च न्यायिक अधिकारियों से बनी जाँच समिति पर छोड़ दी गई है। ऐसी समिति के दोषी नहीं होने का निष्कर्ष देने के मामले में, इसे अंतिम माना गया है और एक मौन दिया गया है और प्रस्ताव पर आगे कोई चर्चा की अनुमति नहीं दी गई है। जाँच समिति द्वारा अभिलिखित दोषी पाए जाने के मामले में ही प्रस्ताव पर आगे विचार करने की आवश्यकता होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता

सहित व्यापक लोक हित में इस तरह के मामले में, दोषी पाए जाने के बाद, यदि कोई हो, तो सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. पी.

1 एस सी आर।

206

जाँच समिति द्वारा और इस स्तर पर न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ऐसी रिपोर्ट को चुनौती देने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। जाँच समिति द्वारा संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ दोषी पाए जाने के मामले को, यदि कोई हो, दर्ज करने के बाद, संसद द्वारा आगे के विचार के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। संसद को इस मामले में अपनी भावी कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर जनता के प्रति जवाबदेह छोड़ दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार, मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता और याचिका द्वारा अनुरोध के अनुसार कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

भाई वर्मा, जे. के निर्णय में दिए गए निर्देश के संदर्भ में निपटाया जाता है।

के. रामास्वामी, जे. मेरे विद्वान भाई वर्मा, जे. द्वारा प्रसारित मसौदा निर्णय को पढ़ने का लाभ प्राप्त करने और अपने चिंतित विचार को देखते हुए, मैं पूरी तरह से उनके साथ नहीं जाने के लिए खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन अकेले डूबना पसंद करता हूँ।

याचिकाकर्ता ने श्री न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत समिति को निर्देश देने के लिए मैडमस की रिट या किसी अन्य रिट या निर्देश की मांग की, जिसे इसके तहत नियुक्त किया गया था। सेक। 3 (2) न्यायाधीश (पूछताछ) अधिनियम 1968 का संक्षिप्त 'अधिनियम', अपनी रिपोर्ट की एक प्रति माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. रामास्वामी को अपने अधीनता के समक्ष प्रदान करने के लिए।

लोकसभा अध्यक्ष को भेंट। उन्होंने उक्त समिति को यह निर्देश देने की भी मांग की कि वह उक्त रिपोर्ट को एक साथ समिति को अग्ररेषित करने से रोके।

अध्यक्ष महोदय। तथ्य यह है कि 9 वीं लोकसभा के अध्यक्ष ने श्री न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत समिति का गठन इस प्रस्ताव के आधारों की जांच करने के लिए किया, जिसमें श्री न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी प्रशासनिक क्षमता में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के साथ इस अदालत के न्यायाधीश के पद से हटाने का अनुरोध किया गया था, जो कला के अर्थ के भीतर दुर्व्यवहार का गठन करती हैं। 124 (4) भारत का संविधान। श्री एम. कृष्ण स्वामी ने 1992 की रिट याचिका संख्या 149 दायर की और प्रस्ताव को स्वीकार करने की अध्यक्ष की शक्ति और न्यायशास्त्र, समिति के गठन और आरोपों की जांच के लिए अनुकूलित प्रक्रिया आदि पर सवाल उठाया। द.

समिति ने अपना पद ग्रहण करने पर जांच शुरू की, कार्यवाही पर रोक, हालांकि मांगी गई थी, लेकिन उसे मंजूरी नहीं दी गई और जांच जारी रही। जब हम रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, 10 मई, 1992 को विद्वान न्यायाधीश ने समिति के पीठासीन अधिकारी को एक पत्र संबोधित किया जिसमें अध्यक्ष को भेजे जाने से पहले उन्हें अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था और उचित समय देकर इसे रोकने का भी अनुरोध किया गया था।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [के. रामास्वामी। जे.]

उन पर गौर करना और उचित कार्रवाई करना। 1992 की रिट याचिका संख्या 149 में भी इसी राहत के लिए आवेदन किया गया था। इस पीठ को यह समझने के लिए दिया गया था कि समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी माननीय अध्यक्ष को 31 जुलाई, 1992 को या उससे पहले, विस्तारित तिथि। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान याचिकाकर्ता ने उपरोक्त के लिए रिट याचिका दायर की।

राहत जो 1992 की रिट याचिका संख्या 149 के साथ पोस्ट की गई थी। इस पीठ द्वारा यह पृच्छने पर कि क्या विद्वान न्यायाधीश इस मामले में दिए जाने वाले निर्णय का पालन करने के लिए सहमत होंगे, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने निर्देश पर पॉजिटिव को बताया। उन्होंने उस पत्र को रिकॉर्ड में रखा जिसे उन्होंने संबोधित किया था और उस पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा समर्थन किया गया था। उन्होंने कहा कि न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति v. भारत संघ और अन्य।, [1991] 2 संक्षिप्त 'एस. सी. जे. ए.' मामले के लिए एस. सी. आर. 741, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करना और

समिति संसदीय प्रक्रिया के बाहर अध्यक्ष के वैधानिक कार्य हैं। जब तक रिपोर्ट प्रत्येक सदन के पटल पर नहीं रखी जाती संसद, अध्यक्ष के पास रिपोर्ट का अधिकार है और उसे रोकने की शक्ति है। समिति भी। यदि जांच में पता चलता है कि कदाचार साबित नहीं हुआ है, तो मामला समाप्त हो जाता है और आगे की राजनीतिक प्रक्रिया की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यदि यह पाया जाता है कि कदाचार किया गया है

यह साबित होता है कि न्यायाधीश को हटाने की संसदीय प्रक्रिया संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रिपोर्ट और साक्ष्य रखने पर पुनर्जीवित हो जाती है और संबोधन शुरू हो जाता है। जांच राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया का विवेकपूर्ण मिश्रण है। प्रस्ताव की स्वीकृति, सं का संविधान: समिति और समिति द्वारा अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करना संसदीय प्रक्रियाओं से बाहर है और न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। विद्वान न्यायाधीश दुर्व्यवहार के प्रतिकूल निष्कर्ष पर सवाल उठाने का हकदार है और इसलिए वह वास्तव में अध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने का हकदार है। जब विद्वान न्यायाधीश को अधिकार है और वह न्यायिक समीक्षा का हकदार है, तो साबित दुर्व्यवहार के निष्कर्ष की शुद्धता पर सवाल उठाने के लिए उसे अनुच्छेद के तहत इस अदालत में जाने का अधिकार है। 32 या कला। 136 या कला के तहत उच्च न्यायालय। 226. रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति के बिना वह

पर्याप्त रूप से अनुरोध नहीं कर सकते हैं और इसे रद्द करने के लिए इसकी गलतता को साबित नहीं कर सकते हैं। तदनुसार यह उनका तर्क है कि रिपोर्ट की आपूर्ति और उचित समय देना न्यायिक समीक्षा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक अभिधारणाएं हैं। तदनुसार विद्वान न्यायाधीश अपनी रिपोर्ट की प्रति का हकदार है। इसके समर्थन में उन्होंने कहा कि संसदीय प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब अध्यक्ष सदन की सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट (1992) में अनुलग्नक के रूप में प्रस्ताव पेश करता है।

1 एस सी आर।

208

न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने वाले संबोधन के साथ। तब तक अध्यक्ष एक सांविधिक प्राधिकारी बना रहता है, अधिनियम या न्यायाधीश जांच नियम 1969 में संक्षिप्त 'नियम' के लिए या संविधान में विद्वान न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व और सुनवाई का अवसर प्रदान करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि संसद अपने संबोधन में किस प्रक्रिया को अपना सकती है और यह न्यायिक समीक्षा से भी मुक्त है। आवश्यक निहितार्थ से, विद्वान न्यायाधीश के पास जब समीक्षा करने का अधिकार होता है तो उसके पास न्यायिक प्रक्रिया में प्रतिकूल रिपोर्ट को चुनौती देने का उपाय होना चाहिए और रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति आवश्यक है। अधिनियम और नियमों में अध्यक्ष के लिए विद्वान न्यायाधीश को रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। एक बार संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर एक रिपोर्ट रखे जाने के बाद यह विशेष रूप से संसद के अधिकार क्षेत्र में आती है और न्यायाधीश न्यायिक समीक्षा का अपना अधिकार खो देता है। संसद रिपोर्ट की एक प्रति देने का विकल्प चुन सकती है या रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए एक उप समिति का गठन कर सकती है या विद्वान न्यायाधीश को बिना किसी अवसर के संबोधन के साथ आगे बढ़ सकती है। एस. सी. जे. ए. के मामले में इस अदालत के फैसले के परिणाम के रूप में, समिति की रिपोर्ट अपने निष्कर्षों के साथ विद्वान न्यायाधीश को प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसके बिना कभी भी कोई प्रभावी न्यायिक कार्य नहीं हो सकता है।

समीक्षा करें। इस मूल्यवान अधिकार को न तो लिया जा सकता है और न ही व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा निरर्थक बनाया जा सकता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और कला का उल्लंघन करने वाली अनुचित प्रक्रिया का उल्लंघन करेगा। 21. समिति एक सांविधिक न्यायाधिकरण है, भले ही बल के अनुसार इसकी रिपोर्ट प्रभावी नहीं है। एक न्यायाधिकरण के रूप में

उसे अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने का आदेश दिया गया है और यदि वह प्रदान करने में विफल रहता है, तो विद्वान न्यायाधीश को रिट याचिका को बनाए रखने का अधिकार है।

रिपोर्ट की प्रति प्रदान करने के लिए समिति।

विद्वान महान्यायवादी श्री जी. रामास्वामी ने तर्क दिया कि समिति अध्यक्ष के अधीनस्थ प्राधिकरण की प्रकृति में है, जो बाद वाला एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की

धारा 197 के तहत एक लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने जैसी है। जब तक मंजूरी की वैधता पर जल्द से जल्द सवाल नहीं उठाया जाता है, तब तक आरोपी को बाद में उस पर हमला करने से रोक दिया जाता है। उसी सादृश्य पर न्यायाधीश: संसद द्वारा दरकिनार किए जाने से पहले ही प्रतिकूल निष्कर्षों, संसद में संबोधन के लिए आधार, को जल्द से जल्द चुनौती देने का हकदार है। एस. सी. जे. ए. के मामले में इस अदालत ने पाया कि समिति की प्रतिकूल रिपोर्ट के खिलाफ न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है। हटाने की समान दायित्व प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। वहाँ

संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर कोई भी प्रस्ताव रखे जाने से पहले, एस. एम. टी.

एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [के. रामास्वामी, जे.]

209

विद्वान न्यायाधीश को रिपोर्ट की एक प्रति और उसकी न्यायिक समीक्षा की आपूर्ति करने का अधिकार है। इसके बाद, इस अदालत के पास संसद के दोनों सदनों द्वारा चर्चा के लिए प्रस्ताव लेने से पहले कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। बाद में हस्तक्षेप करना संसदीय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के समान होगा। केवल संसद को ही यह तय करना है कि प्रस्ताव से कैसे निपटा जाए। न तो इस अदालत के पास और न ही इस काउंटी के किसी अन्य अदालत के पास मामले से निपटने या उसके फैसलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र है। इन परिस्थितियों में विद्वान न्यायाधीश को रिपोर्ट की एक प्रति और इस न्यायालय द्वारा उसी की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। अन्यथा कोई भी निर्माण विद्वान न्यायाधीश को ऊँचा और सूखा छोड़ देगा। ऐसी स्थिति कानून के शासन और न्याय के लिए अभिशाप है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग एससीजेए के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित संविधान, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों की व्याख्या के अनुरूप होगा। कोई भी अन्य दृष्टिकोण एस. सी. जे. ए. के मामले में निष्कर्ष के विपरीत होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह प्राकृतिक न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ निष्कर्ष दिए जाते हैं, वह सुनवाई का हकदार है और प्रतिकूल निष्कर्षों की न्यायिक समीक्षा की मांग करता है। एक परिणाम के रूप में वह रिपोर्ट की प्रति प्रदान करने का हकदार है और बाद में समिति के सदस्य रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

समिति के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरीमन ने कहा कि समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट न्यायाधीश को हटाने की राजनीतिक प्रक्रिया से सीधे संबंधित कुछ वैधानिक परिणामों को अंकुरित करती है, चाहे वह अपराध या दोषमुक्ति का निष्कर्ष हो। रिपोर्ट अपने विचार के लिए एक संसदीय दस्तावेज बनाती है और लंबित प्रस्ताव की भविष्य की दिशा निर्धारित करती है। यदि निष्कर्ष दोषपूर्ण है तो प्रस्ताव को विचार और मतदान के चरण में आगे बढ़ना होगा। यदि निष्कर्ष "दोषी नहीं" का है तो संसद द्वारा आगे विचार या चर्चा किए बिना कानून के बल से प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाता है। अधिनियम की धारा 4 (2) और 4 (3) के संचालन द्वारा समिति को अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है जो इसे धारा 4 (3) के तहत संसद के दोनों सदनों में रखने के लिए बाध्य है। यदि यह तर्क कि रिपोर्ट के निष्कर्ष न्यायिक

समीक्षा के अधीन हैं, तो परिणाम यह होगा कि "दोषी नहीं" के निष्कर्ष पर भी प्रस्ताव पेश करने वाले संसद के किसी भी सदस्य द्वारा सवाल उठाया जा सकता है। जब तक रिपोर्ट को बरकरार नहीं रखा जाता या निरस्त अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों में आगे कोई कदम नहीं उठाएगा। आवश्यक निहितार्थ से यह पारलाइमेंट द्वारा विचार को बाहर करता है। दूसरे शब्दों में, न्यायिक समीक्षा का अर्थ होगा -

मैं अदालत की रिपोर्ट [1992] का समर्थन करता हूँ। 1 एस सी आर।

210

संविधान के तहत सर्वोच्च मंच पर राजनीतिक प्रक्रिया। रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखने पर प्रस्ताव चर्चा और अनुच्छेद के संदर्भ में बहुमत द्वारा संकल्प के अधीन होगा। 124 (4) जो आवश्यक निहितार्थ से संसद में उक्त निष्कर्ष और राजनीतिक प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा को बाहर करता है। विद्वान न्यायाधीश बिना उपचार के नहीं हैं। न्यायिक समीक्षा आवश्यक रूप से न्यायालय द्वारा नहीं की जानी चाहिए। अनुच्छेद 124 (4) संसद को अनुच्छेद के तहत बनाए गए कानून के संदर्भ में समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करने का अधिकार देता है। 124 (5) . जब रिपोर्ट पर विचार किया जाता है तो विद्वान न्यायाधीश को संसद में सुनवाई का अधिकार होता है। इसके समर्थन में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एंजेलो वास्ता के उदाहरण पर भरोसा किया, जिसमें न्यायमूर्ति वास्ता को एक नोटिस दिया गया था और संसद द्वारा उनके आचरण पर चर्चा करने और राज्यपाल को उन्हें हटाने की सिफारिश करने से पहले सदन में उनकी सुनवाई की गई थी।

इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि एस. सी. जे. ए. के मामले में अनुपात केवल समिति की कार्यवाही की "प्रक्रिया और प्रगति" की देखरेख करने के लिए है, इससे पहले कि वह अपनी रिपोर्ट भेजे।

रिपोर्ट करें। समिति का कार्य अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ समाप्त होता है जिसमें उसके सिद्ध अपराध या गैर-अपराध के निष्कर्ष होते हैं। इसके बाद निहितार्थ से रिपोर्ट न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। अनुच्छेद 124 (4) के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने के आदेश के बाद न्यायिक समीक्षा न्यायिक समीक्षा से मुक्त प्रतीत नहीं होती है, चाहे वह धारा 124 (4) के तहत दीवानी मुकदमे द्वारा हो। 9 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 जो नहीं थी

स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा इसे या कला के तहत किसी कार्यवाही में वर्जित करता है। 32 या कला। 226 संविधान से। इस न्यायालय द्वारा यह तय किया गया कानून है कि यह विशेषाधिकार रिट की तकनीकीताओं से बाध्य नहीं है। शक्ति का प्रयोग

कला के तहत। 226 या कला। 32 न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान लचीला है। उपचार की प्रकृति अलग हो सकती है, बहाली नहीं हो सकती है लेकिन नुकसान हो सकता है। यह उनका आगे का तर्क है कि अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव के निपटारे का अभियान, अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजने के

लिए 3 महीने का समय निर्धारित करने वाले प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ने से प्रेरित है। हस्तक्षेप यह है कि न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संसद का एक दस्तावेज होने के नाते, तार्किक निष्कर्ष यह होगा कि संसद को विद्वान न्यायाधीश के सिद्ध दुर्व्यवहार पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए और संसद को संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के संदर्भ में बहुमत के अनुसार अपना निर्णय लेने की अनुमति दी जाए। आवश्यक निहितार्थ द्वारा न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए

इस स्तर पर अनुच्छेद 124 (4) की उचित और सही व्याख्याओं से बचना चाहिए।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [के. रामास्वामी, जे.]

211

और अनुच्छेद 124 (5), अधिनियम और नियम। विद्वान वकील के अनुसार यह विद्वान न्यायाधीश की संवेदनशीलता नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास का व्यापक सार्वजनिक हित है जो सर्वोपरि है।

राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने का आदेश पारित होने तक रिपोर्ट की समीक्षा न करने से जनहित की रक्षा और संरक्षण होगा। यह न्यायिक समीक्षा की प्रभावकारिता पर कपटी प्रभावों के प्रसार और प्रसार से भी बचाता है।

उनके इस तर्क के समर्थन में कि न्यायिक समीक्षा हटाने के तहत

कला. 124 (4) यह अस्वीकार्य है, उन्होंने तुन दातो हाजी मोहनद सल्लाह बिन अबुस बनाम में निर्णय पर भरोसा रखा। ताम श्री दातो, मालसिया के उच्चतम न्यायालय का 1983 एल. आर. सी. 25, जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण को न्यायाधीश के दुर्व्यवहार की जांच करने और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आदेश जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक संवैधानिक कार्य है जो प्रभावी रूप से महामहिम को रिपोर्ट प्राप्त करने से रोकने के बराबर है।

अंतिम चरण में हटाने के आदेश की न्यायसंगतता के बारे में उन्होंने पॉवेल बनाम पर भरोसा रखा। मैककॉमैक, [1937] 395 यू. एस. 486 जिसके तहत

सीनेट द्वारा पॉवेल को सदन से हटाने की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी और यह माना गया था कि महाभियोग की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन थी। उन्होंने महाभियोग पर राउल बर्ज की टिप्पणी, महाभियोग पर ब्लैक और प्रो. एस. ए.

16 मॉडर्न लॉ रिव्यू 502 में डीस्मिथ का लेख; 1974 अमेरिकन बार एसोसिएशन जर्नल 681; और प्रो. हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लॉरेंस जनजाति,

अमेरिकी संवैधानिक कानून 1988, दूसरा संस्करण। कर कानून समीक्षा, खंड। 68 (1989) पी। 97 माइकल गेरहैड्ट और इमानुक्ट्स संवैधानिक कानून 1991-92 द्वारा महाभियोग की न्यायिक समीक्षा। उन्होंने तुलनाओं को आकर्षित किया

अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति। 70 (ग) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना। अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष। 94 (ग) न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वे अनुच्छेद के तहत एक न्यायाधीश को हटाने के लिए विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रक्रियाकारी हैं। 124 (4) और 124 (5) राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया का एक समामेलन है। लोक सेवा के अध्यक्ष या सदस्य को हटाना अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा एक रिपोर्ट पर आयोग। 317 कला के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। 32 , क्योंकि रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय की है न कि न्यायाधीशों की समिति की।

212

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

विद्वान महान्यायवादी और श्री सिब्ल अपने निर्णय में एकमत हैं

जवाब दें कि प्रस्ताव के बाद न्यायाधीश को हटाने की राजनीतिक प्रक्रिया

प्रति बहुमत, कला के अनुरूप। 124 (4) संविधान की, न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है क्योंकि संसद न्यायिक शक्ति का प्रयोग करती है लेकिन विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं करती है। न्यायिक निष्कर्ष को दर्ज करने की इसकी शक्ति कि क्या वह दोषी है या नहीं, समिति को सौंपी गई थी और यह उसका निर्णय है। यह पूर्वानुमान नहीं हो सकता है

यह बताया गया कि विद्वान न्यायाधीश के दुर्व्यवहार पर चर्चा करने के लिए संसद किस प्रक्रिया का पालन करेगी। इसलिए, न्यायिक समीक्षा राज्य की दो संवैधानिक शाखाओं के अधिकार क्षेत्र के टकराव में बदल जाएगी और न्यायालय कानून की अंतिमता को बाधित करने के लिए आत्मसंयम का प्रयोग करेगा।

न्यायाधीश को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया। एस. सी. जे. ए. के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक समीक्षा न्यायाधीश के लिए केवल एक सहयोगी के रूप में सदन के पटल पर रखे जाने से पहले ही उपलब्ध होगी। लेकिन वे इस स्थिति पर सहमत हुए कि न्यायिक समीक्षा उपलब्ध होगी, यदि हटाने को पारित नहीं किया जाता है, जैसे कि संसद के उपस्थित दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा और मतदान या चर्चा और मतदान एक ही सत्र में नहीं था या यहां तक कि साबित तथ्य और उसके आधार पर संसद द्वारा स्वीकार किए गए अपराध का निष्कर्ष कानून की नजर में कदाचार नहीं है, आदि। श्री सिब्ल ने पॉवेल के मामले को इस आधार पर अलग किया कि यह सदन के सदस्य के रूप में बैठने के लिए अयोग्यता थी न कि कदाचार और विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रक्रिया के लिए महाभियोग। उन्होंने हालस्टेड एल. रिटर बनाम पर भरोसा किया। यू. एस., 84 का न्यायालय

श्री नरीमन द्वारा संदर्भित 293 दावों और प्रमाणपत्र को रिटर में अस्वीकार कर दिया गया था।

वी. अमेरिका, 300 यू. एस. 663। एस. सी. जे. ए. के मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि प्रस्ताव को स्वीकार करने के चरण से लेकर रिपोर्ट को वैधानिक होने तक न्यायाधिकरण के निष्कर्ष इस अदालत द्वारा कला के तहत समीक्षा योग्य हैं। 32

या संविधान या अनुच्छेद का 136। 226 उच्च न्यायालय में। प्रतिकूल

रिपोर्ट, यदि पाई जाती है, तो रिट याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण बताएगी। यह विद्वान न्यायाधीश के लिए खुला है कि वह अदालत को समिति द्वारा की गई अवैधताओं को बताए और उन्हें सीमा पर ठीक किया जाए और हटाने के बाद न्यायिक समीक्षा प्रभावी नहीं है। हटाने के बाद उपचार की उपलब्धता

न्यायालय को जल्द से जल्द अवैधताओं या त्रुटियों को सुधारने से नहीं रोकता है।

हालाँकि विवाद चौड़े कैनवास पर उकेरे गए हैं, मैं ध्यान केंद्रित करना पसंद करता हूँ। संकीर्ण सीमाओं के भीतर समस्या। क्या, किसी निष्कर्ष की न्यायिक समीक्षासमिति द्वारा अभिलिखित अपराध का या संसद के दोनों सदनों द्वारा अपेक्षित बहुमत के साथ पारित प्रस्ताव के बाद न्यायाधीश को हटाने का, जो न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है और यदि ऐसा है तो किन आधारों पर:

एसएम। टी. एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [के. रामास्वामी, जे.]

213

कारण यह है कि इस स्तर पर प्रश्न में जाना जल्दबाजी होगी और दूसरी बात यह है कि जब यह इस न्यायालय और न्यायालय की अधिकारिता के टकराव में चला जाता है। संसद, एक अनुचित स्तर पर एक राय से बचना बेहतर होगा। संसद ने इस न्यायालय की भाषा में अधिनियम बनाते समय

एस. सी. जे. ए. के मामले ने संवैधानिक न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के लिए कृष्ण स्वामी के मामले में राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया के "विवेकपूर्ण मिश्रण" या "मिश्रण और एकीकरण" को अपनाया। हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत

एक न्यायाधीश को प्रस्ताव में बताए गए आधारों के साथ राज्यसभा या लोकसभा के आवश्यक सदस्यों को सौंपा गया था। अध्यक्ष को इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति सौंपी गई थी और इसे स्वीकार करने पर सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से एक और एक प्रतिष्ठित न्यायविद से बनी एक उच्च न्यायिक समिति का गठन करने का कर्तव्य सौंपा गया था। एस. सी. जे. ए. के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सभी कार्रवाई अधिनियम के तहत अध्यक्ष संसदीय कार्यवाही के बाहर वैधानिक हैं और न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

मेरे सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण में, एकमात्र प्रश्न, प्रासंगिक तथ्यों पर

इस मामले में निर्णय यह है कि क्या विद्वान न्यायाधीश माननीय को प्रस्तुत की जाने वाली समिति की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने का हकदार है।

लोकसभा अध्यक्ष। यदि श्री नरीमन के इस तर्क को स्वीकार किया जाता है कि जिस क्षण समिति द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, वह एक संसदीय दस्तावेज बनाता है, तो तार्किक परिणाम संसद के दोनों सदनों द्वारा एक संबोधन में समाप्त होना चाहिए; कला के संदर्भ में पारित उस संबंध में एक प्रस्ताव। 124 (4) और हटाने का आदेश राष्ट्रपति द्वारा पारित किया जाएगा। निश्चित रूप से, परिणाम यह होगा कि राजनीतिक प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और न्यायाधीश को हटाने का आदेश अंतिम हो जाता है। न्यायिक प्रक्रिया द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है या नहीं, यह एक और सवाल है। जैसे ही समिति द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जैसा कि बताया गया है कि समिति द्वारा पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, सवाल यह है कि क्या यह स्वचालित रूप से पार लाइमेंटरी दस्तावेज का हिस्सा बन जाएगा। क्या समिति द्वारा विद्वान न्यायाधीश को दोषमुक्त किए जाने के निष्कर्ष पर भी सवाल उठाया जा सकता है जैसा कि श्री नरीमन ने तर्क दिया है? आइए पहले हम बाद के प्रश्न को लेते हैं। उस विवाद को स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए, अधिनियम के Sec.6 के दायरे पर विचार करना आवश्यक है जो इस प्रकार है:

214

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

6. (1) " यदि समिति की रिपोर्ट में कोई निष्कर्ष है

कि न्यायाधीश किसी दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है या करता है

किसी भी असमर्थता से पीड़ित नहीं, फिर, कोई आगे कदम नहीं

इस संबंध में संसद के किसी भी सदन में लिया जाएगा सदन में लंबित रिपोर्ट और प्रस्ताव के लिए या

संसद के सदनों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

(2) यदि समिति की रिपोर्ट में कोई निष्कर्ष है कि

न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी है या पीड़ित है

कोई असमर्थता, तो, धारा 3 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव, समिति की रिपोर्ट के साथ, द्वारा विचार के लिए लिया जाएगा

संसद का वह सदन या सदन जिसमें वह है

लंबित है।

(3) यदि प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा स्वीकार किया जाता है

अनुच्छेद 124 या, जैसा भी मामला हो, संविधान के अनुच्छेद 218 के साथ पठित उस खंड के अनुसार, तब, न्यायाधीश का दुर्व्यवहार या अक्षमता

माना जाता है कि साबित किया गया है और एक पता प्रार्थनान्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा

प्रत्येक सदन द्वारा राष्ट्रपति को निर्धारित विधि

संसद के उसी सत्र में जिसमें प्रस्ताव

अपनाया गया है "।

अधिनियम ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीश को हटाने की राजनीतिक प्रक्रिया को साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के अपराध के निष्कर्ष से सुगंधित किया जाना चाहिए, जो कला के तहत हटाने के लिए एक आधार है। 124 (4) एक उच्च न्यायिक प्राधिकारी द्वारा क्योंकि यह समान रूप से उच्च अधिकारी द्वारा पद की प्रतिष्ठा और अभिग्रहण को बाधित करता है।

संवैधानिक कार्यकर्ता। अनुच्छेद 124 (5) प्रक्रिया का कानून बनाने का अधिकार देता है। न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जाँच के लिए अधिकार। धारा 3 (2) अध्यक्ष को उसके संदर्भ में समिति का गठन करने के लिए अधिकृत करती है और इसलिए, वह समिति पर कोई अधिकार नहीं रखता है। इस प्रकार समिति न्यायाधीश की स्थिति के अनुरूप एक उच्च न्यायिक निकाय है। महान्यायवादी का यह तर्क कि समिति अध्यक्ष की प्रतिनिधि है, गलत धारणा है। सेक के संचालन द्वारा। 6 (1) , यदि समिति की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष है कि न्यायाधीश दोषी नहीं है

दुर्व्यवहार या किसी असमर्थता से पीड़ित नहीं है, तो आगे कोई कदम नहीं 215

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. 1. [के. रामास्वामी, जे.]

रिपोर्ट के संबंध में संसद के किसी भी सदन में लिया जाना चाहिए और विधायी अनिवार्यता है कि संसद के किसी भी सदन में लंबित प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो

गति रुक जाती है। परिणाम की परिकल्पना नियम 9 (4) में भी की गई है। नियम 9 रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। नियम 9 का उप-नियम 4 इस प्रकार प्रदान करता है:

" (4) जहाँ जाँच के अधिकांश सदस्य समिति इस आशय का निष्कर्ष निकालती है कि न्यायाधीश

किसी दुर्व्यवहार का दोषी या कि वह दुर्व्यवहार से पीड़ित है।

क्षमता, लेकिन इसका तीसरा सदस्य एक खोज करता है

इसके विपरीत, जांच समिति के पीठासीन अधिकारी

टीई उप-नियम में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित करेगा।

(2) , ऐसे तीसरे सदस्य द्वारा किए गए निष्कर्ष, डुप्लिकेट में

और उसे रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे। सेक के तहत उसके द्वारा मिट्ट किया गया। 4 .

नियम 9 का उप-नियम (6) इस प्रकार है:

" (6) जहां जांच समिति के अधिकांश सदस्य इस आशय का निष्कर्ष निकालते हैं कि न्यायाधीश किसी दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है या वह किसी असमर्थता से पीड़ित नहीं है, और उसका तीसरा सदस्य इसके विपरीत निष्कर्ष निकालता है, तो जांच समिति ऐसे तीसरे सदस्य द्वारा किए गए निष्कर्ष को संसद या किसी अन्य प्राधिकरण, निकाय या व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगी।

सेक का एक संयुक्त पठन। 6 (1) , नियम 9 (6) के साथ पठित नियम 9 (4) विधायी एनीमेशन को स्थापित करेगा कि जहां रिपोर्ट में अपराध का निष्कर्ष है दुर्व्यवहार या यह कि न्यायाधीश सर्वसम्मति से या बहुमत के दृष्टिकोण से असमर्थता से पीड़ित है, तो जांच समिति का पीठासीन अधिकारी (इस न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश), उप-नियम (2) में निर्धारित तरीके से प्रमाणित करेगा कि तीसरे सदस्य द्वारा दोषी नहीं होने के निष्कर्ष को, डुप्लिकेट में, अध्यक्ष/अध्यक्ष को उनके द्वारा धारा 2 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ भेजा जाना चाहिए। 4 . संसद द्वारा चर्चा में, 'दोषी नहीं' के अनुकूल निष्कर्ष को संसद द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है या यहां तक कि अपराध का निष्कर्ष भी अपने पटल पर रखे गए साक्ष्य की सहायता से चर्चा के लिए खुला हो सकता है और संसद बहुमत के दृष्टिकोण से सहमत हो या नहीं हो सकती है जिसमें सबूत माना जाएगा या 216

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

बहुमत के प्रस्ताव के आलोक में दुर्व्यवहार या अक्षमता का खंडन,

हालाँकि उस ओर से कोई स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था। दूसरी ओर, यदि बहुमत सदस्य यह निष्कर्ष निकालते हैं कि न्यायाधीश किसी दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है या वह किसी असमर्थता से पीड़ित नहीं है, तो तीसरा सदस्य इसके विपरीत एक निष्कर्ष दर्ज करता है, समिति संसद या किसी अन्य सदस्य को तीसरे सदस्य के निष्कर्ष का खुलासा नहीं करेगी।

अधिकार, शरीर या व्यक्ति। दूसरे शब्दों में, अल्पमत के दृष्टिकोण को जनता के सामने प्रकट करने के लिए समिति के लिए एक वैधानिक निषेध या अनिवार्य निषेधाज्ञा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि "दोषी नहीं" का निष्कर्ष, दूसरे शब्दों में, अधिकांश लोगों द्वारा कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता से "दोषमुक्ति"।

सदस्यों को निर्णायक माना जाता था और उन्हें गुप्त रखा जाना चाहिए और आवश्यक निहितार्थ से यह न्यायिक समीक्षा को बाहर करता है। इसका कारण स्पष्ट है कि एक उच्च न्यायिक निकाय, एक अंतिम मध्यस्थ के निष्कर्ष का सम्मान किया जाना चाहिए; इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। समान रूप से अल्पमत के दृष्टिकोण का भी प्रकटीकरण न केवल न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा, बल्कि गैर-प्रकटीकरण किसी भी हिस्से से संपाश्विक हमले या किसी तीसरे पक्ष द्वारा सवाल किए जाने वाले दायित्व को भी रोक देगा। यह कृष्ण में आयोजित किया जाता है।

स्वामी का मामला है कि समिति द्वारा की गई जांच में न तो संसद के सदस्यों और न ही किसी को न्यायाधीश के खिलाफ भाग लेने और साक्ष्य देने का अधिकार है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में व्यक्ति को दर्ज किए गए 'दोषी नहीं' के निष्कर्षों की शुद्धता पर संदेह करने का अधिकार है।

समिति द्वारा, न्यायाधीश को आरोप से दोषमुक्त करना। इसलिए, विधायिका ने स्वयं उन परिणामों के बीच अंतर किया जो दोषी या दोषमुक्त के निष्कर्ष को दर्ज करने से उत्पन्न होंगे और पूर्व राजनीतिक प्रक्रिया के अधीन है, साथ ही तीसरे के विपरीत निष्कर्ष के साथ।

सदस्य लेकिन बाद के मामले में यह निर्णायक है। जैसा कि एस. सी. जे. ए. के मामले में कहा गया है, उसके आधार पर आगे कोई कदम विचार के लिए नहीं उठाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह किसी भी हिस्से से हमले से मुक्त है, जब संसद को भी उस प्रश्न में जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। इस प्रकार यह माना जाना चाहिए कि श्री नरीमन का पहला तर्क मान्य नहीं है और तदनुसार यह नकारात्मक है।

अगला सवाल यह है कि 'साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता' के सर्वसम्मत या बहुमत निष्कर्ष की रिपोर्ट संसदीय दस्तावेज़ का हिस्सा कब बनेगी। सेक की उप-धारा (2) के तहत 4, अंत में जांच के लिए, समिति अध्यक्ष को, या जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष को या जहां समिति को भेजा गया है, रिपोर्ट भेजेगी।

अध्यक्ष और सभापति द्वारा दोनों के लिए संयुक्त रूप से गठित प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्षों को इस तरह के कारणों के साथ बताते हुए 217

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [के. रामास्वामी, जे.]

पूरे मामले में जैसा वह उचित समझता है। उप-सेक के तहत (3) अध्यक्ष या अध्यक्ष या दोनों जब समिति का गठन संयुक्त रूप से किया गया था

उन्हें, 'रिपोर्ट को, जितनी जल्दी हो सके, लोक सभा और राज्य परिषद के समक्ष रखा जाएगा'। नियम 9 (3) के तहत, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित जांच समिति की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। नियम 9 के उप-नियम (6) के तहत जब एक सदस्य ने दुर्व्यवहार का दोषी नहीं होने या किसी असमर्थता से पीड़ित नहीं होने का निष्कर्ष दर्ज किया, तो उक्त रिपोर्ट

पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित तीसरे सदस्य को भी नियम 9 (5) के अनुसार साक्षय के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अधिनियम की धारा 3,4 और 6 की व्याख्या करते हुए एससीजेए के मामले में,

अधिकांश ने, चूक के सिद्धांत के संदर्भ में, यह माना कि दुर्व्यवहार या अक्षमता के प्रमाण तक का पूरा चरण की शुरुआत के साथ शुरू हुआ

लगाए जा रहे आरोप की जाँच कला के तहत अधिनियमित कानून द्वारा नियंत्रित होती है। 124 (5) . संसद के प्रत्येक सदन द्वारा एक संबोधन का चरण केवल तभी शुरू होता है जब कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता

खंड 5 (पैरा 78) के तहत अधिनियमित कानून के अनुसार साबित किया गया। पहला भाग पूरी तरह से वैधानिक है जबकि दूसरा भाग अकेले संसदीय प्रक्रिया है। पहला भाग पूरी तरह से अधिनियमित कानून द्वारा कवर किया गया है, जिसकी वैधता और उसके तहत प्रक्रिया स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

किसी भी राजनीतिक रंग का और सबूत के बाद इसका उद्देश्य एक संसदीय प्रक्रिया होना था (पैरा 82)। प्रस्ताव को स्वीकार करने, समिति का गठन करने और कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच के चरण में सदन तस्वीर में नहीं आता है।

अतः अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्राप्ति पर

धारा 4 (2) के तहत समिति या, जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष या उन दोनों को, इसकी उप-धारा (3) के संचालन द्वारा रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए। तैयारी का तरीका

अभिलेख नियम 16 द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। यह अभिनिर्धारित करता है कि जब समिति सर्वसम्मति से या उसके बहुमत के अनुसार, यह पाती है कि न्यायाधीश किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी है या असमर्थता से पीड़ित है, तो लोकसभा या राज्य सभा का सचिव, जैसा भी मामला हो, तैयार करेगा

फॉर्म II में पता और प्रस्ताव की एक प्रति पते के साथ संलग्न की जाएगी। वे प्रत्येक सदन द्वारा विचार के लिए तारीख तय करेंगे और अनुच्छेद के संदर्भ में बहुमत सदस्य द्वारा संबोधन का समर्थन किया जा सकता है। 124 (4) .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस क्षण समिति द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे,

वास्तव में, यह संसद का दस्तावेज नहीं बना, लेकिन जब अध्यक्ष/सभापति या दोनों ने, जैसा भी मामला हो, रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में साक्ष्य और प्रस्ताव के साथ नियम 16 में निर्धारित तरीके से रखा गया, यह संसद का दस्तावेज बन जाता है। तब तक अध्यक्ष/सभापति

अधिनियम के तहत अपनी वैधानिक क्षमता में दस्तावेज। श्री का लंगर

नरीमन ने अपना हुक खो दिया।

फिर सवाल यह है कि क्या समिति एक न्यायाधिकरण है? हिन्दो में

चाइना स्टीम नेविगेशन कं. लिमिटेड बनाम जसजीत सिंह, एडिशनल। कस्टम और ओआरएस के कलेक्टर।, [1964] 6 एस. सी. आर. 594 तथ्य यह था कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्यवाही किए जाने और माल जब्त किए जाने पर केंद्रीय राजस्व बोर्ड के समक्ष एक अपील की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। केंद्र सरकार के लिए एक संशोधन। उसी भाग्य का सामना भी करना पड़ा। जब इस अदालत में अधिनियम के तहत उनकी शुद्धता पर सवाल उठाया गया था। 136, एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि बोर्ड और सरकार कला के अर्थ के भीतर एक न्यायाधिकरण नहीं हैं। 136 और यह कि, इसलिए, अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पारित आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं था। निरस्त करते समय

संविधान पीठ ने पृष्ठ 603 और 604 पर इस प्रकार निर्णय दिया:

" किसी निकाय के चरित्र को निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित या सटीक परीक्षण निर्धारित करना मुश्किल है, जिसे उसके समक्ष लाए गए मामलों पर निर्णय लेने के लिए बुलाया जाता है। कभी-कभी इस तरह के प्रश्न का निर्णय लेने में, अदालतें यह पूछती हैं कि क्या वह निकाय या प्राधिकरण जिसकी स्थिति या चरित्र जांच का विषय है, अदालत के जाल से ढका हुआ है। क्या वह गवाहों को अपने समक्ष उपस्थित होने और उन्हें शपथ दिलाने के लिए मजबूर कर सकता है, क्या उसे प्रक्रिया के कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता है, क्या वह प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है, क्या उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने समक्ष मामलों को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और गुण-दोष के आधार पर देखेगा और व्यक्तिपरक विचारों द्वारा निर्देशित नहीं होगा; दूसरे शब्दों में, क्या यह अर्ध-न्यायिक दृष्टिकोण है? यदि उस ओर से सभी या कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण संतुष्ट हो जाते हैं, तो कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही के रूप में वर्णित किया जा सकता है और ट्रैपिंग के परीक्षण को संतुष्ट कहा जा सकता है। लेकिन ट्रैपिंग के परीक्षण के अलावा, महत्वपूर्ण 219 का एक और परीक्षण

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [के. रामास्वामी, जे.]

टांस यह है कि क्या निकाय या प्राधिकरण था

राज्य और राज्य द्वारा प्रदत्त

यह एक महत्वपूर्ण, यदि निर्णायक नहीं, संकेत होगा कि उक्त निकाय या प्राधिकरण एक न्यायाधिकरण है "।

तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि केंद्रीय राजस्व बोर्ड और

केंद्र सरकार। कला के उद्देश्य के लिए न्यायाधिकरण हैं। 136. भारत बैंक लिमिटेड में, दिल्ली बनाम. भारत बैंक लिमिटेड, दिल्ली, [1950] एस. सी. आर. 495 के कर्मचारी जब औद्योगिक न्यायाधिकरण की इसी तरह की आपत्ति ली गई थी राष्ट्र पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्य कार्य औद्योगिक विवादों पर निर्णय लेना है जिसका तात्पर्य है कि परस्पर विरोधी मामलों के साथ उसके समक्ष दो या दो से अधिक पक्ष होने चाहिए और उसे इस निष्कर्ष पर भी पहुंचना होगा कि विवाद कैसे समाप्त होता है। इसलिए, प्रथम दृष्टया, इस तरह के न्यायाधिकरण को कला के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है। 136. यह भी माना गया कि हालांकि प्रोपियो वीगर में पुरस्कार लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन संबंधित सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर यह अस्तित्व में आ जाता है और

वा

सरकार द्वारा कानून द्वारा निर्धारित तरीके से एक अधिसूचना जारी की गई थी। पुरस्कार को कला के दायरे से बाहर रखना अपने आप में एक निर्धारक कारक नहीं है। 136 संविधान से। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम पी. एन. शर्मा और अन्र. , [1965] 2 एस. सी. आर. 366 सवाल यह था कि क्या सरकार ने श्रम आयोग की सहमति से आदेश पारित किया था।

पंजाब कल्याण अधिकारी भर्ती और शर्तों के तहतसेवा नियम, 1952 कला के अर्थ में एक न्यायाधिकरण है। 136. इस न्यायालय ने पृष्ठ 386 और 387 पर इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" अदालत के सभी या कुछ जालों की उपस्थिति वास्तव में निर्णायक नहीं है। कुछ जाल की उपस्थिति इस प्रश्न के निर्धारण में सहायता कर सकती है कि क्या प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति जो उक्त जाल को लागू करती है, राज्य की न्यायिक शक्ति है या नहीं। हालांकि, मुख्य और बुनियादी परीक्षा यह है कि क्या निर्णय लेने की शक्ति जो एक विशेष प्राधिकरण है

प्रयोग करने के लिए सशक्त, एक कानून द्वारा इसे प्रदान किया गया है और इसे अपने न्यायिक कार्य के निर्वहन में प्रयोग की गई राज्य की अंतर्निहित शक्ति के एक हिस्से के रूप में वर्णित किया जा सकता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. 1 एस सी आर।

यह। इस परीक्षा को लागू करने में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि

शक्ति जो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। आर. 6 (5) के तहत अभ्यास और

आर. 6 (6) राज्य की न्यायिक शक्ति का एक हिस्सा है। यह राज्य सरकार को एक वैधानिक नियम द्वारा प्रदान किया गया है। और इसका प्रयोग दोनों के बीच विवादों के संबंध में किया जा सकता है

भावना, एक लिस; एक पक्ष द्वारा पुष्टि और इनकार हैदूसरे द्वारा, और विवाद में अनिवार्य रूप से अधिकार शामिल हैं

और इसके लिए पक्षों के दायित्व "।

दुर्गा शंकर मेहता बनाम में भी यही अनुपात है। ठाकुर रघुराज सिंह

और ओआरएस।, [1955] 1 एस. सी. आर. 267 और देव सिंह और अन्य। वी. पंजीयक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य।, [1987] 2 एस. सी. आर. 1005 बाद वाले ने तथ्यों पर थोड़ा ध्यान दिया।

इसलिए, यह तय किया गया कानून है कि प्राधिकरण को एक विशेष मामले में लाने के लिए अदालत के सभी पहलुओं को आवश्यक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायाधिकरण लेकिन आवश्यक अभिधारणा यह होनी चाहिए कि यह कानून का सृजन होना चाहिए और राज्य को न्यायाधिकरण को न्यायिक समीक्षा की अपनी अंतर्निहित शक्ति सौंपनी चाहिए; किसी दिए गए मामले में किसी न्यायालय के सभी या कुछ अंश उपस्थित हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। न्यायाधिकरण को निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप पक्षों को उचित अवसर देने के बाद अपने समक्ष पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय लेना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि प्रोपियर्यो वीगर इसे लागू करने योग्य हो। केवल तथ्य यह है कि

आगे के आदेशों के अधीन निर्णय या उसके तहत दर्ज किए गए निष्कर्षों के प्रभाव को दूर नहीं करता है।

समिति कोई सिफारिश करने वाला निकाय नहीं है। यह एक उच्च न्यायिक प्राधिकरण है जो कला से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। 124 (5) संविधान के साथ पढ़ा गया अधिनियम की धारा 3 (2)। उस पर निश्चित आरोप और सेवा तैयार करने पर, यह विद्वान न्यायाधीश को अपना बचाव दायर करने के लिए उचित समय देता है। द.

नियम 8 के तहत समिति को न्यायाधीश की अनुपस्थिति में एकतरफा जांच करने का अधिकार है, जब वह उपस्थित नहीं हुआ था या अनुपस्थित रहने का विकल्प चुना था। न्यायाधीश को नियम 11 के तहत अपने वकील से परामर्श करने और अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव करने का अधिकार भी दिया गया है। जांच के दौरान समिति को सेक द्वारा अधिकार दिया गया था। 5 सिविल संहिता के तहत 'दीवानी मुकदमे की सुनवाई करते समय दीवानी अदालत की शक्तियों' के साथ अधिनियम

प्रक्रिया, 1908, गणना किए गए मामलों के संबंध में, अर्थात्, समन करने के लिए, 221

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [के. रामास्वामी, जे.]

और गवाहों की उपस्थिति और उनकी परीक्षा, शक्ति को लागू करें

खोज और निरीक्षण या उन्हें निर्देश देना, दस्तावेजों को प्रस्तुत करना, शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करना, गवाहों या दस्तावेजों और ऐसे अन्य निर्धारित मामलों की जांच के लिए आयोग जारी करना। सेक के तहत। 4 (1) समिति अनुभाग के तहत नियुक्त न्यायाधीश और अधिवक्ता को उचित अवसर देगी। 3 (9) गवाहों की जाँच करना, जाँच करने का अधिकार, सबूत में साक्ष्य का न्यायनिर्णयन या आरोपों का खंडन करना और बचाव में सुने जाने का अधिकार। नियम 10 (1) के तहत साक्ष्य होना चाहिए

सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार अभिलिखित। का अधिकार गवाहों की जाँच और प्रतिपरीक्षा एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो किसी मुकदमे के समान है।

न्यायाधीश और अधिवक्ता को सुनने के बाद कानूनी रूप से प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार। समिति के पास निर्णय लेने के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं है। "सिद्ध दोषी या दोषी नहीं" के विवाद पर। नियम 6 के संचालन द्वारा समिति, साक्ष्य पर विचार करने और 'उचित संदेह से परे प्रमाण' के मानक को लागू करने पर, यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित या गलत साबित हुई है। अकेले अपराध का पता लगाना राजनीतिक प्रक्रिया के अधीन है। अतः जाँच समिति एक उच्च न्यायिक निकाय या प्राधिकरण है।

इस समस्या को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। में।

अनुच्छेद के तहत किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और प्रमाण। 124 (5) अधिनियम और नियमों के साथ पढ़ा जाता है; संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपेक्षित बहुमत द्वारा समर्थित संबोधन और राष्ट्रपति द्वारा एक न्यायाधीश को हटाना आवश्यक न्यायिक आचरण और उत्साह को पुनर्जीवित करने के लिए एक अनुशासनात्मक उपाय के समान है।

कानून की सर्वोच्चता कि न्यायाधीश भी कानून के अधीन होगा। न्यायाधीश ने एक संवैधानिक पद धारण करता है। अनुच्छेद 124 (5) ने अक्षमता से पीड़ित एक गलती करने वाले न्यायाधीश या न्यायाधीश को हटाने के लिए न्यायिक और राजनीतिक प्रक्रिया का एक समामेलन तैयार किया। समिति द्वारा अध्यक्ष को इस निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत की गई रिपोर्ट कि कथित दुर्व्यवहार साबित हो गया है और न्यायाधीश को साबित दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया है, नई सामग्री का गठन करती है। यह

भारत संघ में न्यायालय बनाम। एच. सी. गोयल, [1964] 4 एस. सी. आर. 718 ने 728 में कहा कि:

" साक्ष्य के साथ जांच रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1992] एस. यू. पी. दर्ज की गई।

1 एस सी आर।

222

उस सामग्री का गठन करता है जिस पर सरकार का अधिकार है करीब से कार्य करने के लिए। यही जाँच का एकमात्र उद्देश्य है।

सक्षम अधिकारी द्वारा आयोजित और वह रिपोर्ट जो उसने

उक्त जाँच के परिणामस्वरूप करता है "।

(जोर दिया गया)

यह आगे पी में आयोजित किया गया था। 729 वह:

" यह सच है कि बर्खास्तगी का आदेश जो पारित किया जा सकता है एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ दुराचार का दोषी पाया गया,

एक प्रशासनिक आदेश के रूप में वर्णित किया जा सकता है; फिर भी,

ऐसे लोक सेवक के खिलाफ की गई कार्यवाही वैधानिक नियम यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वह दोषी है

उसके खिलाफ लगाए गए आरोप अर्ध-प्रकृति के हैं।

न्यायिक कार्यवाही और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि

कार्यवाही जो उसकी बर्खास्तगी का आधार है कोई सबूत नहीं "।

भारत संघ और अन्य में। वी. मोहम्मद. रमजान खान, [1991] 1 एस. सी. सी. 588

दंड की प्रकृति से संबंधित सिफारिशें लगाया गया। 42 वें संशोधन के साथ अपराधी अधिकारी जुड़ा हुआ है।

अनुशासनात्मक जांच के साथ जो साक्ष्य की रिकॉर्डिंग से परे नहीं है और

जाँच अधिकारी की सहायता के लिए मामले के आधार पर प्रस्तुतियाँ

उसे अपने निष्कर्ष पर पहुंचना है। यदि उसके निष्कर्षों को इससे परे रखा जाता है

सजा के बारे में सिफारिश के साथ या उसके बिना जांच,

क्वेंट को इसकी सामग्री को जानने से रोक दिया गया है, हालांकि इस तरह अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उसके खिलाफ सामग्री का उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट यह है कि

प्रतिकूल सामग्री यदि जांच अधिकारी अपराध का निष्कर्ष दर्ज करता है और जहाँ तक अपराधी को दोषी ठहराया जाता है, वहाँ तक सजा का प्रस्ताव करता है। एक अर्धांश में

न्यायिक मामला, यदि अपराधी को ज्ञान से वंचित किया जा रहा है

उसके खिलाफ सामग्री, हालांकि वही सजा देने के लिए उपलब्ध कराई गई थी

अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के मामले में प्राधिकरण, यह नियमों 223 का उल्लंघन है।

एसएमटी। एस. रामास्वामी बनाम यू. ओ. आई. [के. रामास्वामी, जे.]

प्राकृतिक न्याय। इस अदालत ने मजहूरल इस्लाम में अनुपात को मंजूरी दे दी।

हाशमी वी। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य, [1979] 4 एससीसी 537 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1237

कि दूसरे व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसे क्या मिलना है और उसके पास एक होना चाहिए

उस मामले से मिलने का अवसर। हालाँकि, विधानमंडल बाहर कर सकता है

इन सिद्धांतों का संचालन स्पष्ट रूप से या निहित रूप से लेकिन इसके अभाव में

इस तरह के किसी भी बहिष्कार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा।

दुर्व्यवहार या असमर्थता के अपराध का निष्कर्ष, जिसके साथ न्यायाधीश है

से पीड़ित, प्रतिष्ठा के नुकसान के नागरिक परिणामों के साथ दौरा करेंगे

पद की बरामदगी के अलावा सोसायटी। मोहिंदर सिंह गिल और अन्र में।

वी. मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य।, [1978] 2 एससीआर 272

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नागरिक परिणामों से प्रभावित व्यक्ति का अधिकार है -

रिपोर्ट। यह अब तय कानून है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं न्यायपूर्ण और निष्पक्ष प्रक्रिया की संवैधानिक योजना का एक अभिन्न अंग

संविधान के Art.14 के तहत देखा गया।

उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि समिति ऐसा करती है,
 और कोई भी दोषमुक्ति की रिपोर्ट तक पहुँचने या पाने का हकदार नहीं होगा कमिट द्वारा दर्ज किए गए
 दोषी नहीं होने के निष्कर्ष की शुद्धता पर हमला करें

टी. रिपोर्ट की आपूर्ति करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। दूसरी ओर अगर
 समिति या तो सर्वसम्मति से या बहुमत से 'दोषी' का निष्कर्ष निकालती है
 साबित दुर्व्यवहार 'केवल उस हिस्से को प्रत्येक के फर्श पर रखा जाना चाहिए
 " अधिनियम और नियमों के संदर्भ में संसद का सदन
 'दोषी नहीं' के अल्पसंख्यक विचार और हटाने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया
 न्यायाधीश शुरू करेंगे। वह रिपोर्ट विद्वान न्यायाधीश के लिए प्रतिकूल है। द.
 संवैधानिक योजना ने विचार के अभियान पर जोर दिया
 लंबित प्रस्ताव और, यह निस्संदेह किया जाना चाहिए, इसके विस्तार के लिए
 विज्ञापन की प्रभावकारिता में जनता के विश्वास पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करना
 न्याय मंत्रालय। प्रत्येक अधिकार अपने साथ आनुषंगिक उपाय रखता है -
 चोट को ठीक करें। निर्विवाद रूप से और निष्पक्षता में एक तथ्य के रूप में, श्री नरीमन,
 यह स्वीकार किया कि विद्वान न्यायाधीश न्यायिक समीक्षा का हकदार है। का अखाड़ाविवाद यह है कि
 क्या, संसद द्वारा प्रस्ताव लेने से पहले
 राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश पारित करने के बाद या उसके बाद
 अनुच्छेद 124 (4)। जैसा कि चर्चा की शुरुआत से पहले कहा गया था कि वह चरण अदालत की रिपोर्ट
 [1992] का समर्थन करेगा।

1 एस सी आर।

224

यह जाने बिना कि रिपोर्ट की सामग्री क्या है; न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया में साबित दुर्व्यवहार या अन्य
 अवैधताओं के निष्कर्षों के समर्थन में तर्क, क्या किसी पक्ष को कानूनी उपचार से वंचित किया जा सकता है?
 में। क्या ऐसा मामला गैर-मुद्दा नहीं है? सामग्री की आपूर्ति के बिना, कानूनी चोट की नींव, क्या वह
 पर्याप्त और प्रभावी ढंग से अनुरोध कर सकता है, साबित कर सकता है और निष्कर्ष आदि की गलतता का

दुरुपयोग कर सकता है? विद्वान न्यायाधीश संसद के सदन के पटल पर उपचार का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकते हैं।

क्या रिपोर्ट की गैर-आपूर्ति के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है

प्राकृतिक न्याय? क्या यह न्यायिक प्रक्रिया के लिए अभिशाप नहीं है? अल्पसंख्यक सदस्य के 'अपराध' के निष्कर्ष की रिपोर्ट की गोपनीयता न्यायाधीश की रक्षा के लिए है, लेकिन जब अपराध का निष्कर्ष न्यायाधीश पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो क्या गोपनीयता के अनुरोध पर इसे अस्वीकार किया जा सकता है? हो सकता है कि वकील किसी गैर-मुद्दे पर किसी भी विवाद को उजागर कर सकता है। क्या अदालत सभी दलीलों का जवाब देने के लिए बाध्य है? इन परिस्थितियों में, मेरा विचार है कि विद्वान न्यायाधीश रिपोर्ट की एक प्रति की आपूर्ति का हकदार है और समिति एक उच्च अधिकारी है।

वैधानिक रूप से, न्यायालय समिति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए,

विद्वान न्यायाधीश को रिपोर्ट की प्रति प्रदान करने का अनुरोध करें।

अतः आवश्यक निष्कर्ष यह है कि विद्वान न्यायाधीश है -

समिति की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने का हकदार। एकर सङ्गति ई होयत जे विद्वान न्यायाधीशकें निर्णय लेबा आ ओहि पर कार्रवाई करबा पर विचार करबाक लेल समयक आवश्यकता होयत। हालांकि अध्यक्ष की मांग की गई थी

रिट याचिका के प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया जाना, बाद में वह था

हटा दिया गया। इसलिए, संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रिपोर्ट नहीं रखने के अनुरोध के साथ माननीय अध्यक्ष को निर्देश देने का सवाल।

उठती नहीं है। अनिवार्य रूप से समिति से इसे वापस लेने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

उचित समय के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

तदनुसार, मैं रिट याचिका को स्वीकार करता हूँ और पंजीयक को निर्देश देता हूँ

जनरल श्री जस्टिस पी. बी. सावंत को अनुरोध पत्र प्रेषित करेंगे माननीय श्री न्यायमूर्ति वी. को रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने के लिए समिति।

रामास्वामी और इसके समर्पण को रोकने के लिए आगे अनुरोध करने के लिए

पत्र की प्राप्ति की तारीख से उचित समय के लिए रिपोर्ट करें

रजिस्ट्री से अनुरोध। महान्यायवादी से भी अनुरोध किया जाता है कि

लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को इस में पारित आदेश से अवगत कराया। समिति की ओर से और यदि आवश्यक हो तो समिति को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक समय बढ़ाने के लिए:

यू. ओ. आई. [के. रामास्वामी, जे.]

225

समय बिताया। रिट याचिका समझौता-ए है।

बिना किसी लागत के।

आदेश

के संदर्भ में, और के अनुसार

बी.

याचिका का निपटारा किया गया।